चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 17 अगस्त–23 अगस्त 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

प्रधानमंत्री जी घोटाला होने वाला है

भले ही सूरज पश्चिम से उगना शुरू कर दे, देश में सत्ता परिवर्तन हो जाए, प्रधानमंत्री बदल जाएं, रक्षा मंत्री बदल जाएं, लेकिन हमारे देश में कुछ चीजें ऐसी हैं, जो कभी नहीं बदल सकतीं. उनमें से एक है देश के रक्षा सौदों पर हथियार माफिया का नियंत्रण. देश की थल सेना, वायु सेना और नौसेना को अगर कोई भी सामान खरीदना हो, तो उसमें हथियार माफिया का हस्तक्षेप एक ब्रह्मसत्य है. उनके बिना न तो सामान खरीदा जा सकता है और न उसे उपलब्ध कराया जा सकता है. जानकार बताते हैं कि उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि अगर उन्हें हटा दिया जाए, तो रक्षा मंत्रालय विदेशी बाज़ार से एक भी हथियार नहीं खरीद पाएगा. हथियार माफिया को हिंदुस्तान में ऑपरेट करने की खुली छूट मिली हुई है. वे इज्जतदार और हाई प्रोफाइल लोग हैं. देश के हर राजनीतिक दल और ज़िम्मेदार अधिकारियों को उनके बारे में पूरी जानकारी है, बावजूद इसके उन हथियार माफिया का कारोबार बिना किसी रोक-टोक के जारी है. मोदी सरकार के आने के बाद भी वे सक्रिय हैं और रक्षा मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले हर सौदे में उनका हस्तक्षेप है. हथियार माफिया का खेल ऐसा है, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब उनके प्यादे बन जाते हैं. सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हथियार के दलालों का जाल नष्ट कर पाएंगे या फिर उनका यह खेल बदस्तूर चलता रहेगा?

मनीष कुमार

अक्टूबर 2014 में भारत सरकार ने इजराइल से स्पाइक मिसाइल खरीदने का फ़ैसला लिया. रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका की जैवलिन मिसाइल खारिज करके स्पाइक मिसाइल चुनी. सरकार ने 8,365 मिसाइलें और 321 लॉन्चर खरीदने का फ़ैसला लिया. यह डील 3,200 करोड़ रुपये की है. जैवलिन और स्पाइक, दोनों ही घातक एंटी टैंक मिसाइल हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि इस कैटेगरी में जैवलिन दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल है, इसलिए उसकी क़ीमत ज़्यादा है. स्पाइक भी एक कारगर मिसाइल है, लेकिन वह जैवलिन से सस्ती है. उसमें पाकिस्तान और चीन के टैंकों को तबाह करने की पूरी क्षमता है. उसे कंधे पर रखकर चलाया जाता है. ये सारे गुण अमेरिका की जैवलिन मिसाइल में भी हैं. अमेरिका ने जैवलिन मिसाइल बेचने के लिए टेक्नोलॉजी देने और डीआरडीओ के साथ मिलकर भारत में उसे बनाने का भी ऑफर दिया, लेकिन बात नहीं बनी. सरकार का फ़ैसला इजराइल की स्पाइक मिसाइल के पक्ष में हुआ, लेकिन हाल में ही यह ख़बर आई कि स्पाइक डील में बाधा पैदा हो गई है. डील फाइनल होने के सात महीने के बाद अब स्पाइक मिसाइल की क़ीमत को लेकर विवाद हो गया है. इजराइली कंपनी अब ज़्यादा क़ीमत वसूलना चाहती है, जिस पर भारत को ऐतराज है. बताया जाता है कि अपनी कॉमर्शियल बिड में उसने मिसाइल की क़ीमत सीधे दोगुनी कर दी है. साथ ही वह भारत में उसे बनाने और टेक्नोलॉजी देने की क़ीमत अलग से मांग रही है. इसके अलावा हर सप्लाई पर सालाना चार फ़ीसद की बढ़ोत्तरी की मांग है. यही नहीं, उसने क्वालिटी की खराबी या गिरावट की ज़िम्मेदारी लेने से भी इंकार कर दिया है. स्पाइक की जो क़ीमत अब इजराइली कंपनी मांग रही है, उतने में तो अमेरिका की जैवलिन मिसाइल आ सकती है. अमेरिका टेक्नोलॉजी देने और भारत में उसे बनाने के लिए भी तैयार है. इसलिए रक्षा मंत्रालय ने इस सौदे पर आगे बढ़ने से मना कर दिया है और इजराइली कंपनी को फिर से सोच-विचार करने को कहा है. अब सवाल यह है कि सौदे की मंजूरी के सात महीने बाद ऐसा क्या हुआ, जिसकी वजह से स्पाइक मिसाइल की क़ीमत दोगुनी हो गई? क्या हथियार लॉबी के हस्तक्षेप की वजह से उसकी क़ीमत बढ़ गई? हथियारों की खरीद में माफिया कैसे अपना नियंत्रण रखने में सफल होते हैं? क्या अब भारत स्पाइक मिसाइल नहीं लेगा? सेना के पास अत्याधुनिक एंटी टैंक मिसाइल हो, इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? इसे समझने के लिए सेना में खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को समझना ज़रूरी है.

भारत सरकार सेना के लिए जो भी चीज खरीदती है, चाहे वह हथियार हो, कारतूस हो, हवाई जहाज हो, युद्धपोत हो, मिसाइल हो, उसके लिए वह क्वालिटी रिक्वायरमेंट यानी आवश्यक गुणवत्ता जारी करती है. यानी सेना बताती है कि उसे क्या चाहिए, किस उद्देश्य के लिए चाहिए, उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए और कितनी संख्या में चाहिए? उसके बाद हथियार बनाने वाली कंपनियां अपना प्रस्ताव भेजती हैं. समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी चीज हम दूसरे देश से खरीदते हैं, तो विक्रेता देश खरीददार को अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं देता. वह वही चीज देता है, जो उसके यहां पहले इस्तेमाल हो चुकी होती है या फिर जिसका नवीन संस्करण आ चुका हो. या फिर वह चीज, जो ग़रीब देशों के लिए बनाई गई हो, ताकि वे कभी भी उसके (विक्रेता) हथियारों को मैच न कर सकें यानी उसके हथियारों के साथ मुक़ाबला न कर सकें. होना तो यह चाहिए कि अगर हम क़ीमत देने को तैयार हैं, तो हमें अत्याधुनिक और हमारी उपयोगिता के अनुकूल हथियार मिलें. लेकिन हक़ीक़त में ऐसा होता नहीं है. यहीं से हथियार माफिया का खेल शुरू होता है. विडंबना यह है कि देश के अधिकारी ही आवश्यक गुणवत्ता यानी क्वालिटी रिक्वायरमेंट को हल्का कर देते हैं. यह काम सेना और मंत्रालय में बैठे अधिकारी करते हैं. हर जगह ऐसे लोग बैठे हैं, जो गुणवत्ता के मापदंड ऐसे रखते हैं, जो हथियार माफिया के प्रस्ताव से बिल्कुल मिलते-जुलते हों. हथियार के दलाल किसी न किसी की कंपनी के लिए लॉबिंग करते हैं. भारत सरकार को उनके (विदेशी कंपनियों के) हथियार बेचने के लिए वे उनसे काफी पैसे लेते हैं. वे रिपोर्ट बनाने वाले अधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों को पैसे देते हैं, ताकि अधिकारी हथियार की क्वालिटी तब तक गिराते रहें, जब तक वह दलालों के माल से मैच न कर जाए.

भारत में हथियार लॉबी बहुत सक्रिय और संगठित तरीके से काम करती है. उसके आगे सरकार की भी नहीं चलती. वह पैसे के दम पर अपने हिसाब से सौदा तय करती है. ऐसा लगता है, मानो रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए सामान खरीदने के लिए नहीं, बल्कि हथियार के दलालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करता है. भारत में हथियार लॉबी बहुत बड़ी नहीं है. पांच से दस लोगों का एक कॉकस है, गैंग है. उसके सबसे बड़े और किंग पिन का नाम सुधीर चौधरी है, जो इंग्लैंड में रहकर सब कुछ ऑपरेट करता है.

इसके बाद सौदे से संबंधित हथियार-उपकरण अथवा सामान का परीक्षण होता है. उसमें भी गड़बड़ियां होती हैं. बोफोर्स कांड में यही हुआ था. जब तक क्वात्रोची उस डील में नहीं घुसे, तब तक परीक्षण में बोफोर्स पिछड़ रही थी, लेकिन जैसे ही क्वात्रोची उसमें बिचौलिया बने, ट्रायल में बोफोर्स पहली पसंद बन गई. जानकार बताते हैं कि अगर कोई इस क्यूआर(क्वालिटी रिक्वायरमेंट) में फेरबदल करने की कोशिश करता है, तो उसे पूरी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है या फिर उस पर दबाव डाला जाता है. कागज पर तो यह प्रक्रिया बिल्कुल सटीक नज़र आती है, लेकिन हक़ीक़त में यह सारी प्रक्रिया इसलिए होती है, ताकि संबंधित सामान मुहैय्या कराने के लिए आख़िर में सिर्फ़ एक या दो ही कंपनी बचे. यह वह कंपनी होती है, जिसके लिए हथियार माफिया लॉबिंग कर रहा होता है. अब जब एक ही सप्लायर बच जाता है, तो सरकार के पास उससे सौदा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता. रक्षा मंत्रालय की ज़्यादातर खरीद में यही होता है. और, स्पाइक मिसाइल मामले में भी यही हो रहा है.

कहने का मतलब यह कि सेना की जो भी ज़रूरत हो, सरकार कुछ भी खरीदना चाहे, ड्रेस या फिर मिसाइल, आख़िरकार वह सब दलालों के हाथों ही खरीदना पड़ता है. इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि वह हथियार या सामान विश्वस्तरीय है या नहीं. भारतीय सेना के लिए उपयोगी है या नहीं. यही वजह है कि भारतीय सेना को हमेशा घटिया

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सजा-ए-मौत एक सार्थक संवाद ज़रूरी है | P-3

सच का सिपाही मरता रहेगा बिल लटकता रहेगा | P-4

आजम का नया अवतार | P-6

प्रधानमंत्री जी, घोटाला होने वाला है

पृष्ठ 1 का शेष

उपकरण मिलते रहे हैं. एक तरफ़ उसे हथियार विश्वस्तरीय नहीं मिलते, वहीं दूसरी तरफ़ बुलेटप्रूफ जैकेट इतनी भारी दी जाती है, जिसे जवान पहनना नहीं पसंद करते. बर्फीले इलाके में जवानों को दिए जाने वाले जूते ऐसे होते हैं, जिनसे उनके पैर खराब हो जाते हैं. खराब सामान लेने का सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है. मीडिया में भी कई बार ख़बरें आ चुकी हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय में बैठे मंत्री से लेकर अधिकारियों तक की नज़र आज तक इस ओर नहीं गई. धांधली का आलम यह है कि कई बार ऐसा होता है कि जो सामान हम खरीदते हैं, उसका जवाब या उससे बेहतर हथियार चीन या पाकिस्तान के पास पहले से उपलब्ध होता है. हमारे हज़ारों करोड़ रुपये बर्बाद हो जाते हैं. एक उदाहरण देता हूं. बुमार पोलेंड कंपनी से हमने आर्म्ड रिकवरी व्हीकल लिया. यह लैंड माइन क्लियर करता है और रास्ता बनाता है. लेकिन, देश के नक्सलियों और आतंकियों के पास लैंडमाइन बिछाने की वह तकनीक मौजूद है, जिसमें यह काम नहीं करता. इसलिए हमारे ये वाहन बेकार हो गए.

भारत में हथियार लॉबी बहुत सक्रिय और संगठित तरीके से काम करती है. उसके आगे सरकार की भी नहीं चलती. वह पैसे के दम पर अपने हिसाब से सौदा तय करती है. ऐसा लगता है, मानो रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए सामान खरीदने के लिए नहीं, बल्कि हथियार के दलालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करता है. भारत में हथियार लॉबी बहुत बड़ी नहीं है. पांच से दस लोगों का एक कॉकस है, गैंग है. उसके सबसे बड़े और किंग पिन का नाम सुधीर चौधरी है, जो इंग्लैंड में रहकर सब कुछ ऑपरेट करता है. बराक मिसाइल की आपूर्ति में हुए घोटाले में भी उसका नाम आया था, लेकिन सीबीआई ने केस बंद कर दिया. सीबीआई ने कहा कि वह उसके ख़िलाफ़ कोई सुबूत एकत्र नहीं कर सकी. मीडिया भी चौधरी के बारे में नहीं बताता कि उसके पारिवारिक रिश्ते किन–किन पार्टियों के किन–किन नेताओं के साथ हैं. इसके अलावा भी कुछ और नाम हैं, जिनका खुलासा अलग–अलग हथियार सौदों में हुआ है, जिनमें सुरेश नंदा, रवि ऋषि और अभिषेक वर्मा शामिल हैं. उक्त सारे लोग मिल–जुल कर काम करते हैं. उनके साथ सेना एवं रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, विभिन्न पार्टियों के नेता और पत्रकार मिल–जुल कर काम करते हैं. यह एक ऐसा गैंग है, जो हर सौदे पर मुनाफ़ा कमाता है. इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि सरकार किस पार्टी की है और मंत्री कौन है. मजेदार बात यह है कि दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इसे सारे लोग बखूबी जानते हैं.

एक तरफ़ भारतीय सेना की ज़रूरतें हैं और दूसरी तरफ़ हथियार माफिया है, जो भारतीय सेना की हर खरीद-बिक्री में अपनी कमाई का रास्ता निकालने में जुटा हुआ है. इसमें कोई शक नहीं कि आज भारतीय थल, जल और वायु सेना हथियारों के अभाव के जिस संकट से गुज़र रही है, उसकी जड़ में हथियार माफिया है. उसकी वजह से हथियारों के अभाव के साथ-साथ क़दम-क़दम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है. और, इस सबका खामियाजा देश की सेना को उठाना पड़ता है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह खरीद-बिक्री का एक ऐसा तरीका अपनाए, जिसमें हथियार के दलालों का कोई रोल न हो. दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि देश की सुरक्षा के लिए विश्वस्तरीय टेक्नोलॉजी मुहैय्या कराने की हरसंभव कोशिश होनी चाहिए, ताकि भारतीय सेना को अत्याधुनिक हथियार मिल सकें, जिससे दुश्मन थर्राएं.

अब स्पाइक मिसाइल की बात करते हैं. जर्मनी की एक हथियार कंपनी है, राइनमेटल. इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. लेकिन, इस कंपनी की देश की हथियार लॉबी के साथ साठगांठ है. यह उन्हें पैसा देती है. भारत के कई रिटायर सैन्य अधिकारी राइनमेटल कंपनी के कंसलटेंट हैं, उसके एडवाइजरी पैनल में हैं. यह कंपनी भारत में खूब पैसा खर्च करती है. सरकार ने जब एंटी टैंक मिसाइल खरीदने का फ़ैसला किया, तो यह कंपनी सीधे तौर पर इस सौदे में हिस्सा नहीं ले सकती थी. मजेदार बात यह है कि जिस यूरोस्पाइक नामक कंपनी के ज़रिये इस मिसाइल की मार्केटिंग की जाती है, उसमें राइनमेटल कंपनी की 40 फ़ीसद हिस्सेदारी है. कहने का मतलब यह कि तकनीकी तौर पर इसे इजराइल की राफेल कंपनी बनाती है, लेकिन इसे बेचने में राइनमेटल की हिस्सेदारी है. सीधे शब्दों में अगर समझा जाए, तो राइनमेटल खुद इसकी सप्लाई न करके इजराइल की राफेल के ज़रिये सप्लाई कराएगी. राइनमेटल एक हथियार कंपनी है, जिसका पैसा दुनिया की विभिन्न कंपनियों में लगा हुआ है. सरकार को पता लगाना चाहिए कि इजराइल की राफेल कंपनी के साथ राइनमेटल का क्या रिश्ता है? बताया जाता है कि राफेल के 40 फ़ीसद शेयर राइनमेटल के पास हैं. अगर हमें राइनमेटल से ही मिसाइल खरीदनी है, तो यह सौदा बैन हटाकर सीधे उसी से किया जा सकता है. इससे पैसे की बचत हो सकती है.

जब भी कोई हथियार या अन्य सामान खरीदा जाता है, तो सरकार पहले अपनी इच्छा जताती है और फिर अलग–अलग कंपनियों से प्रस्ताव आते हैं. जो प्रस्ताव सही होता है, उसे मंज़ूर कर लिया जाता है. यह सौदा सरकार मेक इन इंडिया के तहत करना चाहती है. रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि राफेल का राइनमेटल से क्या रिश्ता है? अगर राफेल से राइनमेटल का कोई रिश्ता है और उसी कंपनी से मिसाइल खरीदना तय है, तो उसके ब्लैकलिस्ट होने का कोई मतलब नहीं है. सवाल यह है कि रक्षा मंत्रालय ने इस तथ्य की तरफ़ ध्यान क्यों नहीं दिया? किस लॉबी के दबाव में यह फ़ैसला लिया गया? इस फ़ैसले में कौन–कौन लोग शामिल हैं? क्या इस सौदे के लिए दलाली के रूप में पैसे दिए गए? इन सारे सवालों का जवाब सरकार के पास होना चाहिए और उसे देश की जनता को इसके बारे में बताना चाहिए. मजेदार बात यह है कि उक्त सारे फ़ैसले मोदी सरकार बनने के बाद लिए गए हैं. इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस सरकार ने यह फ़ैसला लिया था. यह सौदा मेक इन इंडिया के तहत होना है. मतलब यह कि इसे बनाने का काम भारत में किया जाएगा. तो अब सवाल यह है कि इसे कौन बनाएगा? क्या इजराइल की कंपनी भारत में मिसाइल बनाने की यूनिट लगाएगी या किसी और निजी कंपनी को इसकी इजाजत दी जाएगी?

नोट करने वाली बात यह है कि भारत सरकार की अपनी एक कंपनी है, जहां पहले से मिसाइल बनाई जा रही है. इसका नाम है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड. वह पिछले कई सालों से मिसाइल बनाने का काम सफलता से कर रही है. अगर भारत में ही स्पाइक मिसाइल बननी है, तो उसे भारत डायनामिक्स के ज़रिये बनाया जा सकता है. उसके पास अनुभवी लोग हैं, टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है. भारत डायनामिक्स के पास मिसाइल बनाने का पूरा सेटअप है और सबसे बड़ी बात यह कि वह सरकारी है. मिसाइल के किसी दूसरे देश या संगठन को बेचने का ख़तरा नहीं है. क्या बन रहा है और कितनी संख्या में बनाया जा रहा है, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में रहेगा. यह सस्ता भी पड़ेगा. लेकिन, हैरानी की बात यह है कि भारत डायनामिक्स के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय ने ग़ौर भी नहीं किया. उसकी जगह रक्षा मंत्रालय ने बाबा कल्याणी नामक एक छोटी सी कंपनी को हरी झंडी दे दी. इजराइल की राफेल कंपनी अब बाबा कल्याणी के साथ ज्वाइंट वेंचर में भारत में स्पाइक मिसाइल बनाएगी. फिर वही सवाल कि इस कंपनी पर रक्षा मंत्रालय क्यों मेहरबान हुआ? इस कंपनी का भारत की हथियार लॉबी से क्या रिश्ता है? क्या मोदी सरकार हथियार के दलालों को हथियार निर्माता बनने में मदद कर रही है? यह सवाल इसलिए भी उठाना ज़रूरी है, क्योंकि इस कंपनी के पास मिसाइल बनाने का न तो अनुभव है, न उसके पास लोग हैं, न उसके पास टेक्नोलॉजी है और न भारत में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है. मतलब यह कि बाबा कल्याणी को सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में तरह–तरह की मदद करेगी. भारत में कंपनी स्थापित करने में जो खर्च आएगा, वह भी मिसाइल की क़ीमत में जुड़ेगा. कोई भी कंपनी अपना नुकसान करके मेक इन इंडिया में क्यों इंवेस्ट करेगी? यही वजह है कि स्पाइक मिसाइल की क़ीमत दोगुनी हो गई और नई–नई शर्तें सामने आ गईं. अगर उसकी बातें मान ली गईं, तो शायद सरकार जवाब देने लायक नहीं बचेगी.

जानकार बताते हैं कि भारत डायनामिक्स के ज़रिये मिसाइल बनाने में दलालों को नुक़सान होगा. चूंकि वह एक सरकारी कंपनी है और उसमें एक–एक पैसे का हिसाब और ऑडिटिंग होती है, इसलिए वहां घोटाला करना नामुमकिन है. सरकारी कंपनी दलाली के नाम पर पैसे नहीं बांट सकती. लेकिन, यदि किसी निजी कंपनी के ज़रिये यह सौदा होता है, तो दलालों के लिए रास्ता खुल जाता है. दलाली के नाम पर पैसे की बंदरबांट हो सकती है. बाबा कल्याणी को अगर मिसाइल बनाने की अनुमति दी जाती है, तो हथियार लॉबी को कई फ़ायदे हैं. कंपनी लगाने में वह अपनी ब्लैक मनी खपा सकती है. अधिकारियों को उनका हिस्सा मिल जाएगा और निजी कंपनी का भी विस्तार हो जाएगा. अब सवाल है कि क्या यह फ़ैसला जानबूझ कर लिया गया, ताकि दलाली के पैसे की बंदरबांट हो सके या फिर कोई और तर्क है? इसका खुलासा सरकार को सार्वजनिक रूप से करना चाहिए. अगर भारत को स्पाइक मिसाइल ही चाहिए, तो उसके लिए सबसे सीधा रास्ता यह है कि राइनमेटल को ब्लैकलिस्ट से हटाकर भारत डायनामिक्स के साथ मिलकर कम क़ीमत में मिसाइल खरीदी और बनाई जा सकती है. दलालों को रास्ते से आसानी से हटाया जा सकता है. इससे हम कम क़ीमत में मिसाइल बनाने में सफल हो सकते थे, लेकिन रक्षा मंत्रालय राइनमेटल से सीधे मिसाइल न खरीद कर उसी की एक कंपनी राफेल से सौदा कर रहा है और बाबा कल्याणी के साथ मिलकर भारत में मिसाइल बनाने के साधन दे रहा है, मदद कर रहा है. इस फ़ैसले ने दलालों और बिचौलियों के लिए रास्ता खोल दिया है. जितना पैसा दलाली में खर्च होगा, वह सब मिसाइल की क़ीमत में जुड़ जाएगा. इसलिए इस फ़ैसले से मिसाइल की क़ीमत भी ज़्यादा हो जाएगी.

एक तरफ़ भारतीय सेना की ज़रूरतें हैं और दूसरी तरफ़ हथियार माफिया है, जो भारतीय सेना की हर खरीद–बिक्री में अपनी कमाई का रास्ता निकालने में जुटा हुआ है. इसमें कोई शक नहीं कि आज भारतीय थल, जल और वायु सेना हथियारों के अभाव के जिस संकट से गुज़र रही है, उसकी जड़ में हथियार माफिया है. उसकी वजह से हथियारों के अभाव के साथ–साथ क़दम–क़दम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है. और, इस सबका खामियाजा देश की सेना को उठाना पड़ता है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह खरीद–बिक्री का एक ऐसा तरीका अपनाए, जिसमें हथियार के दलालों का कोई रोल न हो. दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि देश की सुरक्षा के लिए विश्वस्तरीय टेक्नोलॉजी मुहैय्या कराने की हरसंभव कोशिश होनी चाहिए, ताकि भारतीय सेना को अत्याधुनिक हथियार मिल सकें, जिससे दुश्मन थर्राएं. हमारे जवानों के लिए अत्याधुनिक गैजेट्स, ड्रेस और उत्तम भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उनका हौसला बुलंद रहे. यह सब तब तक नहीं हो सकता, जब तक भारतीय सेना की खरीद–बिक्री में हथियार माफिया का हस्तक्षेप रहेगा. रक्षा मंत्रालय पर हथियार माफिया का जाल ऐसा फैला हुआ है कि कई सरकारों ने उसके सामने घुटने टेक दिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री को हर सौदे पर नज़र रखने की ज़रूरत है. जबसे नई सरकार आई है, तबसे जितने भी फ़ैसले हुए हैं और उन्हें किस तरह लागू किया जा रहा है, इस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है. क्योंकि, जरा–सी चूक सरकार का दामन दागदार कर देगी. किसी को पता भी नहीं चलेगा और प्रधानमंत्री जी की नज़रों के सामने घोटाला हो जाएगा. ■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 24
दिल्ली, 17 अगस्त–23 अगस्त 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोनः 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय	0120–6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022–42296060
	+91–8451050786
	+91–9266627379
फैक्स न.	0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

सजा–ए–मौत

एक सार्थक संवाद ज़रूरी है

राजीव रंजन

महात्मा गांधी ने कहा था कि आंख के बदले आंख निकाल लेने का नतीजा होगा कि एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी. ऐसा माना जाता है कि मौत की सजा का डर लोगों को अपराध करने से रोकता है, पर आंकड़े ऐसा साबित नहीं करते. जिन देशों में मृत्युदंड का प्रावधान ख़त्म हुआ, वहां अपराध बढ़े नहीं और जिन देशों में मृत्युदंड लागू है, वहां अपराध कम नहीं हुए. उदाहरण के तौर पर विश्व में सबसे ज्यादा फांसी चीन में दी जाती है, जबकि अमेरिका फांसी देने वाले देशों में पांचवें स्थान पर है. फिर भी चीन में हिंसात्मक अपराध या मर्डर अमेरिका से तीन प्रतिशत ज्यादा है. फांसी देने वाले देशों में सऊदी अरब तीसरे स्थान पर है, लेकिन अगर सऊदी अरब और अमेरिका के अपराध में तुलना करें तो सऊदी अरब में अमेरिका की तुलना में 70 प्रतिशत क्राइम का डर लोगों में ज्यादा है. सवाल यह उठता है कि अगर फांसी से ही अपराध रोका जा सकता है, तो जिन देशों में फांसी ज्यादा होती है, उन देशों में कम फांसी देने वाले देशों की तुलना में अपराध ज्यादा क्यों है? मृत्युदंड का विरोध करने का अर्थ अपराधी के साथ नरमी से पेश आना नहीं. यह फ़ैसला तो दिया ही जा सकता है कि फलां अपराधी को पूरी ज़िंदगी के लिए सश्रम कारावास मिलना चाहिए. सजा का लक्ष्य अपराध को ख़त्म करना और समाज को ज़्यादा सुरक्षित बनाना होना चाहिए. क़ानून का सम्मान उसके समक्ष बराबरी और सभी की भागीदारी से ही संभव है. किसी भी समाज में मृत्युदंड का प्रावधान होना चाहिए या नहीं, यह हमेशा से विवाद और बहस का विषय रहा है. समाज के उदय काल में मृत्युदंड का सरोकार अपराध से न होकर प्रभुता स्थापित करने की मंशा से अधिक था. यही कारण है कि मृत्युदंड का इस्तेमाल किसी भी समाज या समुदाय के भयादोहन के लिए अधिक हुआ. सजा के इस क्रूरतम रूप के आलोक में समय के साथ समाज में एक ऐसा वर्ग तैयार होता गया, जो आज मृत्युदंड समाप्त करने की वकालत कर रहा है. इस वर्ग का मानना है कि फांसी या मृत्युदंड मानवीय मूल्यों के ख़िलाफ़ है. मुंबई बमकांड के अभियुक्त याकूब की फांसी के बाद भारत में सजा–ए–मौत को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है. कई लोगों ने उसे फांसी की आलोचना करते हुए उसकी सजा उम्रकैद में बदलने की मांग की थी. यह बात और है कि अंतत: उसे फांसी दे दी गई. संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों में से अब सिर्फ़ 40 देशों में ही मृत्युदंड का प्रावधान है. 140 देशों में तो इसे पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है और बाकी में पिछले 10 वर्षों से किसी को सजा–ए–मौत नहीं दी गई. भारत, अमेरिका एवं चीन उन देशों में शामिल हैं, जहां अभी भी मौत की सजा दी जाती है. यूरोपीय संघ ने यह सजा ख़त्म कर दी है. जिन देशों में फांसी की सजा नहीं है, वहां अपराध का ग्राफ फांसी वाले देशों से कम है. ऐसे देशों से सीख ली जा सकती है कि फांसी के फंदे पर लटकाए बिना अपराधियों से कैसे निबटा जाता है. विद्वानों का मत है कि फांसी कोई सजा ही नहीं है. फांसी अपराधी को ख़त्म कर देती है. वहीं कुछ लोगों का मत है कि फांसी से दूसरे अपराधियों में भय पैदा होता है और इस तरह अपराध में कमी आती है. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी फांसी की सजा का विरोधी है.

वर्ष 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सजा–ए–मौत सिर्फ़ दुर्लभतम मामलों में दी जानी चाहिए. हालांकि, ज़मीनी हक़ीक़त पर हमें विचार करना होगा. 2004 से लेकर 2014 तक की अवधि में निचली अदालतों ने 5,454 मामलों में मृत्युदंड की सजा सुनाई. उच्चतर अदालतों ने इनमें से सिर्फ़ 1,303 मामलों में मृत्युदंड की पुष्टि की और इस पूरी अवधि में सिर्फ़ तीन लोगों को फांसी की सजा दी गई. कसाब एवं अफजल गुरु से पहले कोलकाता के धनंजय चटर्जी को फांसी दी गई थी. चर्चित निठारी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली को सजा–ए–मौत सुनाई गई, पर आख़िर में इस वर्ष जनवरी में उसकी सजा उम्रकैद में तब्दील कर दी गई. क्या देश की निचली अदालतें मृत्युदंड के प्रावधान का किसी तरह से दुरुपयोग कर रही हैं? क्या दुर्लभतम शब्द विभिन्न स्तर पर अदालतों ने खुद ईजाद किया है? हाल में 14 प्रतिष्ठित पूर्व न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया था कि कम से कम तेरह मामलों में सजा–ए–मौत सुनाया जाना उचित नहीं था और उनमें से दो अभियुक्तों को तो फांसी पर लटकाया भी जा चुका. इसका सीधा अर्थ यही है कि ऐसे मामलों में न सिर्फ़ निचली, बल्कि उच्चतर और सर्वोच्च अदालत भी चूक कर जाती है.

मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, 2014 में भारत सबसे ज़्यादा मौत की सजा सुनाने वाले दस देशों की सूची में शामिल था. आधुनिक समाज में मौत की सजा के लिए कोई जगह न होने के कई कारण हैं. एक तो इसलिए कि इसका इस्तेमाल चीन, उत्तरी कोरिया, ईरान एवं सऊदी अरब जैसे देशों की निरंकुश सरकारें करती हैं. 2013 में ईरान ने 369 और सऊदी अरब ने 79 लोगों को मौत के घाट उतारा. चीन तो हर साल दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को फांसी देने वाला देश है. इन देशों में फांसी देने के पीछे हुकूमत का मुख्य उद्देश्य आबादी को डराना, भ्रष्ट समर्थकों को अनुशासित और विरोधियों का मुंह बंद करना होता है. मौत की सजा के पक्ष में एक दलील यह है कि इससे अपराधों पर अंकुश लगेगा, लेकिन बार–बार पुष्टि हुई है कि मौत की सजा का प्रावधान अपराध रोकने में कामयाब नहीं रहा. यदि अपराधी का जेल में पुनर्वास हो गया हो, तो उसे मारना और भी बेतुका है. बहुत से मामलों में मौत की सजा पाए लोग जेल में सुधर जाते हैं, अपने अपराधों के लिए माफी चाहते हैं, पढ़ाई करते हैं, किताबें लिखते हैं. जो लोग पश्चाताप नहीं करते, उनके मामलों में भी सुबूत हैं कि समाज को उनसे बचाने का खर्च जेल में कम है. सालों तक चलने वाली क़ानूनी लड़ाई पर ज़्यादा खर्च होता है. यह रकम पीड़ितों के पुनर्वास पर खर्च की जानी चाहिए. फांसी की सजा को लेकर बहस का जो सार निकल कर सामने आ रहा है, वह यह है कि किसी भी सभ्य समाज में मौत की सजा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह एक कलंक के समान है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मुंबई बमकांड के अभियुक्त याकूब की फांसी के बाद भारत में सजा–ए–मौत को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है. कई लोगों ने उसे फांसी की आलोचना करते हुए उसकी सजा उम्रकैद में बदलने की मांग की थी. यह बात और है कि अंतत: उसे फांसी दे दी गई. संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों में से अब सिर्फ़ 40 देशों में ही मृत्युदंड का प्रावधान है. 140 देशों में तो इसे पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है और बाकी में पिछले 10 वर्षों से किसी को सजा–ए–मौत नहीं दी गई.

फांसी देने में अव्वल देश

मौत की सजा देने वाले देशों में चीन पहले नंबर पर है. चीन में दुनिया भर की कुल फांसी से ज़्यादा फांसियां दी गईं. 2013–14 में ईरान मौत की सजा देने के मामले में दूसरे नंबर पर है, जहां औपचारिक रूप से 289 लोगों को फांसी दी गई, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, अनौपचारिक रूप 454 लोगों को फांसी हुई. अपराध के लिए मौत की सजा देने के मामले में सऊदी अरब तीसरे नंबर पर है, जहां पिछले साल विभिन्न आरोपों में 90 लोगों को फांसी दी गई. मध्य–पूर्व का देश इराक सजा–ए–मौत देने के मामले में चौथे नंबर पर है, जहां 61 लोगों को फांसी दी गई. दुनिया का सबसे अहम लोकतांत्रिक देश अमेरिका मौत की सजा देने के मामले में पांचवें स्थान पर है, जहां 2014 में 35 लोगों को विभिन्न तरीकों से मृत्युदंड दिया गया. ■

केंद्र की बेरुखी से बिहार आहत है

सुकांत

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना संभव नहीं है, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद साफ़ कर चुके हैं. नवगठित नीति आयोग ने भी तय कर दिया है कि अब किसी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा. लेकिन, इस ग़रीब और पिछड़े राज्य को विकास के राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए कोई विशेष आर्थिक सहायता (पैकेज) हाल–फिलहाल में दी जाएगी, ऐसा भी नहीं लगता. लोकसभा में योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सांसद पप्पू यादव के एक सवाल के जवाब में बताया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा. हां, विशेष आर्थिक सहायता (पैकेज) देने पर विचार किया जा सकता है. उनके जवाब से यह साफ़ नहीं हुआ कि बिहार को विशेष पैकेज देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है या नहीं. लगता है, बिहार को विशेष मदद देने का कोई प्रस्ताव केंद्र के पास विचाराधीन नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता, तो चुनाव के मौक़े पर केंद्र की एनडीए सरकार खामोश न रहती. वह राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसकी जानकारी बिहार की जनता को ज़रूर देती. बिहार को लेकर केंद्र का यह रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के बिहारी नेताओं द्वारा पिछले डेढ़ साल दिए जा रहे आश्वासनों के विपरीत है. गत संसदीय चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी और एनडीए के सभी बड़े नेता बिहार को विशेष दर्जा या विशेष पैकेज देने का निरंतर आश्वासन देते रहे. कहा गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने पर बिहार को पचास हज़ार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया जाएगा. 26 मई, 2014 को सरकार बनने के बाद भी आश्वासनों का सिलसिला जारी रहा.

विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए मुजफ्फरपुर में बीती 25 जुलाई को आयोजित भाजपा की पहली परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री ने साफ़ संकेत दिया कि फिलहाल बिहार को केंद्र से कुछ विशेष नहीं मिलने जा रहा. मोदी ने दो बातें कहीं. पहली यह कि बिहार को पचास हज़ार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की बात कौन करे, उनके पास उससे काफी बड़ा प्रस्ताव है, लेकिन संसद सत्र ने उनकी ज़ुबान पर ताला लगा दिया है. संसद सत्र समाप्त होने के बाद वह बिहार के लिए तैयार विशेष पैकेज की जानकारी देंगे. दूसरी बात यह कि केंद्र सरकार ने बिहार में निवेश पर पंद्रह प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि और पंद्रह प्रतिशत की डिप्रेशिएशन छूट देने का फ़ैसला किया, लेकिन यह नहीं बताया कि इसे कब से लागू होना है. उधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक पैकेज न देने का मामला वह जनता के बीच ले जाएंगे. वहीं केंद्र की इस बिहार नीति को लेकर भाजपा (एनडीए) के बिहारी नेता असमंजस में हैं कि प्रधानमंत्री पद के तत्कालीन घोषित उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के वादों की भद पिट जाने के बावजूद वे उनका बचाव कैसे करें.

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद यानी 2006 से ही सक्रिय हैं. इस संबंध में उनकी सरकार की पहल पर राज्य विधान मंडल में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था. तत्कालीन प्रधानमंत्री से एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भी मिला था. 2009 के संसदीय चुनाव के बाद उन्होंने इस मसले पर अपनी पार्टी को सड़क पर उतार दिया था. विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर क़रीब डेढ़ करोड़ बिहारियों के हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन केंद्र को सौंपा गया था. विशेष राज्य के दर्जे की मांग को उन्होंने 2010 के विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बनाया. हालांकि, उस समय वह एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री थे. नीतीश के इस राजनीतिक आचरण को देखते हुए भाजपा ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी. राज्य में एनडीए के विघटन के बाद एक बार फिर यह मामला गरमाया और भारत सरकार के तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन (रिजर्व बैंक के गवर्नर) की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई, जिसने अपनी रिपोर्ट में बिहार को अति पिछड़े राज्य की श्रेणी में रखा. कमेटी ने बिहार को विकसित राज्य के स्तर तक लाने के लिए विशेष आर्थिक सहायता देने की सिफारिश भी की थी. केंद्र की मौजूदा एनडीए सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए विशेष पहल की बात बजट में की थी.

ग़ौरतलब है कि बिहार की आधी से ज़्यादा आबादी ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है. देश में ग़रीबी रेखा से नीचे की आबादी का औसत 29.8 फ़ीसद है, जबकि बिहार में 53.5 फ़ीसद. बिहार में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 13,632 रुपये है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 35,993 रुपये है. राज्य विभाजन के बाद बिहार उद्योग विहीन हो गया. इस राज्य में अभी मात्र 0.4 फ़ीसद मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं. बिहार पर पानी की गहरी मार सैकड़ों वर्षों से पड़ती रही है. बाढ़ इस राज्य की वार्षिक त्रासदी है. हाल के कुछ वर्षों से मौसम की मार के कारण सूखा भी इस राज्य की नियति बनता जा रहा है. पर्यावरण चक्र में बदलाव के कारण खेती गंभीर रूप से प्रभावित होती रही है. बिहार लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है, इससे कई परेशानियां हैं, लेकिन केंद्र इस सबसे बेख़बर है. विशेष दर्जे के कई लाभ हैं. मसलन, राज्य को केंद्रीय अनुदान की रकम बढ़ जाती है, उद्योग लगाने में विभिन्न करों में छूट मिलती है, केंद्रीय योजनाओं पर 90 फ़ीसद तक केंद्र का अंश हो जाता है और कर्ज राहत योजना से भी राज्य लाभांवित होता है. चूंकि विशेष राज्य का दर्जा देने की व्यवस्था फिलहाल समाप्त कर दी गई है, इसलिए विशेष आर्थिक पैकेज पर जोर देने की ज़रूरत है. मनरेगा और इंदिरा आवास जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों की धनराशि में निरंतर कटौती की जा रही है. मनरेगा की क़रीब एक तिहाई धनराशि कम हो गई है, वहीं इंदिरा आवास योजना में भी 20 फ़ीसद से अधिक कटौती हुई है.

भाजपा का कहना है कि चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी में क़रीब चार हज़ार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, लिहाजा राज्यों की योजना या उसके धन या उसकी हिस्सेदारी में कोई कटौती नहीं की गई है. लेकिन, भाजपा और एनडीए के ये सारे तर्क बचाव के हैं. बिहार से जो वादे किए गए थे, आज डेढ़ साल बाद भी उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ. बिहार के बौद्धिक समाज का बड़ा तबका मानता है कि नीति आयोग के निर्णय के बाद किसी राज्य को विशेष दर्जा देना संभव नहीं है, लेकिन आर्थिक विकास और मानव विकास सूचकांक में राष्ट्रीय स्तर तक बिहार को ले जाने के लिए विशेष आर्थिक सहायता ज़रूरी है, उसके बगैर बिहार का राष्ट्रीय औसत के अनुरूप विकास कठिन है. ■

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा का कहना है कि चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी में क़रीब चार हज़ार करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, लिहाजा राज्यों की योजना या उसके धन या उसकी हिस्सेदारी में कोई कटौती नहीं की गई है. लेकिन, भाजपा और एनडीए के ये सारे तर्क बचाव के हैं. बिहार से जो वादे किए गए थे, आज डेढ़ साल बाद भी उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ.

लोकपाल और व्हिसल ब्लोअर्स को भूल गई सरकार

सच का सिपाही मरता रहेगा, बिल लटकता रहेगा

राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर 9 मई, 2014 को हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद सरकार ने अब तक इसे क़ानून के तौर पर लागू नहीं किया है. सवाल यह है कि अब तक इस बहु-प्रतीक्षित क़ानून को (पारित किए जाने के बाद भी) लागू क्यों नहीं किया गया, जबकि पिछले कई सालों से देश भर के सामाजिक कार्यकर्ता सरकार से मांग करते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बिगुल बजाने वाले लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए? इसके उलट, अब यह क़ानून लागू करने की जगह एक बार फिर मौजूदा केंद्र सरकार इसमें संशोधन की बात कह रही है. केंद्र की एनडीए सरकर ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे से बाहर रखने के लिए क़ानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा है.

शशि शेखर

व्यापम की धुंध अभी भी माहौल में व्याप्त है. सुशासन का दावा करने वाली मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह खुद को भले ही व्हिसल ब्लोअर बताते हों, लेकिन व्यापमं घोटाले के व्हिसल ब्लोअर्स का जो हाल हुआ है और जिस तरीके से अभी भी कई व्हिसल ब्लोअर्स गृह राज्य मध्य प्रदेश छोड़कर दिल्ली में रहने को मजबूर हैं, उससे एक अलग ही कहानी सामने आती है. शिवराज सरकार यह मामला उजागर करने वाले प्रमुख व्हिसिल ब्लोअर्स को पुख्ता सुरक्षा भी मुहैया नहीं करा पा रही है. आएदिन उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलती रहती हैं. सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी में उन पर हमले हो जाते हैं, लेकिन सरकार में उनकी सुरक्षा को लेकर कोई आवाज़ नहीं उठती. व्यापमं मामले के तीन प्रमुख व्हिसल ब्लोअर्स आशीष चतुर्वेदी, डॉ. आनंद राय एवं प्रशांत पांडेय को कोर्ट के आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन तीनों में से कोई भी मिल रही सुरक्षा से संतुष्ट नहीं है.

इन व्हिसल ब्लोअर्स के अलावा आप चाहें, तो अशोक खेमका, दुर्गा शक्ति नागपाल एवं संजीव चतुर्वेदी जैसे अधिकारियों के नाम भी इस सूची में शामिल कर सकते हैं. एक और गंभीर उदाहरण है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इंजीनियर सत्येंद्र दुबे का. कई साल पहले उन्हें बिहार के गया सर्किट हाउस में गोली मार दी गई थी. उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सीधे पत्र लिखकर एनएचएआई में भ्रष्टाचार के संबंध में जानकारी दी थी, लेकिन पीएमओ ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की. उल्टे यह ख़बर भी आई थी कि पीएमओ से ही इस शिकायत की जानकारी लीक की गई थी. सूचना का अधिकार क़ानून लागू होने के बाद अब तक सैकड़ों आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है.

ऐसे में याद आती है, व्हिसल ब्लोअर्स एक्ट की. 2010 में यूपीए-2 सरकार पब्लिक इंटरेस्ट डिसक्लोजर एंड प्रोटेक्शन फॉर पर्सन्स मेकिंग डिसक्लोजर बिल लाई थी. इसे ही व्हिसल ब्लोअर बिल-2010 कहा गया. इस बिल में सरकारी धन के दुरुपयोग और सरकारी संस्थाओं में हो रहे घोटालों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को व्हिसल ब्लोअर माना गया यानी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बिगुल बजाने वाला. इस बिल में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को अतिरिक्त अधिकार दिए गए. सीवीसी को दीवानी अदालत जैसी शक्तियां भी देने की बात कही गई. सीवीसी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई रोक सकता है. भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखने की ज़िम्मेदारी सीवीसी की है. अगर पहचान उजागर होती है, तो ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ शिकायत भी की जा सकेगी. इस बिल के दायरे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं. यह बिल 2011 में ही लोकसभा से पारित हो गया था. राज्यसभा में भाजपा ने कुछ संशोधन पेश किए और अंतत: संसद ने इस बिल को पारित कर दिया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी.

राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर 9 मई, 2014 को हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद सरकार ने अब तक इसे क़ानून के तौर पर लागू नहीं किया है. सवाल यह है कि अब तक इस बहु-प्रतीक्षित क़ानून को (पारित किए जाने के बाद भी) लागू क्यों नहीं किया गया, जबकि पिछले कई सालों से देश भर के सामाजिक कार्यकर्ता सरकार से मांग करते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बिगुल बजाने वाले लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए? इसके उलट, अब यह क़ानून लागू करने की जगह एक बार फिर मौजूदा केंद्र सरकार इसमें संशोधन की बात कह रही है. केंद्र की एनडीए सरकर ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे से बाहर रखने के लिए क़ानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. देखना दिलचस्प होगा कि व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट में अब किस तरह के संशोधन होते हैं और उनके क्या मायने निकल कर सामने आते हैं.

बात अगर भ्रष्टाचार की हो और लोकपाल की चर्चा न हो, यह संभव नहीं है. दो वर्षों के आंदोलन के बाद यूपीए सरकार ने लोकपाल बिल पारित कर दिया. बिल को पारित हुए एक साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन आज तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी है. लोकपाल की मांग को समर्थन देने वाली भाजपा को केंद्र की सत्ता में आए हुए एक साल से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अब तक यह क़ानून लागू नहीं हो सका है यानी अभी तक यह सरकार एक अदद लोकपाल की तलाश पूरी नहीं कर सकी. दूसरी तरफ़ यह भी ख़बर है कि लोकपाल बिल की जांच करने वाली संसदीय समिति ने मानसून सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट जमा न कराने की बात कही थी. कांग्रेस के सांसद ईएम सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता वाली कार्मिक, जन शिकायतों, क़ानून एवं न्याय पर बनी 31 सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति लोकपाल, लोकायुक्तों और अन्य संबंधित क़ानून (संशोधन) विधेयक-2014 की जांच कर रही है. इस समिति ने कहा है कि उसके पास ऐसे कई महत्वपूर्ण एवं जटिल मुद्दे हैं, जिन पर चर्चा किए जाने की ज़रूरत है.

सवाल है कि क्या यह बिल बिना चर्चा के बना था? क्या इसे पास करते वक्त भाजपा ने कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया था? इस क़ानून के तहत लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्तों की स्थापना की जानी है, ताकि अधिकारियों के ख़िलाफ़ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा सके. लेकिन, क़ानून बनने के बाद भी अब तक इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका है. क्या इस तरह भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ होने वाली लड़ाई को कमजोर नहीं बनाया जा रहा है? ऐसे में सच के सिपाहियों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की नीति और नीयत पर संदेह होना लाजिमी है. आख़िर कब तक सच के सिपाही मरते रहेंगे और सरकार अपना राजनीतिक नफा-नुक़सान देखते हुए महत्वपूर्ण क़ानूनों को सत्ता के अंधेरे गलियारों में भटकाती रहेगी, लटकाती रहेगी?■

shashishekhar@gmail.com

योग पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सख्त

विरोध और समर्थन की राजनीति पर बहस जारी

योग पर मौलाना वली रहमानी द्वारा सख्त रुख अपनाने के विरोध में दो और मज़बूत आवाज़ें उठी हैं. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शिक्षक डॉ. राशिद शाज़ एवं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के पूर्व सचिव डॉ. तसलीम अहमद रहमानी मौलाना वली की गतिविधियों को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं. दोनों का मानना है कि यदि योग जैसे मुद्दे पर न्यायालय के बजाय सड़कों पर फ़ैसला किया जाएगा, तो मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसका ग़लत प्रभाव पड़ सकता है. इस संबंध में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है. दूसरी तरफ, जमात-ए-इस्लामी हिंद ने बोर्ड के फ़ैसले का समर्थन किया है.

खुर्शीद आलम

योग न करने को लेकर मुस्लिम समाज में जो राजनीति शुरू हुई थी, वह सरकार द्वारा योग को स्वैच्छिक करने की घोषणा के बाद भी थमती नज़र नहीं आ रही है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा सरकार से सीधे तौर पर टकराने की तैयारियां जारी हैं. जहां तक योग को लेकर किसी तरह का जनांदोलन चलाने का सवाल है, तो सूत्रों के अनुसार, बोर्ड के कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया था, लेकिन मौलाना वली रहमानी के समर्थकों ने इसे नकारते हुए सख्त रवैये को बेहतर और अपनी तरफ़ देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयुक्त समझा है. उनका मकसद यह संदेश देना है कि वे सफल हो गए हैं. लेकिन, देश का संजीदा वर्ग बोर्ड के वर्तमान दृष्टिकोण को देशहित में नहीं मानता. उसे लगता है कि हिंदुत्ववादी तत्व इसका लाभ उठा सकते हैं, जैसा कि उनकी ओर से जारी विभिन्न वक्तव्यों से भलीभांति प्रतीत होता है. ग़ौरतलब है कि बोर्ड के इस क़दम को एक-दो उर्दू अख़बारों को छोड़कर शेष उर्दू मीडिया कोई तवज्जो नहीं दे रहा है. योग को लेकर एक अन्य महत्वपूर्ण मुस्लिम संगठन जमीअते उलेमा हिंद का जो दृष्टिकोण है, वह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दृष्टिकोण से अलग है. जमीअते उलेमा हिंद को सूर्य-नमस्कार के बिना योग करने में कोई ऐतराज नहीं है. जमीअत के महासचिव मौलाना महमूद मदनी तो एक टीवी चैनल से बात करते हुए यहां तक कह चुके हैं कि वह खुद सूर्य-नमस्कार के साथ योग करते हैं. फ़र्क़ केवल इतना है कि वह ऐसा सूरज की तरफ़ मुंह करके नहीं करते हैं. उनके मुताबिक, सूर्य-नमस्कार एक आसन है. जमीअत के इस विपरीत दृष्टिकोण पर उर्दू अख़बार मौन हैं. मालूम हो कि योग पर मौलाना वली रहमानी द्वारा सख्त रुख अपनाने के विरोध में दो और मज़बूत आवाज़ें उठी हैं. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शिक्षक डॉ. राशिद शाज़ एवं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के पूर्व सचिव डॉ. तसलीम अहमद रहमानी मौलाना वली की गतिविधियों को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं. दोनों का मानना है कि यदि योग जैसे मुद्दे पर न्यायालय के बजाय सड़कों पर फ़ैसला किया जाएगा, तो मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसका ग़लत प्रभाव पड़ सकता है. इस संबंध में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का विशेष रूप से उल्लेख किया जा रहा है. दूसरी तरफ, जमात-ए-इस्लामी हिंद ने बोर्ड के फ़ैसले का समर्थन किया है. मौलाना वली रहमानी द्वारा जैसे ही योग को लेकर सड़कों पर मुहिम चलाने के लिए पत्र जारी किया गया, उस पर एक उर्दू अख़बार ने जमात-ए-इस्लामी हिंद के महासचिव इंजीनियर मोहम्मद सलीम का साक्षात्कार प्रकाशित किया, जिसमें मोहम्मद सलीम ने साफ़-साफ़ कहा कि उनका संगठन पूरी तरह बोर्ड के फ़ैसले के साथ है. जब उनसे यह कहा गया कि यदि राज्यों में योग के ख़िलाफ मुहिम चलाई गई, तो संभावना यह है कि बिहार में वोटों का ध्रुवीकरण होगा, जिसका सीधा फ़ायदा भाजपा को मिलेगा. तो इंजीनियर सलीम ने इस संभावना को सिरे से नकार दिया.

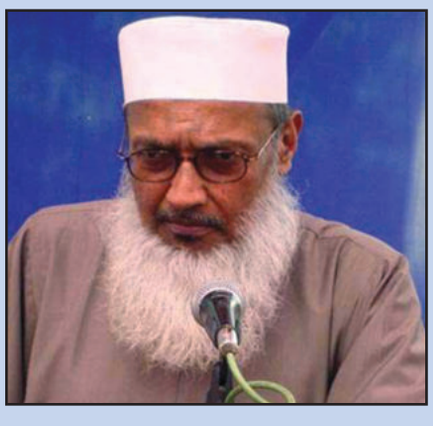

इसी बीच वरिष्ठ उर्दू पत्रकार मंसूर आगा ने अपने एक लेख में बोर्ड की इस मुहिम पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सही नहीं है कि जो योग स्वैच्छिक हो गया है, उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाए. उनका तर्क था कि इस बात पर भी विचार होना चाहिए कि इसका देश में क्या पैग़ाम जाएगा? हमें उन मुसलमानों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो बहुसंख्यक आबादियों में रहते हैं और उनकी संख्या थोड़ी है. इस लेख के प्रकाशित होते ही एक उर्दू अख़बार में मंसूर आगा के ख़िलाफ लिखने वालों की लाइन लग गई और एक ने तो उन्हें जमकर निशाना बनाया. उसके बाद मंसूर आगा ने अपने उस लेख के लिए माफी मांग ली. माफी के बाद समझा जा रहा था कि यह बहस अब ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. एक उर्दू अख़बार लगातार ऐसी सामग्री प्रकाशित करता रहा, जिसमें वली रहमानी का गुणगान करते और पक्ष लेते हुए विरोधियों को लगातार निशाना बनाया गया. उक्त अख़बार ने अपने संपादकीय में भी मंसूर आगा का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष किया. बहरहाल, योग पर शुरू हुआ विवाद आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है. जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योग के विरोध में सख्त क़दम उठाने की ठानी है, उससे बिहार विधानसभा चुनाव में भी यह एक मुद्दा बन सकता है. और, हो सकता है कि इससे पैदा हुए राजनीतिक ध्रुवीकरण का फ़ायदा उन पार्टियों को पहुंचे, जो योग का समर्थन करती हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार चुनाव विशेष बिहार चुनाव

नरकटिया विधानसभा क्षेत्र

टिकट का बंटवारा आसान नहीं है

यह जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है. नरकटिया विधानसभा का निर्माण 2008 में नये परिसीमन के बाद हुआ. 2010 के विधानसभा चुनाव में नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से जदयू के श्यामबिहारी प्रसाद विधायक चुने गये. 2010 के चुनाव में दूसरे स्थान पर लोक जनशक्ति पार्टी के यास्मिन साबिर अली थीं. 2015 के आसन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा के कई नेता चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं.

राकेश कुमार

पूर्वी चम्पारण का नरकटिया विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है. नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली वर्षा के कारण हर वर्ष पहाड़ी नदियों का तांडव झेलना क्षेत्र के लोगों की नियति बन गई है. यह जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है. नरकटिया विधानसभा का निर्माण 2008 में नये परिसीमन के बाद हुआ. 2010 के विधानसभा चुनाव में नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से जदयू के श्यामबिहारी प्रसाद विधायक चुने गये. 2010 के चुनाव में दूसरे स्थान पर लोक जनशक्ति पार्टी के यास्मिन साबिर अली थीं. 2015 के आसन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा के कई नेता चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं. भाजपा के दावेदारों में मुख्य रूप से डॉ लाल बाबू प्रसाद, ध्रुव प्रसाद, पूर्व विधायक वीरेन्द्र कुशवाहा और यास्मिन साबिर अली का नाम आ रहा है.

भाजपा के जिला महामंत्री डॉ लालबाबू प्रसाद एनडीए गठबंधन के प्रबल दावेदार हैं. श्री प्रसाद नरकटिया विधानसभा क्षेत्र स्थित बंजरिया प्रखण्ड के सिसवा अजगरी ग्राम के निवासी हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में वे नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी थे. बकौल डॉ प्रसाद इनके प्रभार में पहली बार छौडादानों और बनकटवा में भाजपा को बड़ी बढ़त प्राप्त हुई थी. वे क्षेत्र के अविकसित रहने का सबसे बड़ा कारण जनप्रतिनिधियों का बाहरी होना मानते हैं.

अनवर आलम अंसारी

डॉ. शमीम अहमद

लालबाबू प्रसाद

नसीमुल हक

यास्मिन साबिर अली

लालबाबू प्रसाद कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं. अजगरी कब्रिस्तान का विवाद सुलझाने में इनकी अहम भूमिका रही है. डॉ लालबाबू प्रसाद अपनी जीत सुनिश्चित मानते हैं. वहीं भाजपा के टिकट की दावेदारी पूर्व विधायक वीरेन्द्र प्रसाद कुशवाहा की भी की जा रही है. श्री कुशवाहा 2000 में आदापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक चुने गये थे. इसके पूर्व वे वामपंथ से जुड़े थे, जबकि पूर्व राज्यसभा सदस्य साबिर अली की पत्नी यास्मिन साबिर अली के दावेदारी की बात भी आ रही है. 2010 के चुनाव में श्रीमती यास्मिन लोजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी थीं. 23861 मत लेकर वे दूसरे स्थान पर थीं. इस लिहाज से उनकी प्रबल दावेदारी बनती है. विगत दिनों साबिर अली भाजपा में शामिल हो गये हैं.

हांलाकि नरकटिया क्षेत्र जदयू का सीट रहा है, लेकिन महागठबंधन के घटक दल राजद के डॉ शमीम अहमद चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हैं. विगत चुनाव में भी इन्होंने नरकटिया से चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन अंतिम समय में टिकट लोजपा के यास्मिन साबिर अली को मिल गया. इससे क्षुब्ध होकर डॉ शमीम अहमद ने 2010 का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा, जिसमें वे 14217 मत के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे. डॉ शमीम 1990 से राजद के साथ हैं. वर्तमान में डॉ शमीम राजद के प्रदेश महासचिव हैं. चुनाव में राजद के टिकट की दावेदारी के संबंध में डॉ शमीम का कहना है कि टिकट इन्हें ही मिलेगा. यह सीट राजद के हिस्से में आयेगी. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार विगत चुनाव भाजपा के सहयोग से जदयू लड़ी और जीती थी. सीटिंग–गेटिंग के अनुसार, यह सीट जदयू की होनी चाहिये, लेकिन ऐसे कयास लगाये जा रहे हैं कि वर्तमान विधायक श्यामबिहारी प्रसाद क्षेत्र परिवर्तन कर रक्सौल से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं. ऐसे में रक्सौल विधानसभा सीट जदयू और नरकटिया विधानसभा राजद के खाते में आयेगा. डॉ शमीम के अनुसार, खैरवा स्वास्थ्य केन्द्र के जरिये इन्होंने क्षेत्र के लोगों की लगातार सेवा की है, जहां गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सेवा दी जाती है. उन्होंने दर्जनों नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है.

महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस के नेता अनवर आलम अंसारी अपनी उम्मीदवारी को लेकर संजीदा हैं. श्री अंसारी पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं. 2005 फरवरी के विधानसभा चुनाव में अदापुर से इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वे चौथे स्थान पर रहे थे. बकौल श्री अंसारी इसमें 9500 मत नरकटिया क्षेत्र के छौडादानों प्रखण्ड से मिले थे. नये परिसीमन में छौडादानों प्रखण्ड के साथ सुगौली विधानसभा का मुस्लिम बहुल प्रखण्ड बंजरिया और बनकटवा को मिलाकर नरकटिया विधानसभा क्षेत्र बना है. इसके कारण मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी बढ़ गई है. मुस्लिम प्रत्याशी इन्हीं मतों को अपना आधार मानते हैं. इधर, पूर्व में आदापुर से चुनाव लड़ चुके सोनू कुमार उर्फ सोनू मुखिया की दावेदारी के भी कयास लगाये जा रहे हैं. 2010 में सोनू कुमार ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था. 13813 मत लेकर वे चौथे स्थान पर थे. वर्तमान में वे राजद में हैं. हालांकि सूत्रों के अनुसार, जिला कांग्रेस कमेटी ने डॉ मोहम्मद नसीमुल हक के नाम को प्रत्याशी के लिए अग्रसारित किया है. डॉ हक पुराने कांग्रेसी स्वर्गीय प्रोफेसर डॉ वाजूल हक के पुत्र हैं. प्रो हक भी राजनीति में गहरी पैठ रखते थे. ■

जातीय आंकड़े

मुस्लिम	– 65,000 लगभग
यादव	– 45,000 लगभग
वैश्य, अतिपिछड़ा	– 40,000 लगभग
ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत	– 30,000 लगभग
अनुसूचित जाति	– 25,000 लगभग
अन्य	–45,000 लगभग

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी : टिकट की दावेदारी में कुशवाहा सबसे आगे

बैद्यनाथ प्रसाद रमन

प्रदीप सिंह कुशवाहा

राघवेंद्र कुशवाहा

राज किशोर कुशवाहा

रामबली सिंह कुशवाहा

सुनील कुशवाहा

अब बारी 2015 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की है. आलम है कि जिले के 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर कुशवाहा समाज के संभावित प्रत्याशी राजनीतिक गलियारों में अपना ठौर तलाशना शुरू कर दिये हैं. यह अलग बात है कि किसी भी सीट पर कुशवाहा बिरादरी इस स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं, जहां से वे अपने बूते चुनावी जंग जीत लेने की कूव्वत रखते हैं. वाबजूद इसके, गठबंधन की राजनीति के बदौलत चुनावी अखाड़ा में आजमाईश को लेकर उठक–बैठक शुरू कर दिया है. अब तक तकरीबन एक दर्जन से अधिक संभावित प्रत्याशी का राजद, जदयू व रालोसपा से चुनाव मैदान में आने की चर्चा है.

वाल्मीकि कुमार

लंबे अर्से से सीतामढ़ी जिला की राजनीति में अपनी भागीदारी देते आ रहे कुशवाहा समाज को अब उम्मीद की लौ दिखायी देने लगी है. 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन के तहत रालोसपा के प्रत्याशी रहे राम कुमार शर्मा की जीत ने जिले में कुशवाहा समाज की मायूसी को बहुत हद तक दूर कर दिया है. इसी का नतीजा है कि 2015 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तकरीबन सभी दलों से कुशवाहा समाज ताल ठोकने की तैयारी में है.

2014 के लोकसभा चुनाव में बतौर रालोसपा प्रत्याशी रहे राम कुमार शर्मा की जीत का सेहरा भले ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे नरेंद्र मोदी के चुनावी लहर को दिया जा रहा है, लेकिन दूसरे नजरिये से इसे कुशवाहा समाज के लिए सीतामढ़ी में एक वरदान भी माना जा रहा है. कारण कि इससे पूर्व कुशवाहा समाज के ही चर्चित शिक्षाविद डॉ इंदल सिंह नवीन, जहां अनेक बार लोकसभा व विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा कर थक चुके, लेकिन सफलता नहीं मिली. वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बतौर लोजपा प्रत्याशी रहे राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जीत के करीब पहुंच कर भी भाजपा के सुनील कुमार पिंटू से चुनाव हार गये. चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति समर्पण भाव रखने वाला कुशवाहा बिरादरी के राज किशोर सिंह कुशवाहा को विधान परिषद सदस्य के रूप में मनोनीत किया था, जबकि दशकों पहले बथनाहा विधानसभा सीट से कुशवाहा बिरादरी के फतुरी सिंह प्रतिनिधित्व का कमान संभाल चुके हैं. अब बारी 2015 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की है. आलम है कि जिले के 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर कुशवाहा समाज के संभावित प्रत्याशी राजनीतिक गलियारों में अपना ठौर तलाशना शुरू कर दिये हैं. यह अलग बात है कि किसी भी सीट पर कुशवाहा बिरादरी इस स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं, जहां से वे अपने बूते चुनावी जंग जीत लेने की कूव्वत रखते हैं. वाबजूद इसके, गठबंधन की राजनीति के बदौलत चुनावी अखाड़ा में आजमाईश को लेकर उठक–बैठक शुरू कर दिया है. अब तक तकरीबन एक दर्जन से अधिक संभावित प्रत्याशी का राजद, जदयू व रालोसपा से चुनाव मैदान में आने की चर्चा है.

बताते चलें कि इन दिनों कुशवाहा बिरादरी के संभावित राजद प्रत्याशी बैद्यनाथ प्रसाद रमन व सुनील कुशवाहा की चर्चा सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में चल रही है. बताया जाता है कि बैद्यनाथ प्रसाद ने रमन शिक्षा सेवा से निवृत्त होने के बाद राजनीति के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया है. लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के कारण इनका दावा है कि समाज के सभी तबके के लोगों में गहरी पैठ का चुनाव में फायदा होना निश्चित है, जबकि सुनील कुशवाहा को पूर्व राजद सांसद सीताराम यादव का करीबी बताया जाता है. इसी सीट से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने को लेकर रामबली सिंह कुशवाहा, प्रदीप सिंह कुशवाहा व सत्येंद्र सिंह कुशवाहा के नाम को लेकर चुनावी चौपालों पर बहस चल रही है. चर्चा यह भी है कि जदयू के उक्त तीनों पार्टी के पूर्व सांसद नवल किशोर राय के करीबी हैं, जबकि इनके अलावा जदयू से ही नागेंद्र कुशवाहा की दावेदारी की भी चर्चा है. चुनावी चर्चा के मुताबिक, रालोसपा से महंत सिंह, श्याम सिंह कुशवाहा, राघवेंद्र रवि व अवधेश कुशवाहा के संभावित दावेदारी की उम्मीद जतायी जा रही है. बताया जाता है कि सीतामढ़ी के अलावा बाजपट्टी, सुरसंड व रून्नीसैदपुर सीट से रालोसपा के संभावित प्रत्याशी खास तौर से तैयारी में लगे हैं. बताते चलें कि राज किशोर सिंह कुशवाहा जदयू से वर्तमान में मनोनीत बिहार विधान परिषद सदस्य हैं. चर्चा है कि वे सीतामढ़ी सीट से अपनी दावेदारी के प्रयास में लगे हैं, जबकि राघवेंद्र सिंह कुशवाहा वर्तमान में नेशनल पीपुल्स पार्टी से जुड़े हैं. जानकारों की मानें तो चुनाव में अभी समय है. वक्त करीब आने पर संभावित प्रत्याशियों की संख्या में बढ़ोत्तरी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. भले ही सीतामढ़ी जिला में गठबंधन की राजनीति के कारण सीटों का हाल जो रहे. ■

feedback@chauthiduniya.com

गया: अबकी बार प्रेम सरकार!

सुनील सौरभ

बिहार विधानसभा का चुनाव ज्यों-ज्यों निकट आते जा रहे हैं, राजनीतिक दलों तथा इनके नेताओं की बेचैनी भी वैसे ही बढ़ती जा रही है. हर दल में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार खड़े हो गये हैं. संस्कार और अनुशासन वाली भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार, भाजपा के देश-प्रदेश के नेतृत्व को हैरान-परेशान कर रहें हैं. इसी कड़ी में गया शहर के विधायक प्रेम कुमार भी भाजपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो गये हैं. बिहार में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में नारा दिया है अबकी बार, भाजपा सरकार. वहीं प्रेम कुमार के समर्थकों द्वारा सोशल मिडिया पर अबकी बार प्रेम सरकार का प्रचार जोर-शोर से किया जा रहा है. जाहिर है इसमें डॉ प्रेम कुमार की भी सहमति होगी. इनके समर्थकों का कहना है कि प्रेम कुमार अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं. वे 1990 से लगातार एक ही क्षेत्र गया शहर विधानसभा से विधायक रहे हैं. उन्होंने बिहार में जदयू-भाजपा की संयुक्त सरकार में सात वर्षों तक महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री पद संभाला. इसलिए बिहार भाजपा तथा भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को चाहिए कि डॉ प्रेम कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें. इतना तो थोड़ी सी राजनीतिक सोच-समझ रखने वाले लोगों को भी मालूम है कि प्रेम कुमार के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के पीछे बिहार प्रदेश भाजपा की गुटबाजी का पता साफ चलता है, क्योंकि बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी के खास रहे प्रेम कुमार अचानक मुख्यमंत्री पद की दावेदारी यूं ही नहीं कर रहे हैं या करा रहे हैं. इसके पीछे भाजपा की अंदरुनी राजनीति और गुटबाजी स्पष्ट मालूम होती है. प्रेम कुमार की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में प्रदेश भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं की मौन सहमति से इंकार नहीं किया जा सकता. वहीं जब प्रेम कुमार की दूरी सुशील कुमार मोदी से बढ़ गयी तो बिहार भाजपा में सुशील मोदी विरोधी गुट ने प्रेम कुमार के प्रचार को मौखिक और मौन समर्थन देना शुरू कर दिया, जिससे प्रेम कुमार के समर्थकों का उत्साह और बढ़ा है. गया में आयोजित अखिल भारतीय चन्द्रवंशी क्षत्रिय महासभा में भी प्रेम कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग भाजपा नेतृत्व से की गयी. वहीं दूसरी ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता अखौरी निरंजन कहते हैं कि प्रेम कुमार मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहें है, इसलिए इन्हें गया सीट छोड़कर बिहार के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए. अखौरी निरंजन ने कहा कि एक बैठक में प्रेम कुमार ने कहा कि पटना जिले का दीघा सीट दिला दिजीए, हम गया सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं. ज्ञात हो कि दीघा सीट से सुशील कुमार मोदी के चुनाव लड़ने की संभावना है. प्रेम कुमार ने दीघा से चुनाव लड़ने की बात पूछे जाने पर कहा कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं. गया शहर के लोग मुझे लगातार छह बार से विजयी बना रहे हैं, यहां के लोगों का स्नेह, सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा है. मैं भी गया शहर वासियों की सेवा में तत्पर रहता हूं. ऐसे में गया शहर विधानसभा क्षेत्र छोड़ने का सवाल ही नहीं है. प्रेम कुमार समर्थक और भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री आर. एस. नागमणी ने कहा कि बिहार में सबसे अधिक मुख्यमंत्री उत्तर बिहार से हुए हैं, ऐसे में दक्षिण बिहार से प्रेम कुमार की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी उचित है. यदि भाजपा इन्हे मुख्यमंत्री बनाती है तो दक्षिण बिहार के सर्वांगिण विकास के साथ-साथ अति पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बनाये जाने का देश में अच्छा संदेश भी जायेगा.

इन सब बातों से स्पष्ट है कि बिहार भाजपा में सबकुछ अच्छा नहीं चल रहा है. आपसी गुटबाजी से भाजपा भी नहीं बच पा रही है. चुनाव को लेकर भले ही ही सभी चुपचाप हैं, लेकिन चुनाव आते-आते भाजपा की अंदरुनी राजनीति बाहर जरूर आयेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए कई लोगों की दावेदारी ने भाजपा की गुटबाजी को सार्वजनिक कर दिया है. देखना है कि डॉ प्रेम कुमार अपने अभियान में कितना सफल हो पाते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

याकूब मेमन को हुई फांसी पर राजनीति की आग में घी डालते हुए एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने नाख़ुशी जताई, तो सपा नेता आजम ख़ान ने ओवैसी पर सीधा निशाना साधा. आजम ख़ान ने कहा कि जो लोग इस सजा का विरोध कर रहे हैं, वे देश को बांटना चाहते हैं. आजम ने कहा, जो लोग याकूब मेमन की हिमायत कर रहे हैं, वे ग़लत हैं और समाज को बांटना चाहते हैं. कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे याकूब के मजहब को उछाला जा रहा है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. क़ानून सबसे ऊपर है. याकूब की फांसी पर ओवैसी ने कहा था, यह इंसाफ नहीं हुआ. यह ठीक है कि मुंबई दंगों में जो लोग मारे गए थे, उनके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बाबू बजरंगी, माया कोडनानी, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को भी फांसी मिलनी चाहिए.

उत्तर प्रदेश

आजम का नया अवतार

प्रभात रंजन दीन

एक तरफ़ याकूब मेमन को फांसी देने की औपचारिकताएं पूरी हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ़ उत्तर प्रदेश में फांसी पर सियासत हो रही थी. याकूब की फांसी पर तल्ख बयान देकर मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की धार कम करने की कोशिश में समाजवादी पार्टी के नेता लगे हुए थे. सपा के सामने दिक्कत यह आ रही थी कि उसके कई नेता भी ओवैसी की भाषा में बात कर रहे थे. सपा के महाराष्ट्र के नेता अबू आजमी हों या याकूब की पत्नी राहीन मेमन को राज्यसभा भेजने की हिमायत करने वाले सपा की महाराष्ट्र इकाई के अपाध्यक्ष फारुक घोसी, इन सबने समाजवादी पार्टी की नीति की ऐसी-तैसी करके ओवैसी की भाषा में बात की. सपा ने इसके लिए अपने वरिष्ठ नेता आजम खान को आगे किया. आजम ने याकूब की फांसी को लेकर ऐसे नपे-तुले बयान दिए कि लोग हैरत में आ गए कि यह वाकई आजम का बयान है या नहीं. लोगों को आश्चर्य इसलिए भी हुआ कि ओवैसी का बयान आने के पहले आजम यह कह चुके थे कि याकूब मेमन को फांसी देने से देश में नफरत की भावना फैलेगी. लेकिन, ओवैसी की राजनीति की काट करने के लिए आजम ने सपा नेतृत्व के इशारे पर फौरन पैंतरा बदल लिया.

याकूब मेमन को हुई फांसी पर राजनीति की आग में घी डालते हुए एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने नाखुशी जताई, तो सपा नेता आजम खान ने ओवैसी पर सीधा निशाना साधा. आजम खान ने कहा कि जो लोग इस सजा का विरोध कर रहे हैं, वे देश को बांटना चाहते हैं. आजम ने कहा, जो लोग याकूब मेमन की हिमायत कर रहे हैं, वे ग़लत हैं और समाज को बांटना चाहते हैं. कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे याकूब के मजहब को उछाला जा रहा है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. क़ानून सबसे ऊपर है. याकूब की फांसी पर ओवैसी ने कहा था, यह इंसाफ नहीं हुआ. यह ठीक है कि मुंबई दंगों में जो लोग मारे गए थे, उनके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बाबू बजरंगी, माया कोडनानी, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को भी फांसी मिलनी चाहिए. फांसी पर लटकाना अगर इंसाफ है, तो इन लोगों को भी फांसी मिलनी चाहिए. मैं याकूब का पक्ष नहीं लेता, लेकिन हमेशा हमारा ही नुक़सान होता है. बेअंत सिंह के कातिल को मजहब के नाम पर बचाया जा रहा है. यही हाल राजीव गांधी के हत्यारों का है. बाबरी मस्जिद गिराने वालों को भी फांसी होनी चाहिए. अगर मैं सम्मान के साथ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से नाखुश होता हूं, तो क्या ग़लत है? ओवैसी ने यह भी कहा था कि याकूब ने तो भारतीय खुफिया एजेंसियों की मदद की थी, उसने अपने भाई के ख़िलाफ़ भी सुबूत दिए थे. गुजरात दंगों के दोषियों को सरकार फांसी क्यों नहीं देती?

ओवैसी के बयान में बाबरी मस्जिद का जिक्र उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मुस्लिम मतदाताओं को साधने के इरादे से किया गया था, यह मानते हुए समाजवादी पार्टी ने फौरन इस पर किलेबंदी शुरू कर दी और ओवैसी के बयान को राष्ट्र विरोधी व क़ानून विरोधी रंग में उतारने की कोशिश हुई, लेकिन इस रंग में सपा नेताओं ने भंग डालने का काम किया. महाराष्ट्र के सपा नेता अबू आजमी ने कहा, याकूब की फांसी पर मुझे गहरा अफ़सोस है. याकूब खुद चलकर आया था, उसने खुद सरेंडर किया था. रॉ के अफसर बी रमण का ऑर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि यह ग़लत हुआ. हमें सोचना होगा कि दाऊद और याकूब ने बम ब्लास्ट क्यों कराए थे? इसके फौरन बाद महाराष्ट्र के ही सपा नेता फारुक घोसी ने याकूब की पत्नी को सांसद बनाने की मांग कर दी. फारुक ने कहा कि यदि मुलायम सिंह ऐसा फ़ैसला लेते हैं, तो उसके कष्ट पर मरहम लगाया जा सकता है. फारुक ने इसके लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को एक पत्र लिख डाला और उसके बारे में मीडिया को बता भी दिया.

पत्र में फारुक ने मुलायम सिंह यादव को लिखा है, आपसे गुजारिश है कि 30 जुलाई, 2015 को याकूब मेमन को फांसी देने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल खड़े हुए, जो आपको लिख रहा हूं. याकूब मेमन के साथ उनकी पत्नी राहीन याकूब मेमन भी गिरफ्तार हुई थीं, परंतु माननीय न्यायालय ने याकूब मेमन को दोषी करार दिया और राहीन को बरी कर दिया. वह भी कई सालों तक जेल में रहीं. कितनी तकलीफ सही होगी और हम समाजवादियों की एक खूबी है कि मन में जो बात रहे, उसे कहना ज़रूरी है. आप ग़रीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए जाने जाते हैं. मेरे मुताबिक याकूब की पत्नी राहीन को इस समय मदद की ज़रूरत है और बहुत सारी औरतें इस देश में उनकी तरह दयनीय हालत में अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं. हमें इन औरतों की मदद करनी चाहिए. आज मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देखा जाता है और मुख्य राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें साइड लाइन कर दिया है. राहीन 21 सालों से अपने पति के बिना रह रही हैं. अगर राहीन राजनीति में आती हैं, तो वह ज़रूरतमंद लोगों की आवाज़ बन सकती हैं. इन बयानों से समाजवादी पार्टी अत्यंत असहज स्थिति में आ गई और उसे आक्रामक रूप से आगे आने पर विवश होना पड़ा. सपा नेतृत्व ने फौरन फारुक घोसी को महाराष्ट्र इकाई के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया और अबू आजमी को मुंह पर काबू रखने की सख्त हिदायत दी. फिर आजम को मैदान में उतारा गया. आजम ने ओवैसी के बयान पर तो तीखी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अबू आजमी और फारुक घोसी के बयानों पर उन्होंने नपे-तुले अंदाज़ में कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है. फारुक घोसी ने मुलायम सिंह को चिट्ठी लिखी है. फ़ैसला मुलायम सिंह यादव को करना है. राज्यसभा का कौन सांसद बनेगा, यह संसदीय बोर्ड तय करता है, लिहाजा घोसी को अपनी बात उसी के सामने रखनी चाहिए थी.

ओवैसी के बयान पर आए आजम खान के बयान को राजनीति के पंडित बेहद सधा हुआ और राष्ट्रीय एकता वाला बताते हैं. वे कहते हैं कि ओवैसी के समानांतर राजनीतिक रेखा खींचने की कोशिश के बावजूद उनका बयान राष्ट्र भावना और धर्मनिरपेक्षता के अनुकूल है. वही आजम खान करगिल के शहीदों और भारत माता के बारे में विवादास्पद बयान देने के कारण कभी सुर्खियों में रहे हैं. आजम ने याकूब के पैरोकारों को जमकर लताड़ा. सपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर ग़ौर से देखें, तो साफ़ होता है कि ओवैसी का बयान उत्तर प्रदेश पर निशाना साध रहा है. ओवैसी ने सुनियोजित तरीके से याकूब मामले को अयोध्या एवं गुजरात से जोड़ा, बाबरी विध्वंस से जोड़ा और धार्मिक दीवार खड़ी करने की सियासत साधी. ओवैसी विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा उठाकर धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे, सपा नेतृत्व इसे भांप रहा है. ओवैसी यह भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के स्टार प्रचारक होंगे, लिहाजा माया कोडनानी एवं बाबू बजरंगी का मुद्दा उठाना उनकी सोची-समझी चाल है. ओवैसी के बयान की सियासी तासीर भांपते हुए न केवल सपा, बल्कि बसपा भी सचेत हुई. बसपा नेता मायावती ने ओवैसी का नाम लिए बगैर उनका असर कम करने की कोशिश की. मायावती ने न्यायिक प्रक्रिया और बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का सम्मान करने पर जोर दिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

अब बुजुर्ग अहमद ने ठोंकी ताल

समाजवादी पार्टी ने एक तरफ़ अपने मुखर नेता आजम खान को संतुलित नेता के रूप में सामने लाने की गोट आजमाई, तो दूसरी तरफ़ अहमद हसन जैसे शाकाहारी नेता को तल्ख बयान देने वाले फ्रंट पर पहले से ही प्रैक्टिस पर उतार दिया है. अपने स्वभाव के विपरीत अहमद हसन ने पिछले दिनों देश में मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप उछाला और अपने बयान की तरफ़ मुसलमानों के साथ-साथ अन्य लोगों का भी ध्यान खींचा. समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की प्रांतीय कार्यकारिणी की पिछले दिनों हुई बैठक में वयोवृद्ध स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने कहा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ी साजिशें हो रही हैं, स्कूलों में पाठ्यक्रम बदला जा रहा है और कहा जा रहा है कि मदरसा पढ़ाई के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं. ये शरारत भरे बयान हमें उकसाने के लिए दिए जाते हैं. हसन ने इसी में आने वाले विधानसभा चुनाव का मुद्दा खोंसा और कहा कि अगला विधानसभा चुनाव बहुत चुनौती भरा होगा. भाजपा ज़हर फैला रही है, वह दंगा कराने की साजिशें करेगी और केंद्र सरकार आतंकवाद के नाम पर बेगुनाहों को सताने का काम करेगी. हसन ने कहा कि मुस्लिम सिर्फ़ समाजवादी सरकार में अमन से रह रहे हैं.

उत्तराखंड

स्टिंग करने वाला पत्रकार राज्य सरकार के निशाने पर

राजकुमार शर्मा

सूबे की हरीश रावत सरकार के कथित भ्रष्टाचार को लेकर किए गए स्टिंग ऑपरेशन ने सियासी गलियारे में गरमाहट पैदा कर दी है. उक्त स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने वाले पत्रकार के निर्माणाधीन आवास के संबंध में शासन-प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री रावत और उनकी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत और नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा कि रावत सरकार बौखला गई है और उसी बौखलाहट में मुख्यमंत्री तानाशाही रवैया अपना रहे हैं. भाजपा नेताओं ने कहा कि उक्त पत्रकार ने प्रदेश के हालात को देखते हुए स्टिंग किया, लेकिन शासन ने बदले की भावना से प्रेरित हो उसका घर तोड़े जाने का नोटिस एमडीडीए द्वारा चस्पा करा दिया. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार उजागर करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना और उनके घर तोड़ना प्रजातंत्र पर हमले के समान है. जब प्रदेश में चारों ओर सरकार के भ्रष्टाचार की बात उजागर हो गई है, तो मुख्यमंत्री को स्वयं पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति कर देनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके. भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री हरीश रावत के सचिव मोहम्मद शाहिद के कथित स्टिंग की जांच दो क़दम भी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन स्टिंग करने वाले पत्रकार अशोक पांडेय सरकार के निशाने पर आ गए.

ग़ौरतलब है कि उक्त पत्रकार ने मुख्यमंत्री के सचिव

इस मामले में एमडीडीए का पक्ष लेने के लिए उपाध्यक्ष आर मीनाक्षी सुंदरम एवं सचिव पीसी दुमका से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया. पीड़ित पत्रकार पांडेय इस मामले और सीडी प्रकरण को लेकर उच्च न्यायालय नैनीताल चले गए हैं. वह रिट दाखिल कर पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करेंगे.

का स्टिंग करके सरकार में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार उजागर करने का प्रयास किया था, जिसे लेकर सूबे से केंद्र तक हलचल मच गई. बीती 22 जुलाई को दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उक्त पत्रकार शामिल क्या हुआ, राज्य सरकार की आंख की किरकिरी बन गया. सूत्र कहते हैं कि पहले तो उक्त पत्रकार को बैलेंस करने की कोशिश की गई, लेकिन जब बात नहीं बनी, तो एमडीडीए (मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण) ने उसका निर्माणाधीन घर गिराने का नोटिस दरवाजे पर चस्पा कर दिया. पांडेय का मकान नारी शिल्प मंदिर मार्ग पर टैगोर विला में निर्माणाधीन है. इस मकान का नक्शा बहुत पहले बना था, जिसकी मियाद 2011 में ख़त्म हो गई और निर्माण शुरू नहीं हो सका. बाद में खंडूडी सरकार ने नियमावली बदली, तो रिवाइज मैप

कंपाउंडिंग के लिए जमा कराया गया. अब बदले माहौल में हुआ यह कि पिछली तारीखों के नोटिस बनवा कर बीती दस जुलाई को घर गिराने का आदेश जारी दिखाकर नोटिस चस्पा कर दिया गया. आरोप यह भी है कि चस्पा करने के बाद नोटिस का फोटो खींचा गया और फिर फाड़ दिया गया.

इस मामले में एमडीडीए का पक्ष लेने के लिए उपाध्यक्ष आर मीनाक्षी सुंदरम एवं सचिव पीसी दुमका से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया. पीड़ित पत्रकार पांडेय इस मामले और सीडी प्रकरण को लेकर उच्च न्यायालय नैनीताल चले गए हैं. वह रिट दाखिल कर पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करेंगे. यदि उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली, तो वह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

नीरा राडिया की अंतरंग दुनिया

अटल तक पहुंच बनाने की नाकाम कोशिश

मेरे लिए यहां किसी परिस्थितिजन्य या कानाफूसी (गॉसिप) आधारित साक्ष्य देने की ज़रूरत नहीं है कि क्या वाकई स्वामी ने प्रधानमंत्री के साथ नीरा के व्यक्तिगत संबंध बनाने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी या नहीं? यह सारी कहानी (सूत्र या खुफिया जानकारी पर आधारित) 26 मार्च, 2003 को एक कन्नड़ साप्ताहिक लंकेश पत्रिका ने प्रकाशित की थी. अब तक इसका कोई खंडन नहीं आया है. इस साप्ताहिक ने एक तस्वीर भी प्रकाशित की थी, जिसमें नीरा राडिया पेजावर स्वामी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ दिख रही है.

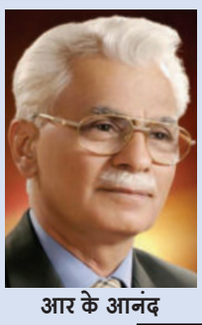

आर के आनंद

नीरा अब तक भारत में अपनी पैठ बना चुकी थी. मंत्रियों तक से उसके रिश्ते बनने लगे थे, लेकिन वह सिर्फ़ मंत्रियों एवं नौकरशाहों से ही अपने ताल्लुकात बनाकर संतुष्ट नहीं थी. उसे यह मालूम था कि उसके बिजनेस के लिए उसका मददगार कौन हो सकता है? वह अपने संबंधों का दायरा बढ़ाना चाह रही थी. उस वक्त विमानन का क्षेत्र बहुत बड़ा हो चुका था. इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं थीं. इसलिए नीरा ने उस वक्त इसी क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया. वह जानती थी कि इस क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है, तो किसी भी क़ीमत पर उसे बड़े नेताओं से संपर्क साधना ही होगा और उन्हें अपनी तरफ़ आकर्षित करना ही होगा. वह भारत के तबके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी से भी अपनी निकटता बढ़ाना चाहती थी. प्राय: किसी प्रधानमंत्री के दिल और दिमाग में उतरने का एक ही रास्ता होता है यानी किसी साधु-महात्मा का सहारा. भारतीय स्वभावत: अंधविश्वासी होते हैं. ज़्यादातर भारतीयों की कमजोरी ज्योतिषी, अंकशास्त्री एवं भविष्यवक्ता होते हैं. खुद नीरा ने भी अपने नाम में दो आई (एनआईआईआरए) लगाया हुआ था. उसका खुद का विश्वास न्यूमेरोलॉजी (अंकशास्त्र) में था. जैसे ही नीरा भारत आई, उसने अपने नाम में एक आई की जगह दो आई लगा लिए.

कई भारतीय प्रधानमंत्री इस तरह के साधु-संतों के चक्कर में पड़ चुके हैं, जैसे धीरेंद्र ब्रह्मचारी. धीरेंद्र ब्रह्मचारी इतने ताकतवर थे कि उनके ज़रिये कोई सीधे इंदिरा गांधी से भी मिल सकता था. चंद्रास्वामी जैसे साधु ने तो शक्तिशाली प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हाराव और समाजवादी नेता चंद्रशेखर को भी मोहित कर लिया था. नीरा के संपर्क में भी कुछ साधु आए. कुमार ने अपने गुरु विश्वेशा तीर्थ स्वामी (पेजावर मठ, उडुपी, कर्नाटक) से नीरा का परिचय कराया. स्वामी से नीरा का परिचय कराने का मकसद स्वामी के ज़रिये प्रधानमंत्री तक पहुंच बनाना था. इस संबंध का फ़ायदा 2002 में वसंत कुंज के अरावली रेंज में स्वामी के उडुपी मठ के लिए ज़मीन आवंटन में उठाया गया. सरकार ने ज़मीन का आवंटन भी कर दिया. मठ के लिए यह ज़मीन एक ट्रस्ट के नाम आवंटित की गई. मजेदार बात यह है कि उस ट्रस्ट में एक महत्वपूर्ण ट्रस्टी नीरा राडिया भी थी. बहुत सालों बाद जब राडिया टेप प्रकरण सामने आया और लगातार मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगा, तब कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस करके कई सवाल उठाए. कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आख़िर क्यों राडिया के ट्रस्ट को दिल्ली में ज़मीन का आवंटन हुआ? किसने और किस आधार पर यह ज़मीन आवंटित की? क्या तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने मठ के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया था, क्योंकि वह राडिया के काम से प्रभावित थे?

अंदर की बात यह है कि जब राडिया उक्त ट्रस्ट की वाइस प्रेसिडेंट बनी, तब वह पेजावर स्वामी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई. प्रधानमंत्री कार्यालय में स्वामी के साथ जाकर राडिया ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को शिलान्यास कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था. लेकिन, खुफिया अधिकारियों ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कुछ ऐसी सूचनाएं दीं, जिससे उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करने से मना कर दिया. खुफिया अधिकारियों ने उन्हें नीरा राडिया की लॉबिंग से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी दी और सलाह दी कि वह इस कार्यक्रम में शिरकत न करें. इस तरह प्रधानमंत्री ने अंतत: इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं की. इसके बाद स्वामी ने आडवाणी से अनुरोध किया कि वह शिलान्यास कार्यक्रम में आएं. स्वामी से अपने निकट संबंधों की वजह से आडवाणी ने इसके लिए हामी भर दी. एक अवसर पर मैं भी दक्षिणी दिल्ली स्थित इस मंदिर में था, जब आडवाणी पेजावर स्वामी से मिलने आए थे. नीरा राडिया से अपनी दोस्ती की वजह से मैं भी स्वामी को जानता था.

लेकिन, मेरे लिए यहां किसी परिस्थितिजन्य या कानाफूसी आधारित (गॉसिप) साक्ष्य देने की ज़रूरत नहीं है कि क्या वाकई स्वामी ने प्रधानमंत्री के साथ नीरा के व्यक्तिगत संबंध बनाने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी या नहीं? यह सारी कहानी (सूत्र या खुफिया जानकारी पर आधारित) 26 मार्च, 2003 को एक कन्नड़ साप्ताहिक लंकेश पत्रिका ने प्रकाशित की थी. अब तक इसका कोई खंडन नहीं आया है. इस साप्ताहिक ने एक तस्वीर भी प्रकाशित की थी, जिसमें नीरा राडिया पेजावर स्वामी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ दिख रही है. ■

जारी...

(आर के आनंद मशहूर वकील और क्लोज इंकाउंटर्स विद नीरा राडिया के लेखक हैं.)

विकास पर भारी जातीय समीकरण

कुमार अभिषेक

सूबे में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है. आगामी अक्टूबर-नवंबर महीने में चुनाव संभावित हैं. राजनीति की पाठशाला कहे जाने वाले बिहार की सच्चाई यह है कि वर्ष 1952 से लेकर 2014 तक के सभी चुनाव जाति आधारित समीकरण पर होते रहे हैं. बिहार के हर चुनाव में विकास की राजनीति पर जातीय समीकरण हावी रहे हैं. राज्य की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की चुनावी तैयारियां देखकर यही लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव भी जातीय समीकरण के आधार पर होंगे. राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने वर्ष 2011 में हुई जाति आधारित जनगणना को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ रखा है. वह न सिर्फ़ इस जनगणना को मुद्दा बनाकर पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों को गोलबंद करके अपना पुराना जातीय जनाधार मजबूत करने के प्रयास में हैं, बल्कि यह संदेश भी दे रहे हैं कि केंद्र सरकार इस जनगणना के आंकड़े जारी न करके पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों की भागीदारी कम करना चाहती है. आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्य मुक़ाबला भाजपा नीत राजग और जद (यू), राजद, कांग्रेस महा-गठबंधन के बीच है. दोनों प्रमुख गठबंधनों में शामिल राजनीतिक दलों ने जातीय समीकरणों के आधार पर राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है.

बिहार

सबसे पहले बात करते हैं भाजपा एवं उसके सहयोगी दलों की. राजग में लोजपा व रालोसपा भी शामिल हैं. राजग को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की नई पार्टी हम और हाल में राजद से निष्कासित हुए लोकसभा सदस्य पप्पू यादव का भी साथ मिलने की संभावना है. अभी उनके बीच सीटों के बंटवारे पर बात चल रही है. इस गठबंधन में शामिल सभी दल इस बात पर सहमत हैं कि चुनाव परिणाम राजग के पक्ष में आया, तो मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा. केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार बिहार के विकास के लिए नई-नई योजनाओं की घोषणा करने वाली है. भाजपा नेतृत्व जातीय समीकरण भी साधने में लगा है. इस क्रम में पटना और उसके आस-पास के ज़िलों में सम्मेलन कराए जा रहे हैं. भाजपा नेतृत्व की नज़र अब तक लालू एवं नीतीश के साथ रहे 51 प्रतिशत आबादी वाले ईबीसी-ओबीसी समुदाय पर है. इसके लिए भाजपा संगठन में पहली बार एक मोर्चा गठित किया गया है, जिसकी ज़िम्मेदारी एसपी सिंह बघेल एवं सुधा यादव को सौंपी गई है. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सह बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव राज्य में बराबर मौजूद हैं. अनंत कुमार को चुनाव प्रभारी और धर्मेंद्र प्रधान, सीआर पाटिल एवं पवन शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है. भाजपा नेतृत्व किसी भी क़ीमत पर बिहार में सरकार बनाना चाहता है.

राज्य में 14 प्रतिशत आबादी वाले ओबीसी मतदाताओं पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद की मजबूत पकड़ है, जिसे भाजपा हर हाल में तोड़ना चाहेगी. पप्पू यादव की कोशी क्षेत्र के मतदाताओं पर अच्छी पकड़ है, लेकिन इलाकाई मतदाता पप्पू का कितना सहयोग करेंगे, यह एक गूढ़ प्रश्न है, क्योंकि

छह प्रतिशत दलितों एवं 18 प्रतिशत महादलितों को रिझाने के लिए वह लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का सहारा लेगी. उधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी विकास पुरुष वाली छवि के साथ-साथ राजद, कांग्रेस एवं अन्य सहयोगी दलों के मतदाताओं पर भरोसा है. नीतीश कुमार भी नई-नई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं.

आज भी बिहार का यादव समुदाय लालू प्रसाद को अपना सबसे बड़ा रहनुमा मानता है. उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बनाए गए 24 प्रतिशत ईबीसी समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा रालोसपा प्रमुख सह केंद्रीय राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा का सहयोग लेगी, जिनका नीतीश कुमार के साथ छत्तीस का आंकड़ा है. यादव के बाद कुशवाहा बिहार में ईबीसी के अधीन दूसरी सबसे बड़ी बिरादरी है, जिसकी आबादी क़रीब छह प्रतिशत है. नीतीश कुमार ने अभी हाल में कुशवाहा समुदाय की उपजाति दांगी को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करा दिया, जिससे उपेंद्र कुशवाहा की ताकत घटी है. राज्य में 15 प्रतिशत आबादी वाली उच्च जातियों को भाजपा अपना सबसे बड़ा वोट बैंक मानती है. ब्राह्मण एवं कायस्थ भाजपा के परंपरागत मतदाता रहे हैं. पूर्व में भी इन दोनों जातियों के वोट भाजपा को मिले हैं.

दो भूमिहार विधायकों अनंत सिंह और सुनील पांडे की गिरफ्तारी से भूमिहार बिरादरी जद (यू) से नाराज चल रही है, जिसकी आबादी क़रीब छह प्रतिशत है. पूर्व में रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के मामले में भी जद (यू) सरकार की निरकुंशता को लेकर भूमिहार बिरादरी में खासी नाराजगी है. भाजपा उच्च वर्ग में शामिल इस सबसे बड़ी बिरादरी को रिझाने का प्रयास कर रही है. वहीं तीन प्रतिशत राजपूत समुदाय के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उसने विशेष रणनीति बनाई है. छह प्रतिशत दलितों एवं 18 प्रतिशत महादलितों को रिझाने के लिए वह लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का सहारा लेगी. उधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी विकास पुरुष वाली छवि के साथ-साथ राजद, कांग्रेस एवं अन्य सहयोगी दलों के मतदाताओं पर भरोसा है. नीतीश कुमार भी नई-नई योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं. महा-गठबंधन में शामिल सभी दलों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है. जातीय समीकरण साधने में भी नीतीश कुमार भाजपा (राजग) से पीछे नहीं हैं. छह प्रतिशत आबादी वाली पासवान एवं दुसाध जाति को छोड़कर शेष 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति के मतदाताओं को उन्होंने महादलित का दर्जा दे दिया है. नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं और 12 प्रतिशत आबादी वाले कोयरी-कुर्मी समाज पर उनकी विशेष पकड़ है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

देश का राजनीतिक रुख बिहार चुनाव तय करेगा

वित्तीय अधिकार लोकसभा को इसलिए दिया गया है, ताकि राज्यसभा सरकार के वित्त संबंधी कामों में बाधा न उत्पन्न कर सके. हालांकि, जिन विधेयकों का सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है, जैसे भूमि अधिग्रहण इत्यादि, उन पर राज्यसभा को अपनी बात रखने का अधिकार अवश्य मिलना चाहिए. यह कहना भी उचित नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य सीधे तौर पर जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि विधानसभा द्वारा चुनकर आते हैं, इसलिए वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते. दूसरी तरफ़ वे लोग भी हैं, जो इसे विशेषाधिकार का हनन कह रहे हैं, जो कि ग़लत है. अरुण जेटली ने कोई विशेषाधिकार हनन करने वाली बात नहीं कही है. लेकिन, निश्चित तौर पर उन्होंने एक मुद्दा उठाया है, जिस पर बहस होनी चाहिए.

संसद ने पिछले दिनों पिछले 15 महीनों के दौरान सबसे खराब स्थिति देखी. 44 सदस्यों वाली कांग्रेस शुरू से ही सत्तारूढ़ पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रही थी. हालांकि, अब जो हो रहा है, वह संसदीय मानकों और राजनीतिक आचरण के ख़िलाफ़ है. यदि महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने हैं, तो यह सत्तारूढ़ पार्टी का काम है कि वह विपक्ष से बातचीत करके उसे अपने पक्ष में लाए और एक आम सहमति पर पहुंचने की कोशिश करे. अमेरिका में क्या होता है? वहां विधेयक पारित करने के लिए सीनेट के साठ सदस्यों की ज़रूरत होती है और राष्ट्रपति की पार्टी के पास साठ सदस्य कभी नहीं होते. इसलिए राष्ट्रपति को हमेशा विपक्षी दल के समर्थन की ज़रूरत पड़ती है.

यहां तक कि ब्रिटेन में भी अंतर्दलीय चर्चा हमेशा होती रहती है और संसदीय समिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. भारत भी थोड़ी-बहुत समस्या के साथ काफी सुचारू रूप से कार्य करता रहा है. पिछले दस सालों के दौरान कांग्रेस भाजपा को मनाकर अपना काम करती रही. दुर्भाग्य की बात यह है कि 282 सीटों पर जीत और विपक्ष या सहयोगियों के समर्थन के बिना सरकार चलाने लायक बहुमत हासिल करके भी भाजपा आज अपना काम नहीं कर पा रही है. संसद को सुचारू रूप से चलाने में संसदीय मामलों के मंत्रालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. वेंकैया नायडू इसके मंत्री हैं, लेकिन वह सक्षम नज़र नहीं आ रहे हैं. उनका हाव-भाव और भाषा टकराव वाली है. वेंकैया जिस तरीके से बोल रहे हैं, वह तरीका अन्य दलों को मिलाकर सौहार्द स्थापित करने वाला नहीं है. मेरे जैसा व्यक्ति सोचता था कि दो-तीन सत्रों के बाद वे लोग इसके आदी हो जाएंगे और मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन एनडीए के सत्ता में आने के बाद यह चौथा सत्र है और चीजें बद से बदतर होती जा रही हैं.

विपक्ष के 25 सांसदों का निलंबन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्थापित एक ग़लत मिसाल है. अगर कोई सदस्य नियंत्रण से बाहर जाता है, तो आप उसे निलंबित कर सकते हैं. और, अगर वह माफी मांग ले, तो उसका निलंबन वापस भी हो सकता है. लेकिन, कांग्रेस के 44 में से 25 सांसदों का निलंबन आपातकाल की याद दिलाता है, जिसमें सरकार ने लगभग सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद संसद सत्र बहुत आसानी से चला. वही अब हो रहा है. विपक्ष ने 25 सांसदों के निलंबन के बाद संसद का बहिष्कार किया है. अब यह सत्र एक अर्थहीन सत्र है. अगर आप अपने सभी विधेयक पारित कर लेते हैं और वहां कोई विरोध करने वाला नहीं है, तो उसका क्या अर्थ है? एक पुरानी कहावत है कि सरकार अपना काम करे और विपक्ष अपनी बात रखे. इसी तरह से पूरी दुनिया में संसद चलती है. अगर आप विपक्ष की बातों को महत्व नहीं देते, तो फिर संसदीय लोकतंत्र कैसे चलेगा, यह समझ से बाहर है. रणनीतिकार कौन है, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन मेरी आशंका है कि यह अमित शाह हैं, जो रणनीति बना रहे हैं. प्रधानमंत्री एक मूकदर्शक नहीं बने रह सकते. आख़िरकार इससे उनकी प्रतिष्ठा को ही क्षति पहुंचेगी, जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव जीता था.

मैं समझ सकता हूं कि बिहार चुनाव आ रहा है और वे चाहते हैं कि एक सख्त रुख अपना कर सदन के भीतर से ही चुनाव अभियान की शुरुआत हो, लेकिन इस तरह काम नहीं होना चाहिए. यह एक घटिया तरीका है, जो संसदीय कामकाज में पहुंच गया है. अरुण जेटली संसदीय कामकाज के अनुभवी व्यक्ति हैं. वह जानते हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब भाजपा ने भी यही रणनीति अपनाई थी. तब भी इतनी संख्या में निलंबन नहीं हुआ था. अब यह क्यों होना चाहिए? किसी की समझ में नहीं आ रहा है. अरुण जेटली ने यह भी कहा कि राज्यसभा को इतना महत्व नहीं मिलना चाहिए, जितना उसे अभी मिल रहा है. अनिर्वाचित सदस्य विधेयक पारित करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं. यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान है. संविधान में स्पष्ट रूप से लोकसभा और राज्यसभा के नियमों का उल्लेख है, जिनमें यह बताया गया है कि दोनों सदन महत्वपूर्ण क्यों हैं?

वित्तीय अधिकार लोकसभा को इसलिए दिया गया है, ताकि राज्यसभा सरकार के वित्त संबंधी कामों में बाधा न उत्पन्न कर सके. हालांकि, जिन विधेयकों का सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है, जैसे भूमि अधिग्रहण इत्यादि, उन पर राज्यसभा को अपनी बात रखने का अधिकार अवश्य मिलना चाहिए. यह कहना भी उचित नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य सीधे तौर पर जनता द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि विधानसभा द्वारा चुनकर आते हैं, इसलिए वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते. दूसरी तरफ़ वे लोग भी हैं, जो इसे विशेषाधिकार का हनन कह रहे हैं, जो कि ग़लत है. अरुण जेटली ने कोई विशेषाधिकार हनन करने वाली बात नहीं कही है. लेकिन, निश्चित तौर पर उन्होंने एक मुद्दा उठाया है, जिस पर बहस होनी चाहिए. वह मुद्दा यह है कि हमें राज्यसभा की ज़रूरत है या नहीं? वह यह क्यों नहीं कहते कि राज्यसभा को ख़त्म कर देना चाहिए? एक संविधान संशोधन लाइए और उस पर बहस कीजिए. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ दल विधेयक पारित कराने और संसदीय सद्भावना बनाए रखने में सक्षम साबित नहीं हो रहा है. काम न करा पाने से उसमें झल्लाहट बढ़ रही है, जिसके चलते तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो सही नहीं हैं.

मैं आशा करता हूं कि स्पीकर (लोकसभा अध्यक्ष) अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार करेंगी, क्योंकि निलंबन केवल पांच दिन का था और पांच दिन का समय बीत गया है. भाजपा के इस फ़ैसले ने संपूर्ण विपक्ष को एकजुट कर दिया है. अगर भाजपा धैर्य से काम लेती, तो विपक्ष में एकजुटता पैदा न होती. लेकिन, उसने विपक्ष को एकजुट होने का मौक़ा दे दिया. यह भारतीय जनता पार्टी की अच्छी राजनीति नहीं कही जा सकती. यह सत्र बहुत छोटा है. इसके बाद बिहार चुनाव होना है. दरअसल, बिहार चुनाव ही निर्णय करेगा कि देश की राजनीति कौन-सा रुख अख्तियार करेगी. अगर भाजपा जीतती है, तो वह और सख्त एवं अहंकारी हो जाएगी तथा संसदीय राजनीति एक नई राह पर चल निकलेगी. अगर वह बिहार में हार जाती है, तो उसका रवैया कुछ नरम पड़ेगा और उसकी रणनीति में भी तब्दीली आएगी या फिर आपातकालीन हालत दोहराते हुए वह और अधिक अहंकारी एवं अतार्किक हो जाएगी. यह देश के लिए बहुत दु:खद बात होगी. देखते हैं, क्या होता है? ■

feedback@chauthiduniya.com

अंततः छविराम मारा गया-5

आपराधिक जीवन का मिथक

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

छविराम लगभग चालीस वर्ष पहले मैनपुरी ज़िले के कुरावली थाना अंतर्गत हरिनागरपुर गांव में निरंजन यादव के घर पैदा हुआ था. उसकी शिक्षा कक्षा सात तक हुई, पर ग़लत साथ हो जाने के कारण उसने पढ़ना-लिखना छोड़ दिया तथा राहजनी करने लगा. उस समय यादवों में जरमन हीरो बना हुआ था. छविराम उसी के गिरोह में शामिल हो गया. जरमन के मारे जाने के बाद गिरोह का नेता अलवर हुआ. छविराम तब तक काफी सक्रिय हो चुका था. अलवर के मारे जाने के बाद वह नंबर दो पर रहा तथा काशी की मृत्यु के बाद उसने पोथी से मिलकर एक संयुक्त गिरोह बना लिया. पोथी बेहटी गांव, थाना कलां, ज़िला शाहजहांपुर के चिरौंजी अहीर का लड़का था. छविराम-पोथी गिरोह काफी कुख्यात रहा.

इस गिरोह के पास सामान्य हथियारों के अतिरिक्त एलएमजी, एसएलआर, थ्री नॉट थ्री राइफल, सेमी ऑटोमेटिक राइफल, स्टेनगन, थर्टी कारबाइन जैसे घातक हथियार थे. इस सूचीबद्ध गिरोह ने मैनपुरी, एटा, फतेहगढ़, बदायूं व शाहजहांपुर ज़िलों में हत्या, डकैती, लूट व अपहरण के 140 से ज़्यादा अपराध किए. 15 अक्टूबर, 1977 को इस गिरोह ने मुखबिरी के संदेह में पांच व्यक्तियों को एटा ज़िले के जैथरा क्षेत्र में काली नदी में डुबा कर मार डाला. 19 नवंबर, 1979 को मैनपुरी के औंछा थाने के बदनपुर गांव में इस गिरोह ने 11 हरिजनों को गोली से भून दिया, इनमें पांच महिलाएं भी थीं. दिसंबर, 1979 में एटा ज़िले के सकीट थाना अंतर्गत गठकोई गांव में सात व्यक्तियों की हत्या इसी गिरोह ने की थी. मई, 1981 में जैथरा थाना अंतर्गत कुंअरपुर गांव के 11 हरिजनों की हत्या में भी इसी गिरोह का हाथ था. अगस्त, 1981 में एटा ज़िले के अलीगंज थाना अंतर्गत नथुआपुर गांव में सनसनीखेज डकैती व हत्या तथा अक्टूबर, 1981 में मैनपुरी के औंछा थाना अंतर्गत फकीरपुर गांव में पांच महिलाओं सहित 12 ठाकुरों की हत्या व लूटपाट छविराम द्वारा की गई. इस गिरोह ने फिरौती के लिए दो दर्जन से अधिक अपराध किए. बाद में महाबीरा, पोथी तथा अनार सिंह अपना-अपना अलग गिरोह बना लिया, पर निर्देशन वे छविराम से ही लेते रहे.

पुलिस को इस गिरोह के कारण कई बार भारी क्षति उठानी पड़ी. नौ मई, 1981 को मैनपुरी ज़िले के घिरोर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मुंशीलाल शर्मा व पांच कांस्टेबिल मारे गए. 29 मई, 1981 को आगरा ज़िले के पिनाहट थाना क्षेत्र में इस गिरोह से मुठभेड़ में कांस्टेबिल श्रीपत राम व कांस्टेबिल शिव सिंह ने वीरगति पाई. 17 अगस्त को एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में इंस्पेक्टर राजपाल सिंह सहित पुलिस के नौ जवान व तीन ग्रामीण शहीद हुए थे. उत्तर प्रदेश पुलिस ने 90 सदस्यों के इस गिरोह के 34 डाकुओं का सफाया करने तथा 12 डाकुओं को पकड़ने का दावा 1981 में किया था. मारे गए डाकुओं में रघुवीरा पर चार हज़ार, कुंदन उर्फ टोढ़ी व मेहताब पर दो-दो हज़ार, जयवीरा, कलक्टर व रक्षपाल पर डेढ़-डेढ़ हज़ार तथा चरन सिंह पर एक हज़ार रुपये का इनाम था. राम औतार, राजेंद्र, दुर्योधन, देवी दयाल, छेदालाल, मिलाप सिंह महराज, नरेश, शंकर, यदुनाथ, सोनपाल तथा जबर सिंह गिरफ्तार किए गए. इस वर्ष पुलिस ने गिरोह के प्रमुख सदस्य शिवराज उर्फ नेता को मौत के घाट उतार दिया तथा मेदेव, वीरा, पुरुषोत्तम तथा शेर सिंह को दबोच लिया.

छविराम इस क्षेत्र में सबसे अधिक दिन ज़िंदा रह पाने वाला दस्यु सरदार था. उसे ही पहली बार जन-सम्मान भी मिला. यहां अब तक डाकुओं की ज़िंदगी औसतन तीन साल की रही है, लेकिन छविराम आठ साल से ज़्यादा जीवित रहा तथा कभी उसने अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा. उसके क्षेत्र में न जंगल है, न बीहड़ है, न बड़े नदी-नाले हैं. समतल ज़मीन है, खेत हैं, ऊसर हैं, गांव हैं. फिर भी छविराम को पकड़ना मुश्किल था. जनता उसका कितना सम्मान करती थी, इसका सुबूत यह है कि जब छविराम की तलाशी ली गई, तो कर्मवीर सिंह को बहुत-सी दरख्वास्तें मिलीं, जिनमें प्रार्थना की गई थी कि नेता जी उनके कष्टों का निवारण करें. तलाशी में शादी, तिलक तथा पूजा-पाठ के समारोहों में साथियों सहित आने के निमंत्रण भी मिले. छविराम के मरने के साथ ही उन सब मिथकों का अंत हो गया, जो छविराम के साथ जुड़े थे. छविराम को यदुवंश के सितारे तथा कृष्ण के बाद दूसरे उद्धारक व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता था. माना जाने लगा था कि छविराम को दैवीय शक्ति का वरदान प्राप्त है. मैनपुरी में किसी ने यह नहीं कहा कि डाकू मारा गया, उनके शब्द थे-नेता मारे गए. जब पुलिस लाश के पास से लोगों को भगा रही थी, तो एक नौजवान लाठी खाने के बाद बोला, नेता, जियत हते, तबों लाठी खबाई, मरेऊ पै पिटवाय रओ औ.

छविराम इस क्षेत्र में सबसे अधिक दिन ज़िंदा रह पाने वाला दस्यु सरदार था. उसे ही पहली बार जन-सम्मान भी मिला. यहां अब तक डाकुओं की ज़िंदगी औसतन तीन साल की रही है, लेकिन छविराम आठ साल से ज़्यादा जीवित रहा तथा कभी उसने अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा. उसके क्षेत्र में न जंगल है, न बीहड़ है, न बड़े नदी-नाले हैं. समतल ज़मीन है, खेत हैं, ऊसर हैं, गांव हैं. फिर भी छविराम को पकड़ना मुश्किल था.

एक और फूलन?

झगड़ा मुरारी व भूरा के बीच था, जिसमें मुरारी, उसका बेटा ओम प्रकाश, छोटी बेटी तथा पत्नी मारे गए. बच गई मुरारी की बड़ी बेटी ओमवती, उसकी भाभी तथा ओम प्रकाश की चार साल की लड़की. ओमवती को भूरा 19 फरवरी की रात अंडरवियर व बनियान में ही ले भागा तथा उसके साथ बलात्कार भी किया. बाद में छविराम ने छुड़वा दिया. ओमवती एटा के स्वामी प्रकाशानंद की शिष्या थी. उसकी शिक्षा आठवीं तक हुई थी. उसके बाद उसने पढ़ना छोड़ दिया था, क्योंकि उसका पिता चाहता था कि वह आगे गुरुकुल में ही पढ़े. पिता ने ही पूजा-पाठ करना भी सिखाया, लेकिन भूरा ने उसकी ज़िंदगी में उथल-पुथल ला दिया. ओमवती अभी पुलिस के संरक्षण में है. ओमवती की पारिवारिक संपत्ति साठ बीघा ज़मीन है, पर उसकी विधवा भाभी नहीं चाहती कि वह वापस घर जाए. भाभी के पिता बल्लमपुर आ चुके हैं. वह चाहते हैं कि ज़मीन बेचकर अपने घर चले जाएं तथा अपनी लड़की की दूसरी शादी कर दें. ओमवती का अपने गांव में रहना ख़तरनाक भी है, क्योंकि भूरा अभी तक ज़िंदा है. ओमवती जवान है, सुंदर है तथा इस छोटी उम्र में पुरुष अत्याचार से परिचित भी हो चुकी है. पुलिस वाले भी उसकी अनुभव राशि में कुछ न कुछ वृद्धि करेंगे ही. इस तरह ज़िंदगी ने ओमवती को एक दोराहे पर ला खड़ा किया है. एक रास्ता समाज की ओर जाता है, दूसरा जंगलों की ओर. देखना है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, समाज की हालत और देश की महिला संस्थाएं उसे समाज में सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर देने की कोशिश करती हैं या नहीं. यदि ऐसा नहीं होता, तो साल-दो साल में देश को एक और फूलन देवी मिल जाने की पूरी संभावना है, जिसका नाम होगा, दस्यु-सुंदरी ओमवती.

(21 मार्च, 1982) ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

मीडिया को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए

अब आतंकवाद को लेकर बहस चल रही है और टाइगर मेमन का नाम किसी न किसी बहाने हमारे बीच आ रहा है. याक़ूब मेमन की फांसी से सवा घंटे पहले टाइगर मेमन ने अपनी मां से बातचीत की और मुंबई पुलिस का दावा है कि उसने वह रिकॉर्डिंग सेव कर रखी है. टाइगर मेमन आज के इस आधुनिक युग में अगर किसी रिश्तेदार के साथ फोन पर बातचीत करे और वह रिश्तेदार उसकी मां से या उसके घर वालों से बातचीत करा दे, यह असंभव तो नहीं और ऐसा पिछले बीस वर्षों में कितनी बार हुआ होगा, पता नहीं. लेकिन, अचानक हमारे टीवी चैनल और सोशल मीडिया के लोग इतने मासूम बन जाते हैं कि उन्हें लगता है कि बीस वर्षों में टाइगर मेमन ने सिर्फ़ एक बार अपनी मां से उसके फोन पर बातचीत की. कोई भी किसी के फोन से, किसी के नौकर के ज़रिये बात कर सकता है और वह जहां से फोन कर रहा है, दुनिया के किसी भी हिस्से से, ज़रूरी नहीं कि अपने नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल से फोन करे, पर हम इसे एक बड़ी ख़बर बना रहे हैं.

दूसरी बड़ी ख़बर उधमपुर में ज़िंदा पकड़े गए 22 वर्षीय युवक की है, जिसके कई नाम सामने आए हैं. हम उसके पहले नाम कासिम का इस्तेमाल करते हैं. कासिम लोगों के सवालों के जवाब हंस-हंस कर दे रहा है, उसके चेहरे पर पकड़े जाने की कोई शिकन नहीं है. वह यह भी कहता है कि उसे लोगों को मारने में मजा आता है. वहां बैठे लोग पूछते हैं, तुम हिंदुस्तान ट्रेन से आए या बस से? तो वह कहता है, ट्रेन और बस यहां आती होती, तो मैं उसी से आ जाता, पर मैं तो जंगल-जंगल आया. अब रोज़ एक नई ख़बर उसके बारे में उड़ रही है. पर चिंता की बात यह नहीं है. इसमें एक ही चिंता की बात है कि किसी भी आतंकवादी को पकड़ कर हम उसका तत्काल लाइव डेमोंस्ट्रेशन सारी दुनिया के सामने करते हैं, तो हम अपना केस वहां थोड़ा कमज़ोर कर लेते हैं. अगर हम दुनिया के सामने सिर्फ़ यह कहते कि एक व्यक्ति पकड़ा गया और फिर उससे सारी जानकारी लेने के बाद उसे दुनिया के सामने लाते, उसके बयान के साथ, तो शायद हमें ज़्यादा फ़ायदा होता, पर कासिम के केस में ऐसा नहीं हुआ.

चिंता की बात यह है कि जैसे ही टेलीविजन के ऊपर बहस शुरू हुई, पाकिस्तान के पत्रकारों ने कहा कि जिस व्यक्ति को आपने पकड़ा है, वह पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि उसके मुंह से निकली भाषा खालिस उर्दू नहीं है. पंजाब के जितने मुसलमान हैं, वे खालिस उर्दू नहीं बोलते, पंजाबी मिश्रित उर्दू बोलते हैं, जैसे हिंदुस्तान में बोलते हैं. कासिम बता रहा है कि वह पंजाब से जुड़ा हुआ है और उसके भाई किसी स्कूल में पढ़ाते हैं. उसके पिता का इंटरव्यू आया कि उन्हें अपनी और अपने परिवार की जान का ख़तरा है, क्योंकि आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना उनके ऊपर नज़र गड़ाए हैं. यह भी चिंता की बात ज़रूर है, लेकिन यह पाकिस्तान के अंदर का मसला है. चिंता की बात पत्रकारों के बीच की है. जिस तरह से टेलीविजन के ऊपर बहस शुरू हुई, उसमें पाकिस्तान के पत्रकार अपने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बन गए और हिंदुस्तान से जो लोग बहस कर रहे थे, खासकर टेलीविजन के एंकर, उनकी भाव-भंगिमा देखकर ऐसा लग रहा था, मानो वे तत्काल पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की सलाह भारत सरकार को दे रहे हों. उनके हाव-भाव से ऐसा लगा रहा था, चूंकि दो लोगों ने हमला किया, जिसमें हमारे बीएसएफ के दो जवान मारे गए और 20-25 घायल हुए, इसलिए हमें तत्काल पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल देना चाहिए.

मेरे मन में एक सवाल उठता है कि क्या दुनिया या भारत और पाकिस्तान तनाव के उस बिंदु पर पहुंच गए हैं कि कोई एक अफ़वाह उड़ा दे और हम युद्ध कर डालें. अक्सर भारत में सांप्रदायिक दंगों की वजह ऐसी छोटी-छोटी चीजें होती हैं. छोटी चीजों का मतलब यह कि अफ़वाह फैलती है कि किसी एक धर्म के लड़के की साइकिल दूसरे धर्म के लड़के की साइकिल से टकरा गई, गाली-गलौच हुआ और फिर मामला सांप्रदायिक तनाव में बदल गया. ऐसी घटनाएं बहुत सारे सांप्रदायिक दंगों की जड़ में दिखाई दीं. क्या कोई एक संगठन, 10-12 लोगों का संगठन हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में, वह इतनी क्षमता रखता है कि एक ऐसी घटना को अंजाम दे, जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध हो जाए. और, युद्ध होने की स्थिति में पाकिस्तान कहे कि हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं, बम छोड़ देंगे और हिंदुस्तान भी कहे कि हम परमाणु शक्ति संपन्न हैं, बम छोड़ देंगे. पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही हलवा नहीं हैं. आज के जमाने में जबकि तकनीक अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, तब यह सोचना कि एक ऐसी घटना दंगा कराने की जगह दो देशों में युद्ध करा सकती है, अफ़सोसनाक नहीं, तो क्या है?

मीडिया, जिसके ऊपर दोनों देशों के बीच तनाव घटाने की भी ज़िम्मेदारी है, वह तनाव घटाने की जगह दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा रहा है. अच्छा तो यह होता कि मीडिया ऐसे सवालों के ऊपर भारत और पाकिस्तान के प्रबुद्ध नागरिकों की एक-दूसरे के मुल्क में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराता और बात कराता. पाकिस्तान के हमारे सिविल सोसायटी के दोस्त फोन करके बताते हैं कि उनका समाज किस तरह आतंकवाद से पीड़ित है और अक्सर कहीं न कहीं दहशतगर्द या आतंकवादी कोई न कोई शिगूफा छोड़ देते हैं, जिससे वहां के लोगों की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाती है. लड़कियों का स्कूल जाना तो मुसीबत है ही. यह माहौल पूरे पाकिस्तान में पता नहीं क्यों बन गया कि लड़कियों की शिक्षा इस्लाम के ख़िलाफ़ है? इसके बावजूद पाकिस्तान के लड़कियों के कॉलेज ज़िंदगी से भरपूर हैं, हंसी-कहकहों से भरपूर हैं और वे लोग उन सवालों को बहुत ज़्यादा नहीं मानते, जिन्हें हमारे तथाकथित धार्मिक ठेकेदार सवाल बनाकर खड़ा करते हैं. हिंदुस्तान से जो लोग पाकिस्तान जाते हैं और जो लोग वहां के शिक्षा संस्थानों में जाते हैं, उनके अनुभव ऐसे ही हैं. पहले तो वहां के बच्चे, खासकर स्कूलों एवं कॉलेजों में पढ़ने वाले वे सवाल दागते हैं, जो पाकिस्तान सरकार वहां के मीडिया के ज़रिये लोगों के दिमाग में घुसाती है. पर जैसे ही उन सवालों पर बातचीत होती है, दोनों ओर की हंसी-कहकहे एक जैसे हो जाते हैं.

पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक फर्क और है. वह फर्क है कि अगर पाकिस्तान में किसी को यह पता चले कि फलां शख्स हिंदुस्तान से आया है, तो वे उसकी इतनी आवभगत करते हैं कि क्या कहने! वहां के दुकानदार बहुत सारी जगहों पर तो पैसे लेते ही नहीं और जहां पैसे लेते हैं, वहां सिर्फ़ लागत लेते हैं. यह स्थिति आज भी है, जब मैं ये बातें लिख रहा हूं. दूसरी तरफ़ हिंदुस्तान की सिविल सोसायटी के लोग किसी भी क़ीमत पर पाकिस्तान से लड़ाई नहीं चाहते, क्योंकि

चिंता की बात यह है कि जैसे ही टेलीविजन के ऊपर बहस शुरू हुई, पाकिस्तान के पत्रकारों ने कहा कि जिस व्यक्ति को आपने पकड़ा है, वह पाकिस्तान का नहीं है, क्योंकि उसके मुंह से निकली भाषा खालिस उर्दू नहीं है. पंजाब के जितने मुसलमान हैं, वे खालिस उर्दू नहीं बोलते, पंजाबी मिश्रित उर्दू बोलते हैं, जैसे हिंदुस्तान में बोलते हैं. कासिम बता रहा है कि वह पंजाब से जुड़ा हुआ है और उसके भाई किसी स्कूल में पढ़ाते हैं.

उन्हें लगता है कि लड़ाई होने की स्थिति में सिर्फ़ दो-चार लोग नहीं मरेंगे, ग़रीबों के परिवारों के हज़ारों जवान शहीद हो जाएंगे. वह शहादत हिंदुस्तान की तरफ़ से भी होगी और पाकिस्तान की तरफ़ से भी, लेकिन नतीजा किसी को कुछ मिलेगा नहीं. पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ जैसे लोग हैं, जो कहेंगे कि करगिल हमने जीत लिया और भारत करगिल की हार पचा नहीं पा रहा है, जबकि हम सुबूतों के साथ कहेंगे कि करगिल हमने जीता और पाकिस्तान को पीछे खदेड़ दिया. हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह, सिविल सोसायटी को लगता है कि ये चीजें मीडिया के लिए ठीक हैं, लोगों को भरमाने के लिए ठीक हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं है. बल्कि सच्चाई यह है कि उस लड़ाई से हिंदुस्तान को भी बहुत नुक़सान हुआ और पाकिस्तान को भी. और, दोनों की विकास की गति धीमी पड़ी.

आज ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी भारत और पाकिस्तान के मीडिया की है कि वह चीजों को भावनात्मक तरीके से न देखकर वास्तविक तरीके से देखे और ऐसे लोगों को पिन प्वाइंट करे, जो चाहते हैं कि दोनों देशों में लड़ाई हो और किसी भी एक घटना को लड़ाई का केंद्र बना लें. कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करती है कि वह पहले कहती थी कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो अब पत्थर क्यों नहीं चलाती, गोलियां क्यों नहीं चलाती, बम क्यों नहीं चलाती? भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ऐसे लोग हैं, जो कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करो. वे यह भूल जाते हैं कि दोनों देशों की लड़ाई क्या-क्या नुक़सान करती है. और आज के जमाने में, जबकि दोनों के पास विनाशकारी हथियार हैं, नुक़सान की कल्पना सहज की जा सकती है. क्या किसी आतंकवादी समूह को यह इजाजत दी जानी चाहिए, विशेषकर मीडिया की तरफ़ से कि वह कोई घटना करे और पूरा मीडिया उसके समर्थन में युद्ध कराने पर उतारू हो जाए. यह बात पाकिस्तान के ऊपर भी लागू होती है और हिंदुस्तान के ऊपर भी.

इसीलिए मैं फिर आतंकवाद की बात पर आता हूं. आतंकवाद एक ऐसा ज़हर है, जिसने दोनों देशों का विकास अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है. राजनीतिक कारण एक तरफ़. पाकिस्तान में क्यों विकास नहीं हो पा रहा है, हिंदुस्तान में विकास की शुरुआत, जिसका वादा प्रधानमंत्री ने किया, अब तक क्यों नहीं हो पा रही है, यह अपनी जगह है. लेकिन, क्या सिविल सोसायटी या मीडिया के लोग युद्ध कराने के पक्ष में तर्क गढ़ेंगे? यही सवाल पाकिस्तान के मीडिया से है कि क्या वह चाहता है कि भारत और पाकिस्तान लड़ें और दोनों तरफ़ के लाखों लोग मर जाएं. हज़ारों मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर कहीं दिमागी संतुलन बिगड़ा और परमाणु युद्ध हो गया, तो दो तिहाई से ज़्यादा पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा और एक तिहाई हिंदुस्तान नष्ट हो जाएगा. और जो बचेंगे, वे लूले-लंगड़े होंगे.

मैं युद्ध से डरने की बात नहीं कर रहा, युद्ध न होने देने की बात कर रहा हूं, क्योंकि मानवता को बचाए रखने की ज़िम्मेदारी जितनी मीडिया की है, सिविल सोसायटी की है, उतनी सरकार और राजनीतिक दलों की नहीं है. अफ़सोस की बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के राजनीतिक दल देश का हित नहीं सोचते. वे अपने प्वॉइंट स्कोर करने के लिए कुछ भी अनाप-शनाप उलूल-जुलूल तर्क गढ़कर सामने आ जाते हैं. उससे भी बड़ा अफ़सोस यह है कि हमारे मीडिया के साथी, चाहे वे हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के, दोनों इस सवाल के ऊपर बिल्कुल एक रुख अपनाते हैं, मारो-काटो, नेस्त-ओ-नाबूद कर दो.

मैं आशा करता हूं कि ईश्वर और अल्लाह दोनों को सद्बुद्धि देगा. पर सबसे बड़ी आशा मैं सिविल सोसायटी से करता हूं, जो इन तर्कों के फेर में नहीं पड़ रही है, इनके जाल में नहीं पड़ रही है. मीडिया की किसी भी उत्तेजक बहस को लोग मनोरंजन की तरह देखते हैं, हक़ीक़त के तौर पर नहीं. यह बात मीडिया को जिस दिन समझ में आ जाएगी, वह मनोरंजन की श्रेणी से निकल कर सचमुच समाचारों की श्रेणी में पहुंच जाएगा. ■

editor@chauthiduniya.com

सजा-ए-मौत को राजनीतिक रंग देती है दया याचिका

मेघनाद देसाई

न्याय क्या है? क्या याक़ूब मेमन और उसके कृत्य के शिकार लोगों को न्याय मिल गया? अपनी मशहूर किताब न्याय के सिद्धांत में न्याय की परिभाषा देते हुए जॉन रावलस लिखते हैं कि न्याय जीवन का अवसर प्रदान (वितरण) करने में निष्पक्षता का नाम है. लेकिन, आम लोगों के एक बड़े तबके में न्याय के कुछ और ही मायने होते हैं. इन लोगों के मुताबिक, किसी अत्याचार या क्षति का प्रतिकार या बदला अन्याय है. लेकिन, जब ओसामा बिन लादेन मारा गया, तो 9/11 के हताहतों के परिवार वालों को लगा कि उन्हें न्याय मिल गया. न्याय रावलस के मुताबिक वितरणात्मक होता है या आम धारणा के मुताबिक विनिमयात्मक या परिवर्तन योग्य होता है. इन दोनों तरह के न्याय पर सवाल उठना लाजिमी है. क्या वितरणात्मक न्याय उचित है? क्या किसी हताहत की तरफ़ से बदले की कार्रवाई करना न्यायसंगत है या आंख के बदले आंख और ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी की मांग करना ग़लत है? यदि हत्या के आरोप में किसी इंसान को फांसी पर चढ़ाया जाता है, तो क्या वह सही है? अगर उस व्यक्ति ने 10 या 100 लोगों की हत्या की हो तो? सौ ज़िंदगियों का बदला एक जान लेकर कैसे लिया जा सकता है? क्या जान के बदले जान लेना सही और न्यायोचित है?

पिछले कुछ हफ्तों से इस सवाल पर हो रही बहस में अलग-अलग मत सुनने को मिल रहे हैं. भारत में रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में सजा-ए-मौत का प्रावधान है. यहां न्यायपालिका सजा-ए-मौत सुनाने में बहुत सावधानी से काम लेती है. इसके बावजूद हमारी व्यवस्था इसमें बाधा उत्पन्न करती रहती है. भारत में राजशाही माफ़ी का एक प्रावधान है. सजायाफ्ता शख्स दया याचिका दाखिल कर सकता है. राष्ट्रपति (या किसी राज्य के राज्यपाल) को अधिकार है कि वह मौत की सजा माफ़ कर सकते हैं. यह अनियमितता ब्रिटिश राज की परंपरा मात्र है. ब्रिटेन ने मृत्युदंड का प्रावधान समाप्त कर दिया है, इसलिए वहां अब राजशाही माफ़ी की आवश्यकता ही नहीं रही. दरअसल, दया याचिका किसी भी मामले को राजनीतिक रंग दे देती है, क्योंकि राष्ट्रपति कैबिनेट के मशविरे पर ही कोई फ़ैसला ले सकते हैं. लिहाज़ा, अप्रत्यक्ष रूप से जो पार्टी या गठबंधन सत्ता में है, वह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में मृत्युदंड के

पिछले कुछ हफ्तों से इस सवाल पर हो रही बहस में अलग-अलग मत सुनने को मिल रहे हैं. भारत में रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में सजा-ए-मौत का प्रावधान है. यहां न्यायपालिका सजा-ए-मौत सुनाने में बहुत सावधानी से काम लेती है. इसके बावजूद हमारी व्यवस्था इसमें बाधा उत्पन्न करती रहती है. भारत में राजशाही माफ़ी का एक प्रावधान है जिसके तहत सजायाफ्ता शख्स दया याचिका दाखिल कर सकता है.

क़ानून से ऊपर है. दया याचिका सजा में देरी या सजा देने या न देने की दुविधा की वजह बन जाती है. लिहाज़ा, ऐसी याचिकाओं को रोके रखकर वोट लेने की ओछी राजनीति शुरू हो जाती है. उसमें अल्पसंख्यक होने का हास्यास्पद बहाना भी सामने आ जाता है, जिसमें यूनानी त्रासदी के सभी तत्व मौजूद होते हैं. याक़ूब के मामले में न्यायपालिका ने उसके द्वारा दाखिल सभी याचिकाओं पर सुनवाई करके अपनी ईमानदारी का सुबूत दिया. न्यायपालिका ने ओछी राजनीति के कारण अपनी साख दांव पर लगाई और खुद मज़ाक का विषय बनने का जोखिम उठाया.

ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि लोकतंत्र में सबकी नज़र वोट बैंक पर होती है. हर वोट बैंक, चाहे वह धर्म के आधार पर हो, भाषा, क्षेत्र, जाति या वंश के आधार पर हो, असुरक्षित अल्पसंख्यक बन जाता है. मौत की सजा का सामना कर रहे किसी मुसलमान या सिख को निर्दोष साबित करने वाले समर्थक मिल जाते हैं. इसी कड़ी में तमिलनाडु विधानसभा राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचने वालों को क्षमा दिलाना चाहती है, क्योंकि वे सभी तमिल हैं. उसी तरह दलित, आदिवासी, जाट या विपरीतलिंगी अपने-अपने समूह के लिए खड़े हो जाएंगे. लिहाज़ा किसी अल्पसंख्यक या फिर किसी भी नागरिक को मौत की सजा देना ग़लत हो जाएगा. अदालत के फ़ैसले को दलगत राजनीति में उलझा कर भारत ने मौत की सजा का राजनीतिकरण कर दिया है. अब समय आ गया है कि दया याचिका को क़ानून की किताब से हटा दिया जाए. उसके बाद इस बात पर बहस होनी चाहिए कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले की बुनियाद क्या हो? कभी-कभी मुझे लगता है कि मौत की सजा के फ़ैसले बहुसंख्यक समुदाय की तरजीह के आधार पर दिए जाते हैं. हालांकि, हकीक़त यह भी है कि आभिजात्य वर्ग पहले से ही मौत की सजा ख़त्म करने की वकालत कर रहा है. मैं भी उसकी राय से सहमत हूं, लेकिन साथ ही मानता हूं कि यह ठीक नहीं है. फिलहाल इस मुद्दे पर अखिल भारतीय पैमाने पर बहस होनी चाहिए और अगले आम चुनाव के साथ जनमत संग्रह कराना चाहिए, ताकि इस मुद्दे पर हम किसी स्थायी समाधान तक पहुंच सकें.

इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह अफ़ज़ल गुरु और बटला हाउस एनकाउंटर पर बहस हुई, उसी तरह याक़ूब को न्याय मिला या नहीं मिला, पर भी बहस जारी रहेगी. यह कहा जाएगा कि मुसलमान भारत में न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते. लेकिन, ज़रा एक और मुसलमान के बारे में सोचिए, जिसकी मौत का मातम हमने पिछले दिनों मनाया. एपीजे अब्दुल कलाम ने दिखाया कि एक ग़रीब मुस्लिम लड़के को भारत क्या दे सकता है. क्या यह न्याय नहीं है? ■

feedback@chauthiduniya.com

एक्स–37 एक अमेरिकी मानवरहित अंतरिक्षयान है. पेंटागन के अनुसार, एक्स–37 बी का उद्देश्य अंतरिक्ष हथियारों का निर्माण नहीं है. एक्स–37 का प्रारंभ नासा ने 1999 में किया था, 2004 में इसे अमेरिकी रक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया. इसकी पहली परीक्षण उड़ान 7 अप्रैल, 2006 को एडवर्ड वायु सैनिक अड्डे पर की गई थी. इस यान की पहली कक्षा में उड़ान 22 अप्रैल 2010 को एटलस–5 से हुई थी.

लो ब्लड प्रेशर ख़तरनाक है

चौथी दुनिया ब्यूरो

जब किसी के शरीर में रक्त–प्रवाह सामान्य से कम हो जाता है, तो उसे निम्न रक्तचाप या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं. सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 होता है. यह आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर–नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर 90 से कम हो जाए तो उसे लो ब्लड प्रेशर यानी निम्न रक्तचाप कहते हैं. अक्सर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, जबकि लो ब्लड प्रेशर में शरीर में ब्लड का दबाव कम होने से आवश्यक अंगों तक पूरा ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिससे अंगों के कार्यों में बाधा पहुंचती है. ऐसे में दिल, किडनी, फेफड़े और दिमाग आंशिक रूप से या पूरी तरह से काम करना भी बंद कर सकते हैं.

लक्षण

लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को आमतौर पर चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना, कुछ पल के लिए बेहोश हो जाना आदि प्रमुख लक्षण हैं.

ऐसे मरीज के हाथ–पैर ठंडे रहते हैं

हार्ट में मिस्ड बीट्स महसूस की जाती है. इस तरह के मरीजों के चेकअप में ब्लड प्रेशर में काफी अंतर होता है. अगर मरीज लेटा हो, बैठा हो और बाद में खड़ा हो, तो उसके ब्लड प्रेशर में काफी बदलाव आ जाता है.

कारण

1. दिल की बीमारी–ब्लड प्रेशर कम होना दिल की गंभीर बीमारी से जुड़ा होता है. दिल की बीमारी से हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे हार्ट पर्याप्त खून को पम्प नहीं कर पाता और हमारा बीपी लो रहने लगता है. दिल के मरीजों और एनीमिया के शिकार लो बीपी को लेकर सावधान रहें.

2. आर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन टाइप– इसमें मरीज को खड़े होने पर चक्कर आते हैं, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर एकदम से 20 प्वॉइंट नीचे आ जाता है. यह नर्वस सिस्टम पर आधारित होता है, लेकिन कई बार ऐसा दवाओं के साइड इफेक्ट से या एलर्जी से भी हो सकता है.

इसके अलावा शरीर के अंदरूनी अंगों से खून बह जाने या खून की कमी से, खाने में पौष्टिकता की कमी या अनियमितता से, लंग या फेफड़ों के अटैक से, हार्ट का वॉल्व खराब हो जाने से लो बीपी हो सकता है. अचानक सदमा लगने, कोई भयावह दृश्य देखने या खबर सुनने से भी लो बीपी हो सकता है.

बचाव

- जब लेटे हों, तो सीधे उठकर खड़े न हों. पहले बैठें, कुछ सेकेंड रुकें, फिर उठकर खड़े हों.
- कम से कम आठ गिलास पानी और तरल पदार्थ रोज पिएं.
- खाने में नमक की मात्रा बढ़ा दें.
- डॉक्टर की सलाह से खाने के साथ एक कप चाय या कॉफी पिएं.
- अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं, तो शराब का सेवन पूरी तरह बंद कर दें.
- अगर खाने के बाद ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो थोड़ी मात्रा में खाएं. दिन में तीन बार से अधिक मात्रा में खाने की बजाए छह बार थोड़ी मात्रा में खाएं. खाने के बाद थोड़ा आराम करें. भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर दें.

इन बातों पर भी ध्यान दें

- पोस्टुरल हाइपरटेंशन सुबह के समय ज्यादा होता है, क्योंकि रातभर में शरीर में सोडियम (नमक) की मात्रा कम हो जाती है.
- पोस्ट प्रनडियल हाइपरटेंशन खाने के बाद होता है. खाना खाने के बाद रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अचानक बढ़ जाती है. ऐसे लोग भोजन में कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करें.
- हाइपरवोलेमिया के कारण भी यह हो सकता है. इसमें तरल पदार्थों की कमी हो जाती है.
- डायलिसिस कराने या डायबिटीज का उपचार कराने से भी यह समस्या हो सकती है.

उपचार

- सबसे जरूरी है कारणों का पता लगाना, ताकि ठीक तरह से उपचार किया जाए. अगर किसी दवा से लो ब्लड प्रेशर हो तो उसकी वैकल्पिक दवाई दी जा सकती है.
- अगर एड्रिनल ग्लैंड के काम न करने से लो ब्लड प्रेशर है, तो आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ेगी.

घरेलू उपचार

- जो लोग लो ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, उन्हें नमक ज्यादा खाना चाहिए.
- अगर आपको लगातार चक्कर आ रहे हों, तो पानी ज्यादा पिएं.
- एक कप शकरकंद का जूस दिन में दो बार पिएं. यह लो ब्लड प्रेशर का सबसे अच्छा घरेलू उपचार है.
- मिट्टी के बर्तन में 32 किशमिश भिगोएं. बर्तन को पानी से पूरा भर दें. सुबह खाली पेट उन्हें एक–एक कर चबाएं, उसके बाद पानी पी लें.
- तुलसी की 10–15 पत्तियों का रस निकाल लें और उसे एक चम्मच शहद के साथ खाली पेट खा लें.
- सात बादाम को रातभर भिगोएं. उसका छिलका उतारकर पीस लें और दूध में थोड़ी देर उबाल लें. इसे गुनगुने रूप में पी लें.

क्या है इलाज

सबसे पहले लो ब्लड प्रेशर की आशंका होने पर लेटकर और खड़े होकर दोनों तरीको से बीपी चेक कराएं. तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाएं. अगर किसी दवा से लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर दवा की मात्रा कम या पूरी तरह बंद कर दें.

पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें. अलग–अलग किस्म के फलों, सब्जियों, अनाज, कम फैट वाले मांस और मछली को भोजन में शामिल करें. कई बार थोड़ा–थोड़ा भोजन करें और खाने में आलू, चावल और ब्रेड जैसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों का प्रयोग कम कर दें. स्मोकिंग से परहेज करें, एक्टिव रहें, ज्यादा पसीना निकालने वाले कामों से बचें, धूप में ज्यादा न घूमें और पर्याप्त मात्रा में नमक खाएं और ज्यादा टेंशन न करें तो लो बीपी से बचा जा सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

जासूसी के अजब-गजब तरीके

जासूसी, दुनिया का सबसे पुराना पेशा है, लेकिन तब और अब की जासूसी का तरीका बदल गया है. आज जासूसी तकनीक पर ज्यादा आधारित हो गई है. जैसे, अपराध के तौर–तरीके बदले हैं, वैसे ही जासूसी के तरीके भी बदल गए हैं. आइए, एक नजर डालते हैं जासूसी के नए तौर–तरीकों पर. अमेरिकी सेना के लिए एक ऐसा जासूसी विमान तैयार किया गया है, जो चमगादड़ जितना बड़ा होगा. यह लड़ाई के मैदानों का जायजा लेकर सेना की मदद कर सकेगा. मिशिगन यूनिवर्सिटी में इसे तैयार करने के लिए अमेरिकी सरकार ने फिलहाल एक करोड़ डॉलर का अनुदान दिया. लड़ाई के मैदानों का जायजा लेने के लिए जहां कॉम–बैट में कैमरों को लगाया जाएगा, वहीं इसमें मौजूद मिनी माइक्रोफोन आवाजों को रिकॉर्ड करने का काम करेंगे. गूगल से जासूसी में भारत का दूसरा व अमेरिका और ब्राजील का तीसरा स्थान है. इंटरनेट यूजर्स अपनी छोटी–बड़ी हर जानकारी के लिए गूगल सर्च का इस्तेमाल करते हैं और जब सरकार लोगों की जासूसी करना चाहती है, तो वह गूगल के अधिकारियों से संपर्क साधती है. यह दुनिया भर में सरकारी एजेंसियों के लिए लोगों की जासूसी करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरी है. बोइंग एक्स 37 अमेरिकी मानवरहित अंतरिक्षयान है. यह अमेरिकी वायुसेना द्वारा पृथ्वी की कक्षा में पुन: प्रयोग किए जाने वाली तकनीकों के प्रदर्शन में उपयोग में लाया गया है. इसकी लंबाई 8.9 मीटर है और इसके पिछले हिस्से में दो पंख लगे हैं. अमेरिका ने इस यान को गोपनीय रखा था, लेकिन विश्व भर में फैले शौकिया खगोल वैज्ञानिकों ने इसे पृथ्वी की कक्षा में देख लिया. शौकिया खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार, इस यान का लक्ष्य अंतरिक्ष से निगरानी तथा सैनिक सर्वेक्षण है. उनके अनुसार, एक्स 37–बी उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान के ऊपर से गुजरा था. यह यान हर चार दिनों में उसी स्थान से गुजरता है. इस यान की कक्षा– 410 किलोमीटर है, जो कि सैनिक सर्वेक्षण उपग्रहों की होती है.

एक्स–37 एक अमेरिकी मानवरहित अंतरिक्षयान है. पेंटागन के अनुसार, एक्स–37 बी का उद्देश्य अंतरिक्ष हथियारों का निर्माण नहीं है. एक्स–37 का प्रारंभ नासा ने 1999 में किया था, 2004 में इसे अमेरिकी रक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया. इसका पहली परीक्षण उड़ान 7 अप्रैल, 2006 को एडवर्ड वायु सैनिक अड्डे पर की गई थी. इस यान की पहली कक्षा में उड़ान 22 अप्रैल 2010 को एटलस–5 से हुई थी. 3 दिसंबर, 2010 को यह यान पृथ्वी पर वापस आया. यह इस यान के उष्मारोध को तथा हायपर्सोनिक एयरोडायनामिक नियंत्रण की पहली जांच थी.

सऊदी अरब के अधिकारियों ने इजरायल की गुप्तचर संस्था मोसाद के लिए जासूसी करने के संदेह में एक बाज को पकड़ा था. इस बाज पर तेल अबीब यूनिवर्सिटी अंकित था. इजरायली डेली माआरिव के मुताबिक, यह पक्षी सऊदी अरब के इलाके में था और इसमें एक ट्रांसमीटर लगा था. पक्षी के पैर पर बंधी एक पट्टी पर तेल अबीब यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था. इस पट्टी से ऐसा लगता है कि यह बाज प्रवासी तकनीक पर लंबे समय से चल रही शोध परियोजना का हिस्सा है, लेकिन स्थानीय लोगों और रिपोर्टरों ने इसे यहूदी जासूसी साजिश बताया है. अरबी भाषा की वेबसाइट पर आरोप लगाया गया है कि यहूदियों ने इस पक्षी को जासूसी के लिए प्रशिक्षित किया है. इसी तरह की एक अन्य घटना में सिनाई क्षेत्रीय गवर्नर ने आशंका व्यक्त की थी कि लाल सागर में कई पर्यटकों को मारने और घायल करने वाली एक शार्क को इजरायली एजेंटों ने इसी काम के लिए छोड़ा होगा. अब सेल फोन से भी जासूसी होने लगी है. जासूसी सॉफ्टवेयर सेल फोन में लग जाता है, फिर जहां भी आप जाते हैं या जिसकी जासूसी करनी हो, उसकी गुप्त सूचनाएं सेल फोन पर निरंतर मिलती रहती हैं.

इसका प्रयोग सर्वाधिक विदेशों में हो रहा है, लेकिन विगत तीन–चार सालों से भारत में भी सेलफोन के जारिए जासूसी के मामले सामने आए हैं.

आइफोन में आप जिन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, वे चुपके–चुपके आपकी जासूसी भी कर सकती है. एक नए अध्ययन में पता चला है कि स्मार्टफोन्स के आधे से ज्यादा प्रोग्राम और गेम्स एक बार डाउनलोड होने बाद निजी कम्पनियों को आप दोबारा डाटा भेज सकते हैं. अध्ययन में 101 एप्लीकेशंस शामिल किए गए, जिसमें देखा गया कि उनमें से 56 किसी न किसी तरह से एक निजी कम्पनी को फोन का नंबर उपलब्ध करा देते हैं. इस प्रक्रिया को युनिक डिवाइस आइडेंटीफायर या यूडीआईडी कहते हैं. समाचार पत्र डेली मेल के मुताबिक, करीब 47 एप्लीकेशंस फोन के स्थान के बारे में जानकारी दे देती हैं, जबकि पांच एप्लीकेशंस उसे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की उम्र, लिंग व अन्य निजी जानकारियां उपलब्ध करा देती हैं. इन एप्लीकेशंस में लोकप्रिय एंग्री बर्ड्स गेम और म्यूजिक सॉफ्टवेयर शैजैम शामिल हैं. प्रत्येक आइफोन में ये दोनों एप्लीकेशंस पहले से ही होती हैं. यह अध्ययन अमेरिका में हुआ था. वाल स्ट्रीट जर्नल द्वारा किए गए इस शोध में कहा गया है कि आइफोन को इस्तेमाल करने वाला किसी भी तरह से इस जासूसी को रोक नहीं सकता है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

मुल्ला उमर की मौत और अफ़ग़ानिस्तान का भविष्य

शफ़ीक आलम

तालिबान नेता मुल्ला मोहम्मद उमर की ज़िन्दगी जितनी रहस्यमय रही, उसकी मौत की खबर भी उतने ही रहस्मय ढंग से बाहर आई. पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में विभिन्न स्रोतों से छन–छन कर यह खबर आई कि मुल्ला उमर मारा गया. इन ख़बरों में यह भी कहा गया कि उसकी मौत आज से दो–तीन साल पहले हो चुकी थी. चूंकि पहले भी कई बार उसकी मौत की ख़बरें आ चुकी थीं, इसलिए अफ़ग़ानिस्तान सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देने से पहले इस खबर की जांच का आदेश दे दिया. इसके समानान्तर यह खबर भी आई कि चूंकि मुल्ला उमर का नाम अब तालिबान के अलग–अलग गुटों को एकजुट रखने में नाकाम हो रहा था, इसलिए पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान सरकार को उसकी मौत की जानकारी दी, जहां से यह खबर बाहर आई. इस खबर की पुष्टि करने में तालिबान ने समय ज़रूर लिया, लेकिन बाद में संगठन द्वारा इस बात को तस्लीम कर लिए गया कि उनका नेता मारा गया है. मुल्ला उमर की मौत और पिछले दिनों इस क्षेत्र का घटनाक्रम अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है.

ख़ुफ़िया सूत्रों के हवाले से छपी रिपोर्टों के मुताबिक, दिसम्बर 2001 में अमेरिकी फौजियों ने मुल्ला उमर को दक्षिणी अफ़ग़ानिस्तान में घेर लिया था. दो–तीन दिन तक उसके प्रत्यर्पण की कोशिशें भी हुईं. लेकिन ये कोशिशें नाकाम हो गईं और मुल्ला उमर अमेरिकियों को चकमा देकर एक मोटर साइकिल पर सवार होकर वहां से भाग निकला था. बाद में अमेरिका ने उसके सर पर 1 करोड़ डॉलर का इनाम रखा, लेकिन उसके बावजूद भी अफ़ग़ान और अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसियों को उसके वास्तविक ठीकाने का कभी पता नहीं चल सका. कभी कहा गया कि वह क्वेटा में है तो कभी कहा गया कराची में है.

बहरहाल, अफगानिस्तान से फरार होने के बाद वह अपने किसी बयान के साथ प्रत्यक्ष रूप से दुनिया के सामने नहीं आया. वह अपने समर्थकों से साल में दो बार ईद और बकरीद के मौकों पर ही कोई पैगाम जारी करता था. अब ये पैगाम उसके अपने होते थे या उसके नाम पर कोई और जारी करता था, यह तथ्य भी रहस्य के परदे में छुपा हुआ है. उसके द्वारा जारी बयानों की प्रमाणिकता पर सवाल उठाना इसलिए भी लाज़मी है, क्योंकि जब उसकी मौत दो–तीन साल पहले हो चुकी थी तो अभी 17 जुलाई को ईद के मौके पर उसके नाम पर जो पैगाम जारी हुआ और पिछले दो–तीन साल से जो पैगाम जारी हो रहे थे, उसके पीछे कौन था? 17 जुलाई को जारी बयान में उसमें अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच मुर्री (पाकिस्तान) में हो रही वार्ता (जिसमें पाकिस्तान अमेरिका और चीन भी शामिल थे और जिसे 2+2+1 का नाम दिया गया था) को समर्थन दिया था. हालांकि इस बयान में ऐसा कुछ भी नहीं था, जो तालिबान के घोषित रुख से अलग था, लेकिन फिर भी यह सवाल उठाना लाज़मी है कि आखिर अफ़ग़ान सरकार से कौन वार्ता कर रहा है और किस अधिकार से कर रहा है?

इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए मुल्ला उमर की शख्सियत के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालना ज़रूरी है.

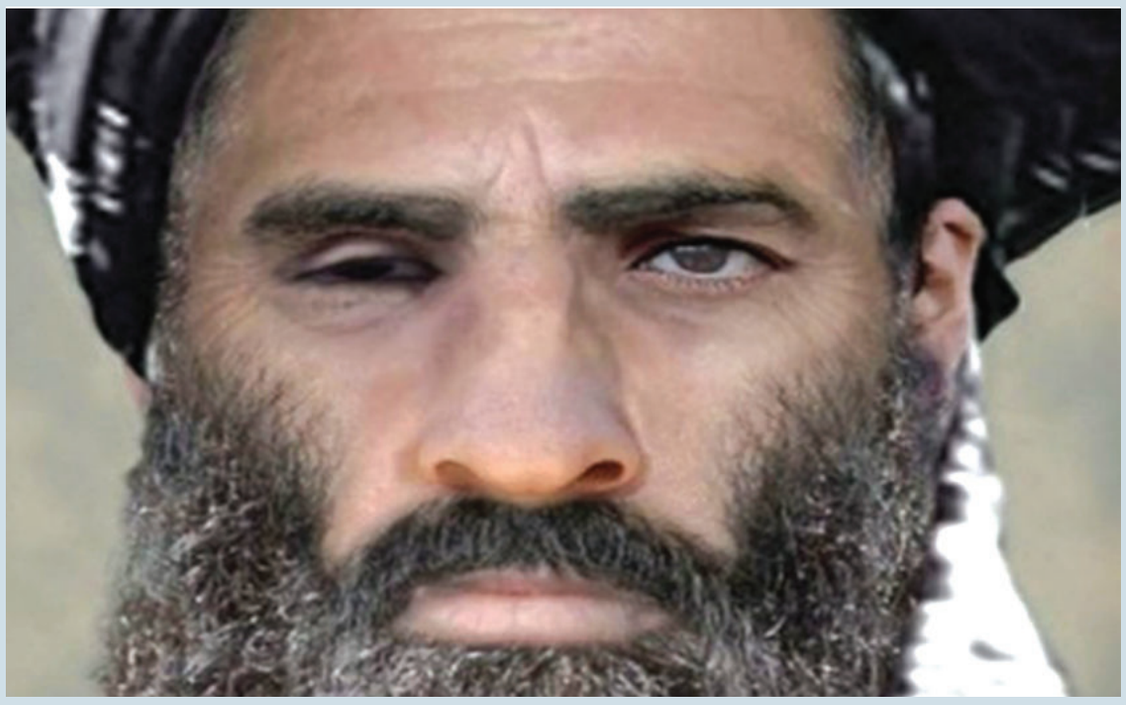

उसके बारे में कहा जाता है कि वह अलग–थलग रहने वाला शर्मीला इंसान था. वह फोटो नहीं खिंचवाता था और ना ही किसी विदेशी पत्रकार को इंटरव्यू देता था. बहुत दिनों तक उसकी एक ही तस्वीर अखबारों में छपती रही, जिसमें वह किसी भीड़ का हिस्सा था. उसके बाद भी जो तस्वीरें आईं, उन पर भी संदेह है कि वो तस्वीरें वास्तव में उसकी हैं या किसी और की. तालिबान पर एक विश्वसनीय किताब तालिबान के लेखक अहमद रशीद कहते हैं कि 1994 के आखिरी दिनों में और 1995 का ज्यादातर समय मैं हाल ही में स्थापित तालिबान आन्दोलन के नेता मुल्ला मुहम्मद उमर के कंदहार स्थित निवास के आसपास भटकता रहा, इस उम्मीद में कि उनका एक इंटरव्यू मिल जाए. मैंने उनके ड्राईवर, सेक्रेटरी, कमांडर्स और यहां तक कि उनका खाना चखने वाले तक से जान–पहचान बना ली, जिनसे मुझे उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलीं, लेकिन उनका इंटरव्यू कभी नहीं मिला.

दरअसल, विदेशी पत्रकार तो दूर, तालिबान लड़ाकों में से बहुत कम को मुल्ला उमर को देखना नसीब हुआ था. शायद इसी वजह से अमेरिका के एक करोड़ डॉलर के इनाम के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल सका. उसकी मौत के बाद भी उसके नाम से फरमान जारी होते रहे और किसी को कोई शक भी नहीं हुआ. जब तक पाकिस्तान स्थित उसके हैंडलरस ने उसकी मौत की जानकारी नहीं दी, उसकी खबर किसी को नहीं हो सकी. ख़ुफ़िया एजेंसियों के हवाले से छपी रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई ने कंदहार से निकाल कर मुल्ला उमर को पहले क्वेटा, फिर कराची में अपने संरक्षण में रखा. वजह साफ़ थी कि पाकिस्तान को मालूम था कि सोवियत फौजों की वापसी और नजीबुल्लाह हुकूमत के खात्मे और तालिबान हुकूमत के दौरान अफ़ग़ानिस्तान में पाकिस्तान के रोल को देखते हुए नई

तालिबान, अमेरिका और अफ़ग़ानिस्तान वार्ता के दौरान कई मौके ऐसे आये, जिसमें तालिबान ने पाकिस्तान को विश्वास में लिए बगैर वार्ता शुरू कर दी. इस दौरान एक समय ऐसा भी आया कि तालिबान के कई धड़े इस वार्ता के खिलाफ हो गए. ऐसे में मुल्ला उमर पाकिस्तान के लिए खास नहीं रह गया था. लिहाज़ा, दो–तीन साल बाद ही सही, इस खबर को अफगानिस्तान सरकार के ज़रिये आम कर दिया गया.

सरकार में पाकिस्तान की वह हैसियत नहीं रहेगी, जो तालिबान हुकूमत के दौरान थी. पाकिस्तान को अफ़ग़ानिस्तान में भारत की दखल को भी रोकना था, इसलिए उन्होंने अमेरिका से युद्ध में तालिबान की हार के बाद भी वो उन्हें बचाए रखना चाहता था. बाद में अमेरिका और तालिबान के बीच वार्ता आरंभ करवाने में भी पाकिस्तान की बहुत ही अहम भूमिका थी, जिसके विस्तार के बाद अफ़ग़ानिस्तान सरकार भी शामिल हुई थी. इसी वार्ता के मद्देनज़र दोहा–क़तर में तालिबान के पॉलिटिकल कमीशन का दफ्तर स्थापित किया गया है.

तालिबान, अमेरिका और अफ़ग़ानिस्तान वार्ता के दौरान कई मौके ऐसे आये, जिसमें तालिबान ने पाकिस्तान को विश्वास में लिए बगैर वार्ता शुरू कर दी. इस दौरान एक समय ऐसा भी आया कि तालिबान के कई धड़े इस वार्ता के खिलाफ हो गए. ऐसे में मुल्ला उमर पाकिस्तान के लिए खास नहीं रह गया था. लिहाज़ा, दो–तीन साल बाद ही सही, इस खबर को अफगानिस्तान सरकार के ज़रिये आम कर दिया गया. इस खबर को आम करने में इतनी सावधानी बरती गई कि पाकिस्तान टीवी ने इस खबर को काफी समय तक नज़रंदाज़ किया. प्राइवेट टीवी चैनल्स ने इस खबर को लिया भी तो बीबीसी के हवाले से किसी पाकिस्तानी हवाले से नहीं.

मुल्ला उमर के बाद

दरअसल, पाकिस्तान ने मुल्ला उमर की मौत की खबर से कई शिकार करने की कोशिश की है. पहली यह कि पाकिस्तान तालिबान खुद के लिए जिस तरह के नतीजों की उम्मीद कर रहा था, वह उसे नहीं मिले और उसे ऐसा लगने लगा है कि उसका हित तालिबान का साथ देने से अधिक अफ़ग़ानिस्तान सरकार से सम्बन्ध सुधारने में है. इसी साल मई महीने में दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों ने एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किये, जिसमें आतंकवाद विरोधी सूचनाएं साझा करने पर सहमती बनी थी. लिहाज़ा, इस खबर से पहले से ही कई गुटों में बंट चुके तालिबान और कमज़ोर हो जायेंगे. कम से कम मुल्ला उमर के नाम पर जो थोड़ी बहुत एकजुटता थी, वह भी ख़त्म हो जायेगी. पाकिस्तान के इस कदम से इस वार्ता में शामिल बाक़ी तीनों पक्ष खुश होंगे.

जैसा कि ऊपर ज़िक्र हो चुका है कि मुल्ला उमर की मौत की खबर से तालिबान अनादोलन कमज़ोर पड़ जायेगा, इसकी झलक भी नज़र आने लगी है. मुल्ला उमर की मौत के बाद जिस तरह आनन–फानन में मुल्ला मुहम्मद मंसूर को नया नेता चुना गया और जिस तरह उसकी नियुक्ति का विरोध हुआ, उससे तो यही साबित होता है. तालिबान आन्दोलन कमज़ोर पड़ चुका है और इसकी एकजुटता अब नहीं रही है, क्योंकि जहां उनका एक धड़ा मुल्ला मंसूर का समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरा धड़ा मुल्ला उमर के खानदान से किसी को नेता बनाने के पक्ष में है. बहरहाल, तालिबान के अन्दरुनी रस्साकशी का जो भी नतीजा हो, लेकिन इस तथ्य में कोई शक नहीं कि तालिबान के बिखर जाने पर भी या फिर से संगठित होने में भी पाकिस्तान की अहम भूमिका होगी. यह आने वाला समय ही बताएगा कि पाकिस्तान कौन सा रास्ता अपनाता है, क्योंकि पाकिस्तान पर न तो अमेरिका को भरोसा है और न ही अफगानिस्तान या तालिबान को. ■

feedback@chauthiduniya.com

लापता मलेशियाई विमान की तलाश पूरी

चीन ने मलेशिया से मलेशियाई एयरलाइंस के दुर्घटनाग्रस्त विमान एमएच 370 (बोइंग 777) की जांच जारी रखने की अपील की. चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दुर्घटना के दिन विमान के साथ आखिर हुआ क्या था, इस रहस्य का पता लगाने के लिए जांच आगे भी जारी रखी जाए. चीन ने यह अनुरोध मलेशिया की ओर से की गई उस घोषणा के बाद किया है, जिसमें कहा गया था कि हिंद महासागर में रीयूनियन द्वीप पर मिला मलबा पिछले 17 महीने से लापता विमामन एमएच 370 का ही है. चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिये गये बयान में मलेशिया से इस दुर्घटना के पीड़ित लोगों के परिजनों के हितों और उनके कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास करने की अपील की है. इससे पहले मलेशियाई विमान एमएच 370 की गुत्थी पिछले दिनों सुलझ गई. विशेषज्ञों ने हिंद महासागर के रीयूनियन द्वीप पर मिले मलबे के मलेशियाई विमान के होने की पुष्टि कर दी है. मलेशिया के प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा कि विशेषज्ञों की एक अंतरराष्टीय टीम ने इस बात की पुष्टि की है कि रीयूनियन द्वीप पर पाया गया विमान का मलबा वास्तव में एमएच 370 का ही है. विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के ठोस सबूत उपलब्ध कराने के बाद इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य का एक अध्याय बंद हो गया, लेकिन अभी भी इसके लापता होने का रहस्य बरकरार है. रज्जाक ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम ने रीयूनियन द्वीप पर मिले मलबे के एमएच370 का होने की पुष्टि की है. विशेषज्ञों ने द्वीप पर मिले विमान के डैनों की पड़ताल के बाद यह पुष्टि की है. मलेशियाई विमान 8 मार्च, 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग जाते समय लापता हो गया था. विमान में यात्रियों और चालक दल के सदस्यों समेत 239 लोग सवार थे.

अब नया हिरोशिमा ऐसा दिखता है

जापान विश्व में उच्च तकनीक के लिए जाना जाता है. ऐसे में इस देश के बारे में यह अनुमान लगाना भी मुश्किल लगता है कि यह देश कभी भयानक त्रादसी से गुजरा भी होगा, लेकिन 70 साल पहले यह देश भयानक त्रासदी से गुजरा था, यह सत्य है. 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिरा दिया था. इस हमले ने 90 फीसदी शहर को तबाह कर दिया था और करीब 1 लाख 40 हजार लोगों की जान ले ली थी. हमले के बाद शहर में सिर्फ एक ही इमारत का ढांचा खड़ा रह गया था. वो अटॉमिक बॉम्ब डोम की इमारत आज भी इस शहर में मौजूद है. जापान और दूसरे देशों के फोटोग्राफरों ने हिरोशिमा की कुछ ताजा तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं, जिसमें त्रासदी के बाद 70 साल में शहर में आए बदलाव को आसानी देखा जा सकता है. इन तस्वीरों में ये शहर पुर्ननिर्माण के बाद ज्यादा रौनक से भरा दिख रहा है. इस समय हिरोशिमा में करीब 12 लाख की आबादी रह रही है.

रूसी गोताखोर नतालिया मोलचानोवा लापता

माइकल शुमाकर जैसे लोगों को जब जिंदगी धोखा दे सकती है, तो किसी के साथ क्या हो जाए, इस पर अचरज नहीं किया जा सकता. कुछ ऐसा ही हुआ पिछले दिनों रूसी गोताखोर चैंपियन नतालिया मोलचानोवा के साथ, जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है. आशंका जतायी जा रही है कि उसकी मौत हो गयी है. बताया जा रहा है कि

53 वर्षीय यह गोताखोर बिजा के पास स्थित स्पेनिश आईलैंड फारमेंटेरा में गोताखोरी के लिए गई थीं, जिसके बाद से वह लापता हैं. ऐसे कयास लगाये जा रहे हैं कि गोताखोरी करने के दौरान उनकी मौत हो गयी होगी, लेकिन इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह गोताखोर चैंपियन थीं और उसने गोताखोरी में कई मेडल हासिल किया है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो नतालिया मोलचानोवा की तलाश के लिए खोजी अभियान जारी है. आशंका जताई जा रही है कि वह समुद्र के नीचे की शक्तिशाली लहरों में फंसकर लापता हो गई हैं. नतालिया के नाम 41 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं. वह पानी के अंदर नौ मिनट तक अपनी सांस रोक सकती थीं और पानी में फिन का इस्तेमाल करते हुए 101 मीटर (331 फीट) गहराई तक गोता लगा सकती थीं. ऐसे में उनके डुबने की खबरें सिर्फ कयास ही साबित हो सकती हैं.

आईएस ने बंधक न्यायाधीश की हत्या की

लीबिया में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) से जुड़े एक गुट ने बंधक न्यायाधीश की हत्या कर दी है. आतंकवादियों ने एक सप्ताह पहले न्यायाधीश को अगवा किया था. यह जानकारी लीबियन ज्यूडिशियल ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले दिनों दी. संस्था ने बताया कि अल–खोम्स अपील न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद अल–नामली पिछले दिनों अल–हरावा कस्बे में मृत पाए गए. उनके शरीर पर प्रताड़ना के निशान थे. संस्था ने आईएस से जुड़े गुट को उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार बताया. अल–नामली को राजधानी त्रिपोली से 450 किलोमीटर दूर सिरते शहर से अज्ञात हथियारबंद गुट ने अगवा किया था, जब वह यहां से होकर गुजर रहे थे. इस गुट के आईएस से जुड़े होने की संभावना है. सिरते शहर से लीबिया डॉन

मिलिशिया के हटने के बाद से यहां आईएस के लिए वफादार आतंकवादी गुट का नियंत्रण है. इससे पहले भी लीबिया में न्यायायिक अधिकारियों पर त्रिपोली, बेनगाजी और डेरना में कई बार हमले हो चुके हैं. लीबिया उत्तरी अफ्रीका का प्रमुख उत्पादक देश है. 2011 में हुए राजनीतिक उथल–पुथल के दौरान पूर्व शासक मुअम्मर गद्दाफी के तख्तापल्ट के बाद से यहां राजनीतिक हालात में अस्थिरता बनी हुई है. ■

feedback@chauthiduniya.com

भैरव को तांत्रिक और योगियों का इष्टदेव माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भैरव छाया ग्रह राहु के देवता हैं. इसलिए वे लोग जो राहु से वरदान पाने की इच्छा रखते हैं, वे भैरव की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं. पुराणों में भैरव को देवी महाविद्या जिनका दूसरा नाम भैरवी भी है उनसे जोड़ा गया है. भैरवी अपने भक्तों को शुद्ध करती हैं, जिससे व्यक्ति के विचार, चरित्र और व्यक्तित्व आदि को शुद्धता मिलती है. शिव महापुराण में वर्णित ब्रह्माजी और भगवाण विष्णु के बीच हुए संवाद में भैरव की उत्पत्ति से जुड़ा उल्लेख मिलता है.

साईं के लिए सभी एक समान हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

बाबा के पास जितने आदमी आए थे, क्या सबने इतना पुण्य किया था कि उन्हें सद्गुरु मिल जाएं ?

सद्गुरु गुणातीत हैं. इसका अर्थ है कि प्रकृति द्वारा बनाए गए जगत के पाप–पुण्य, दुख–सुख, जन्म–मृत्यु आदि गुणों से वे बाहर हैं. उनकी ईश्वरीय प्रकृति में कृपा, क्षमा और धैर्य अथाह परिणाम में होने के कारण चाहे, पापी हो, चाहे पुण्यवान हो– वे दोनों को आकर्षित करते हैं. उनके पास जाकर पापी अपनी पाप–बुद्धि से मुक्त होते हैं और पुण्यवान व्यक्ति और ज्यादा पुण्य करके ईश्वराभिमुखी होते हैं. इसके अलावा सद्गुरु बनने से पहले उनके जितने व्यक्तियों या प्राणियों के साथ जो भी संबध होगा, वे उन सब प्राणियों को ऋण–बंधन के कारण अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनकी अत्यधिक उन्नति करते रहते हैं.

ऐसा क्यों होता है कि बाबा की फोटो देखने से या उनके बारे में पढ़ने से आंखों से आंसू आ जाते हैं, गला कांपता है और शरीर में रोमांच होता है?

जब भी कोई व्यक्ति चाहे प्रथम बार हो, एक ही बार हो या कहीं पर भी हो श्री साईनाथ महाराज को एक प्रणाम करता है, एक भक्ति–भाव देता है, तो वह तत्क्षण सद्गुरु को पता चल जाता है. उसकी भक्ति के भाव के अनुसार सद्गुरु की भी आशीर्वाद–शक्ति की एक सूक्ष्म तरंग उसकी आत्मा को छूती है. एक बार यह संपर्क स्थापित होने के बाद जितनी भी बार उनके

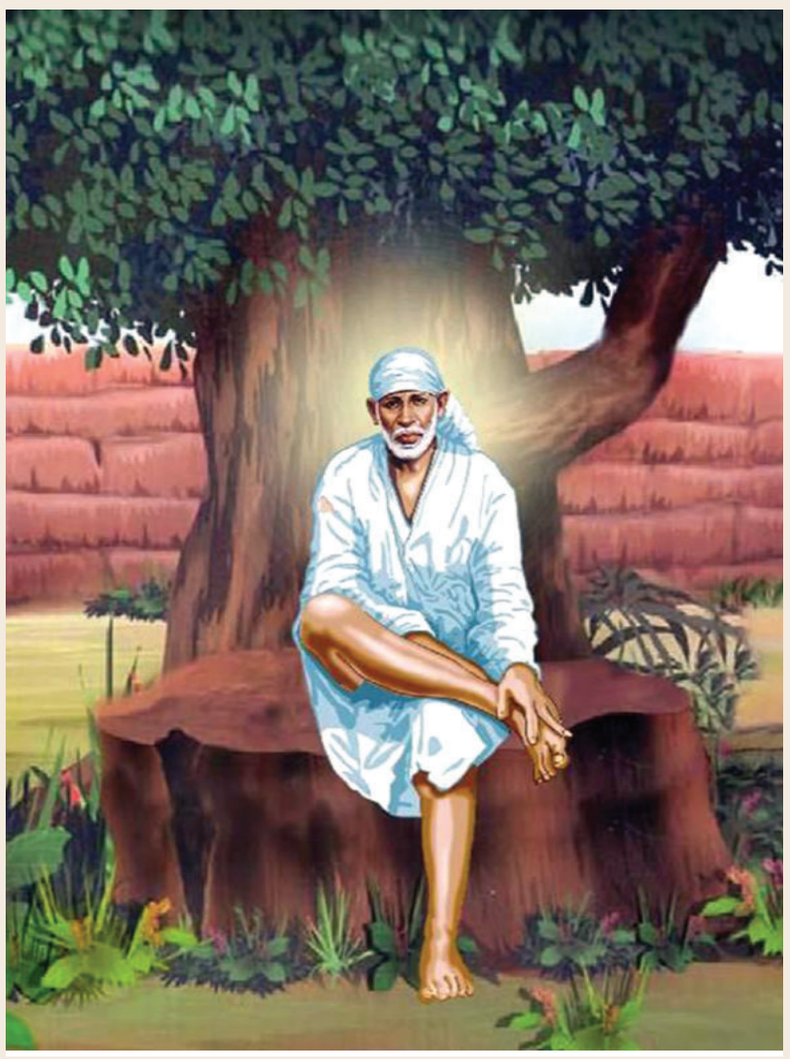

बारे में सोचता है, उस समय उसकी श्रद्धा की गंभीरता जितनी है, उतनी शक्ति या प्राण में संचालित होती है. इस सूक्ष्म शक्ति की तरंग उसके शरीर पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती है, जिन्हें अष्टशक्ति–प्रभाव या सात्विक भाव कहते हैं, जैसे–स्वेद, कंप रोमांच, अश्रु आदि. इस प्रकार की प्रतिक्रिया यदि स्वत: तभी अच्छा है.

बाबा का शिरडी में प्रवास–काल

बाबा साठ वर्षों तक शिरडी की उस जीर्ण–शीर्ण मस्जिद जिसे, द्वारका माई कहते हैं, में क्यों रहे थे ?

चय: देखा गया है कि सद्गुरु जिस जगह पर एक बार ठहर जाते हैं. उस जगह को नहीं छोड़ते हैं. अक्कलकोट महाराज अक्कलकोट में श्री गजानन अवधूत शेगांव में, बाबा ताजुद्दीन नागपुर में, श्री रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में सम्पूर्ण जीवन रहे. यह इसलिए कि एक ही स्थान में रहकर चारों ओर अपना काम करना आसान होता है. लोगों को पहुंचने में आसानी होती है और वह स्थान तप स्थान बन जाता है, जो कि उनके देह त्याग करने के बाद भी माहिमा मंडित रहता है.

बाबा की शिक्षाओं की प्रासंगिकता

आज की दुनिया में बाबा की शिक्षाओं की क्या प्रासंगिकता है?

1–प्राणी–मात्र के प्रति प्रेम–चाहे वे पशु, पक्षी, कीट–पतंग ही क्यों न हो. बाबा स्वयं भोजन ग्रहण करने के पूर्व कुत्तों को खिलाते थे. उन्होंने कपड़े धोने के काम में आने वाली एक व्यर्थ–सी चट्टान पर विराज कर उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट किया. आज भी शिरडी में द्वारकामाई में वह चट्टान देखी जा सकती है. जो भी भक्त वहां जाते हैं. वे उसकी सेवा करते हैं. लोगों को बाबा से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और उनकी शिक्षाओं पर अमल करना चाहिए. आज संसार में बाबा के भक्त इन दृष्टांतों से प्राप्त शिक्षाओं का पालन करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं. लोग गरीबों को खाना–कपड़ा बांटते हुए दिखलाई देते हैं संसार भर में विभिन्न साई–केंद्रों के माध्यम से नारायण सेवा की जा रही है.

2–धार्मिक सहिष्णु–शिरडी साई बाबा ने हिन्दुओं, मुसलमानों एवं अन्य धर्म तथा सम्प्रदाय के लोगों को समान दृष्टि से देखा. आज भी सभी धर्म के लोग बाबा के पास आते हैं. बाबा ने सदैव यह कहा है कि सभी एक हैं और सबसे समान रूप से व्यवहार करो. आज संसार में विभिन्न धर्मों के लोगों में बहुत असहिष्णुता है लोगों को यह समझना चाहिए कि सभी मानव हैं, जिनका मालिक एक ही ईश्वर है लोगों के धार्मिक विश्वास चाहे अलग–अलग हों, लेकिन लक्ष्य तो सबका एक ही है. इस सन्दर्भ में वे आपस में अपने अनुभव बांटते हुए दिखाई देते हैं और घुल–मिलकर प्रेमभाव से बातें करते हैं. वे दृढ़ता से यह विश्वास करते हैं कि तारे अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन प्रकाश तो एक है. इसी प्रकार रास्ते अलग–अलग हो सकते हैं, पर मंजिल एक है.

2–जातिगत मेल–भाव शिरडी साई बाबा ने किसी को भी अस्पृश्य समझे जाने वाले लोगों के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करने दिया. इसका उदाहरण बाबा स्वयं थे. शिरडी में उन्होंने भागोजी को–जो कि एक कोढ़ी थे, सदैव अपने पास रखा उन्होंने ब्राह्मणों को कोढ़ी एवं अन्य अस्पृश्य लोगों के बर्तन में खाना खिलाया. बाबा को जब लगा कि लोग उनके इस प्रकार के कृत्य के प्रति जुगुप्सा(घृणा) का अनुभव कर रहें हैं, तो उन्होंने लोगों को फटकारा और कहा कि सब में आत्मन् है. उनका कहना था कि लोग यदि ऐसे लोगों के प्रति घृणा करते हैं, तो वे वस्तुत: उनके प्रति घृमा कर रहे हैं, क्योंकि वही आत्मन तो आत्मन् तो उनमें भी है. जो लोग बाबा को मानते हैं. उन्हें बाबा के कथनानुसार आचरण करना चाहिए. प्राणिमात्र के प्रति सद्भाव रखना कथनानुसार आचरण करना चाहिए. प्राणिमात्र के प्रति सद्भाव रखना चाहिए एवं आनंदपूर्वक रहना चाहिए. अत: मानव मात्र के प्रति भाई चारे को मानो एवं ईश्वर को अपना पिता जानो. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दु:ख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

यह किताब गुमराह करती है

आदरणीय स्मृति ईरानी जी,
माननीय मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली.

विषय : एनसीपीयूएल के वित्तीय सहयोग से छपने वाली पुस्तक के संबंध में, जिसमें मौलाना आजाद तथा भारत सरकार का चरित्र–हनन किया गया है.

महोदया,

प्रसन्नता का अवसर है कि आपकी अध्यक्षता में नवंबर 2015 में एनसीपीयूएल भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भारत रत्न मौलाना आजाद पर सेमिनार आयोजित करने जा रहा है और इस अवसर पर मौलाना की जीवनी तथा उनके राजनीतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक योगदान पर किताबें प्रकाशित करने का कार्यक्रम है.

मौलाना आजाद जैसे महान नेता एवं राष्ट्रवादी विचारक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के इस सराहनीय कदम का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. लेकिन खेद है कि आप के इसी एनसीपीयूएल ने (उर्दू सहाफत आजादी के बाद) नामक एक ऐसे मसौदे को प्रकाशित करने के लिए 75 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी है, जिसमें जानबूझ कर मौलाना आजाद और भारत सरकार का चरित्र हनन किया गया है.

इस मसौदे पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने पीएचडी की डिग्री दी थी. जिसमें कहा गया है कि मौलाना आजाद का जन्म पश्चिम पंजाब के एक कसबे में हुआ था. जो पाकिस्तान में है जबकि यह सर्वमान्य तथ्य के विरुद्ध एक सफेद झूठ है. मौलाना आज़ाद की मशहूर पुस्तक भारत की आजादी उनके देहांत के 4 साल बाद प्रकाशित हुई थी. लेकिन एनसीपीयूएल के वित्तीय सहयोग से प्रकाशित इस पुस्तक के पृष्ठ 217 पर कहा गया है, कि मौलाना आजाद की विवादित पुस्तक इंडिया विन्स फ्रीडम पर आपकी जिंदगी में पाबंदी से आप टूट गए थे और यह पाबंदी आपकी किताब के 30 विवादित पृष्ठों पर थी, जो 30 साल तक 22 फरवरी 1988 तक जारी रही. यह आजाद भारत की सबसे दर्दनाक घटना थी. यह लेखक की अपनी सोच है, जिसका तथ्यों से कोई संबंध नहीं है.

दुनिया जानती है कि मौलाना आजाद ने प्रकाशक को अपनी किताब के 30 पृष्ठ अपने देहांत के 30 वर्ष बाद प्रकाशित करने की अनुमति दी थी और इंडिया विन्स फ्रीडम पर भारत सरकार की ओर से कभी कोई पाबंदी नहीं लगी थी. इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद मैंने एनसीपीयूएल के भूतपूर्व निदेशक श्री ख्वाजा इकराम को ध्यान दिलाते हुए कार्रवाई की मांग की थी. मैं आपसे उर्दू भाषी समाज की ओर से मांग करता हूं कि उर्दू सहाफत आजादी के बाद नामक इस पुस्तक के लेखक अफजल हुसैन तथा एनसीपीयूएल के निदेशक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भारत का रिकॉर्ड दुरुस्त रहे और लेखक की फैलाई हुई गुमराही आम न हो.

आशा है कि एनसीपीयूएल के वित्तीय सहयोग से प्रकाशित इस गुमराह करने वाली पुस्तक के विरुद्ध आपका मंत्रालय उचित कार्रवाई जरूर करेगा.

धन्यवाद ,

आपका
अज़ीम अख्तर

लोकतंत्र का मजाक उड़ाना बंद करे

बिहार और उत्तर प्रदेश के जातिवादी क्षत्रपों ने सामाजिक न्याय की आड़ में जमकर लूट की. संविधान जाति आधारित राजनीति की अनुमति नहीं देता, लेकिन भारत में जाति एक कड़वी सच्चाई है. चुनावों के समय प्रत्येक दल प्रत्याशियों का चयन जाति के ही आधार पर करते हैं. उदारवादी लेखकों ने अपने साहित्य में जिस जातिवाद को हतोत्साहित किया था, इन जातीय क्षत्रपों ने उसे खूब खाद पानी देकर सींचा है. वंचितों को बराबरी के स्तर पर लाने के लिए संविधान में मात्र 10 वर्ष के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी. जाति आधारित राजनीति करने वाले जातीय जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनकि करने की मांग कर रहे हैं. उन्हें केवल अपनी गरीबी दूर करनी है. असल गरीब को तो ये अपने करीब नहीं आने देते. सामाजिक न्याय के इन झंडाबरदारों से देशवासी पूछें कि बसपा राज में आरक्षण का अधिकांश का लाभ सिर्फ हरिजनों को ही क्यों मिला? पिछड़ी जातियों में आरक्षण का लाभ यादव ही क्यों लूट ले गए? उत्तर प्रदेश में कान्सटेबल भर्ती व पी.सी.एस भर्ती में 70 प्रतिशत सफल अभ्यर्थी केवल एक ही विरादरी के क्यों? अन्य पिछड़ी जातियों व दलितों को इन चालबाज नेताओं का असली चेहरा सामने लाना होगा.

–राज किशोर पाण्डेय, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

सीबीआई जांच राजनीतिक हथकंडा है

व्यापमं भ्रष्टाचार कई सालों से चल रहा था. मुझे नहीं लगता है कि सीबीआई को जांच सौंप देने से सारी सच्चाई सामने आ सकेगी. एसटीएफ अच्छा काम कर रही थी, सीबीआई को जांच सौंपने का फैसला केवल राजनीतिक है. यह कहकर मैं सीबीआई की काबलियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सीबीआई के पास पहले से ही काम का बोझ अधिक है, इस बीच सुप्रीम कोर्ट का दबाव भी अधिक होता है और सीबीआई के पास साधन की भी कमी है. इससे पूर्व राज्य सरकार एसटीएफ से जांच करा रही थी और एसटीएफ ने अच्छा काम भी किया था. हाइकोर्ट एसटीएफ की जांच को मॉनिटर भी कर रहा था, एसटीएफ के पास सीबीआई जितना काम का बोझ भी नहीं था और वो अच्छा काम भी कर रही थी. फिर भी राजनीतिक दबाव के कारण सीबीआई को जांच सौपना कहां तक उचित है?

–आदित्य पाण्डेय, भोपाल, मध्य प्रदेश.

भगवान शिव का भैरव रूप

आदित्य नारायण

श्रावण मास में भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है और श्रावण मास भगवान भोले भक्त कांवड़ में जल भरकर अपने आराध्य शिव का जलाभिषेक करते हैं. ऐसी मान्यता है कि सावन में जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव की अराधना करता है, उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है. आज हम अपनी धर्म की कड़ी में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों के बारे में बताएगें, वैसे तो हिन्दू धर्म में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों का जिक्र किया गया है. पुराणों और शास्त्रों में भगवान शिव के विभिन्न अवतारों का उल्लेख मिलता है. पहले आपको भगवान शिव के भयंकर अवतार, भैरव के बारे में बताते हैं, जिन्हें काशी का रक्षक भी कहा जाता है और भक्त उन्हें अपना रक्षक मानते हैं. भैरव को तांत्रिक और योगियों का इष्टदेव माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भैरव छाया ग्रह राहु के देवता हैं. इसलिए वे लोग जो राहु से वरदान पाने की इच्छा रखते हैं, वे भैरव की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं. पुराणों में भैरव को देवी महाविद्या जिनका दूसरा नाम भैरवी भी है उनसे जोड़ा गया है. भैरवी अपने भक्तों को शुद्ध करती हैं, जिससे व्यक्ति के विचार, चरित्र और व्यक्तित्व आदि को शुद्धता मिलती है. शिव महापुराण में वर्णित ब्रह्माजी और भगवाण विष्णु के बीच हुए संवाद में भैरव की उत्पत्ति से जुड़ा उल्लेख मिलता है. एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्माजी में

इस बात को लेकर बहस हो गई कि इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम रचनाकार कौन है? इस सवाल पर ब्रह्माजी ने स्वयं को श्रेष्ठ बताया. इसे सुनकर भगवान विष्णु के अंदर अहंकार का भाव उत्पन्न हो उठा और क्रोधित हो गए. उसके बाद दोनों देवता चारों वेदों के पास इस सवाल का जवाब जानने के लिए गए. सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुंचे. शिव ही सबसे श्रेष्ठ है, वो सर्वशक्तिमान है और सभी जीवजंतु उन्हीं में समाहित हैं. यही सवाल जब यजुर्वेद से पूछा गया, तो उन्होंने उत्तर दिया यज्ञों द्वारा जिन्हें पूजा जाता है, वही श्रेष्ठ हैं और वो एक मात्र शिव हैं. फिर दोनों देवता सामवेद के पास गए सामवेद ने कहा कि साधक और योगी जिसकी अराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ हैं और वो शिव ही हैं. अथर्ववेद ने कहा कि भक्ति पर चलकर जिसे पाया जा सकता है, जो इंसानों को उनके किए हुए पापों से मुक्ति देते हैं, वह भगवान शिव ही सबसे श्रेष्ठ हैं. इस तरह बह्मा और विष्णु का अहंकार चारों वेदों से पूछने पर भी शांत नहीं हुआ और वे उनके जवाबों पर जोर–जोर से हंसने लगे. इतने मे ही वहां दिव्य प्रकाश के रूप में महादेव प्रकट हुए. शिव को देखकर ब्रह्मा का सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा.

उसी समय भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना कि और काल नाम देकर कहा कि ये काल यानि मृत्यु के देवता हैं और इन्हें भैरव नाम से भी जाना जाएगा. इस पर ब्रह्मा का अहंकार और बढ़ गया और वो हसने लगे. इस पर भैरव ने ब्रह्मा के अहंकार भरे सिर को शरीर से अलग कर दिया. इसके बाद भगवान शिव ने भैरव से सभी तीर्थ स्थानों पर जाने को कहा ताकि उन्हें ब्रह्मा के हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके.

ब्रह्मा का कटा सिर लेकर भैरव विभिन्न तीर्थ स्थानों पर गए, लेकिन उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली. उसके बाद भैरव जैसे काशी पहुंचे, वैसे ही उनका पाप मिट गया. भैरव के हाथ से ब्रह्मा का सिर गिर गया. जिस स्थान पर ब्रह्मा का कटा सिर गिरा था, उसे कपाल मोचन तीर्थ के रूप में जाना जाता है. उस दिन से लेकर अब तक काल भैरव स्थायी रूप से काशी में ही निवास करते हैं और काशी के द्वारपाल के रूप विख्यात हैं. ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति काशी जाता है या वहां रहता हैं, उसे कपाल मोचन तीर्थ स्थान पर अवश्य जाना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

हिंदी प्रेमी कलाम

अनंत विजय

पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन के बाद उन पर कई तरह के लेख लिखे गए. ज्ञान–विज्ञान से लेकर उनके संगीत प्रेम तक. उनके व्यक्तित्व के आयामों पर भी बहुतेरे लेख छपे, लेकिन कलाम साहब की एक खासियत अभी थोड़ी अलक्षित रह गई है. वर्ष 2002 की बात है, कलाम साहब राष्ट्रपति बने ही बने थे. संसद भवन के बालयोगी सभागृह में विश्वनाथ प्रताप सिंह की कविताओं का पाठ आयोजित हुआ था. उस समारोह में चार भूतपूर्व प्रधानमंत्री– खुद विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल एक साथ एक मंच पर मौजूद थे. भव्य कार्यक्रम था. राष्ट्रपति कलाम साहब उस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे थे. कार्यक्रम हिंदी में था. विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी कविताएं सुनाईं और सारे वक्ताओं ने हिंदी में अपना भाषण दिया. कलाम साहब बेहद संजीदगी से सबके भाषण सुनते और समझते रहे. एपीजे अब्दुल कलाम ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की कविताओं पर बहुत अच्छा भाषण दिया था. उनका भाषण सुनकर ऐसा लग रहा था कि एक अहिंदीभाषी ने कितनी मेहनत की होगी, सारी कविताओं और उनके अर्थ–मर्म को समझने के लिए. कलाम साहब जब समारोह से जाने लगे, तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने संतोष भारतीय जी से कहा, तुम कलाम साहब को छोड़कर आओ. जब कलाम साहब वहां से निकले, तो बाहर निकलते ही उन्होंने संतोष भारतीय का हाथ पकड़ा और कहा, यू ऑर्गेनाइज्ड अ वेरी वंडरफुल प्रोग्राम. मैं हैरान था कि एक अहिंदीभाषी कैसे इतनी रुचि के साथ कवि गोष्ठी में न केवल सक्रियता के साथ भाग लेता है, बल्कि हिंदी में आयोजित कार्यक्रम को श्रेष्ठ करार देकर ऐसे और कार्यक्रमों के आयोजन की वकालत करता है. दरअसल, कलाम साहब को हिंदी एवं तमिल से बहुत प्यार था. वह बेहद टूटी–फूटी हिंदी बोलते थे, बल्कि न के बराबर ही बोलते थे, लेकिन हिंदी के प्रति उनका काफी लगाव था. कलाम साहब की हिंदी में बीस से ज़्यादा किताबें प्रकाशित होकर लोकप्रिय हो चुकी हैं. उनकी किताबों के प्रकाशक प्रभात प्रकाशन के निदेशक पीयूष कुमार के अनुसार, जब भी वह कलाम साहब से मिलने जाते थे, तो कलाम साहब अपनी किताब के हिंदी अनुवाद में खासी रुचि लेते थे.

कलाम साहब कहा करते थे कि उनकी मजबूरी है कि वह अंग्रेजी में ही लिखते हैं, लेकिन जब तक उनकी किताब हिंदी और तमिल में प्रकाशित न हो जाए, उन्हें संतोष नहीं होता. कलाम साहब हिंदी में प्रकाशित अपनी किताबों के टाइटिल को लेकर भी खासे सतर्क रहते थे और यह जानना चाहते थे कि

पाठक इस शीर्षक से कनेक्ट होगा कि नहीं. कलाम साहब हिंदी में प्रकाशित किताबों के मूल्य को लेकर भी सजग रहते थे और बार–बार कहा करते थे कि दाम कम से कम होने चाहिए, ताकि वह अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंच सके. पीयूष जी ने एक और दिलचस्प बात बताई कि वर्ष 2000 में जब वह कलाम से मिले और उनकी किताब के बारे में बातचीत हुई, तो बातों–बातों में उन्होंने पूछा, तुम्हारी ईमेल आईडी क्या है? जब पीयूष ने न में जवाब दिया, तो उन्होंने अपने कंप्यूटर पर उनकी मेल आईडी कलामपीयूष के नाम से बना दी. कलाम साहब भाषा के साथ–साथ तकनीक के मेल पर भी जोर देते थे. कलाम साहब के साथ कई किताबें लिखने वाले प्रोफेसर अरुण तिवारी बताते हैं कि कलाम साहब हमेशा कहते थे, तिवारी, जो पुस्तक तुम्हारी मां न पढ़ सके, उसे लिखने का क्या फ़ायदा? मातृभाषा में लिखा साहित्य ही आत्मा को तृप्त करता और छूता है. कलाम साहब तो विज्ञान एवं चिकित्सा की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से कराए जाने के पक्षधर थे. कलाम साहब के साथ अग्नि की उड़ान जैसी किताब लिखने वाले प्रोफेसर तिवारी ने बताया कि एक बार दक्षिण कोरिया से लौटकर आए कलाम साहब वहां की तकनीक एवं चिकित्सा सुविधाओं से काफी प्रभावित दिखे और बोले कि कोरिया ने यह केवल अपनी मातृभाषा के दम पर किया है. कलाम साहब ने तब कहा था कि भारत को भी हिंदी के माध्यम से ऐसा करना चाहिए. तो ऐसे थे हमारे कलाम साहब, जो ग़ैर हिंदीभाषी होते हुए भी भारत के विकास के लिए हिंदी को आवश्यक मानते थे!

कलाम साहब से मेरी दूसरी मुलाकात वर्ष 2013 में हुई थी. मैंने उनकी किताब टर्निंग प्वाइंट की समीक्षा लिखी थी, जो वाणी प्रकाशन से प्रकाशित मेरी किताब विधाओं का विन्यास में संकलित है. मैंने उनसे मिलने का वक्त मांगा. पहले किताब भेजने को कहा गया. मैंने यह सोचकर किताब भेज दी कि शायद उनका दफ्तर देखना चाहता हो कि किताब में कुछ विवादित तो नहीं है. अमूमन बड़ी हस्तियां किताब भेंट में स्वीकारने के पहले प्रति मंगवा लेती हैं. मैं वहां पहुंचा और बातचीत के दौरान उन्हें बताया कि इस किताब में टर्निंग प्वाइंट की रिव्यू है. उन्होंने कहा, यस, आई नो. फिर उन्होंने लेख के शीर्षक राजनीति के टर्निंग प्वाइंट की भी तारीफ़ की और कहा, मेरी ज़िंदगी के टर्निंग प्वाइंट तुमने राजनीति के टर्निंग प्वाइंट बना दिए. फिर उन्होंने मेरे लेख पर थोड़ी देर बात की, किताब में लिखे अन्य लेखों पर भी. मैं हैरान कि हिंदी में लिखे लेखों को उन्होंने कैसे समझा होगा. फिर उस किताब के बहाने वह हिंदी साहित्य पर बात करने लगे. जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी इस किताब में अंग्रेजी में लिखी जा रही किताबों पर लेख है, तो उन्होंने कहा कि मालूम है. कलाम साहब ने अपनी उजली हंसी के साथ कहा, दिस इज वंडरफुल. हिंदी पीपल शुड ऑल्सो नो व्हॉट इज बीइंग रिट्न इन अदर लैंग्वेजेज. मैं क़रीब बीस मिनट की उस मुलाकात के बाद जब बाहर निकला, तो सोचकर हैरान था कि यह शख्स कितना गंभीर है. दरअसल, उनकी किताब टर्निंग प्वाइंट पर हिंदी में लिखी गई पहली समीक्षा मेरी ही थी, उसके बाद इस किताब का अनुवाद हुआ. अभी जब उनके क़रीबी सहयोगी सृजन पाल सिंह से बात हुई, तो पता चला कि हिंदी को लेकर कलाम साहब के मन में गहरा अनुराग था. सृजन पाल ने बताया कि कलाम साहब उत्तर भारत के सैकड़ों दौरे पर रहे होंगे और हर दौरे में वह अपनी स्पीच हिंदी में मुझसे बुलवाते थे, ताकि श्रोताओं को उनकी बात समझने में आसानी हो. अपने भाषण की शुरुआती चार–पांच पंक्तियां हिंदी में बोलने के लिए वह प्रैक्टिस करते थे. सृजन पाल सिंह ने भी इस बात को स्वीकारा है कि हिंदी को लेकर कलाम साहब के मन में गहरा सम्मान था.

दरअसल, कलाम साहब डॉ. राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे, जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन के बड़े–बड़े लोहे के गेट आम जनता और महामहिम के बीच बाधा नहीं बने. राष्ट्रपति भवन बच्चों, युवाओं एवं वैज्ञानिकों के लिए हमेशा खुला रहता था. अपने कार्यकाल के दौरान कलाम ने राष्ट्रपति भवन को देश के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार करने का केंद्र बना दिया था. एक राष्ट्रपति के रूप में कलाम का उद्देश्य जनता का दिमाग उस स्तर पर ले जाना था, जहां एक महान भारत का निर्माण हो सके. राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने अपना एक विजन–पीयूआरए (प्रोविजन ऑफ अरबन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज) देश के सामने पेश किया, जिसके मुताबिक 2020 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र हो जाना है. इन वजहों से उस दौर में लोग राष्ट्रपति भवन को समाज में बदलाव की प्रयोगशाला तक कहने लगे थे. अब्दुल कलाम की किताबें भारतीय प्रकाशन जगत में एक सुखद घटना की तरह होती हैं. हिंदी में भी. एक अनुमान के मुताबिक, विंग्स ऑफ फायर की अब तक दस लाख से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं. कलाम साहब ने राष्ट्रपति रहते हुए सांसदों एवं विधायकों के अलावा देश के नीति नियंताओं के साथ मुलाकात कर विकास की दिशा में आगे बढ़ने की योजनाएं बनाई थीं. वह स्वतंत्रता दिवस पर दिए जाने वाले अपने भाषण को लेकर भी खासे चौकस रहते थे. वर्ष 2005 के स्वतंत्रता दिवस के मौक़े पर दिया गया उनका भाषण 15 बार लिखा गया. इसके अलावा 25 अप्रैल, 2007 को कलाम को यूरोपियन पार्लियामेंट में भाषण देना था. उस भाषण के 31 ड्राफ्ट हुए, जिसके बाद वह फाइनल हो पाया. इससे पता लगता है कि कलाम हर मामले में परफेक्शनिस्ट थे. कलाम साहब वैज्ञानिक सहायक के पद से देश के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे थे. वह सार्वजनिक जीवन में उच्च सिद्धांतों एवं सादगी के प्रतीक हैं और उनका जीवन बहुतों के लिए प्रेरणादायी है. उनका जीवन और हिंदी को लेकर उनका प्रेम हिंदी विरोधियों के लिए एक मिसाल है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

बदरंग व्यवस्था की असली तस्वीर

महेंद्र अवधेश

भला कौन भूल सकता है, 16 दिसंबर, 2012 का वह मनहूस दिन, जिसने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दरिंदगी का एक काला इतिहास रच दिया. देर रात ही सही, लेकिन सड़कों पर फर्राटा भरती बेशक़ीमती कारों में सवार स्वयंभू संभ्रातों के सामने एक युगल लगभग नग्न और गंभीर रूप से घायल अवस्था में मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा. धन्य हैं समीप स्थित किसी होटल के वे अनाम कर्मचारी, जो वहां पहुंचे और उन्होंने उस युगल का तन ढंकने और पुलिस को बुलाने का काम किया. जी हां, हम पैरा–मेडिकल छात्रा निर्भया और उसके उस दोस्त की बात कर रहे हैं, जिन्हें सड़क छाप मानसिकता वाले लोगों, जिनमें बस ड्राइवर, क्लीनर एवं उसके साथी शामिल थे, ने अपनी पाशविकता का शिकार बनाया. कलंक से भी ज़्यादा काली उस रात ने सिर्फ़ दिल्ली को ही शर्मसार नहीं किया, बल्कि पूरे देश को उस सच से अवगत करा दिया, जो तमाम सरकारी आंकड़ों–दावों के ठीक विपरीत है, मुंह चिढ़ाता है. वह सच यह है कि हमारे देश के किसी भी कोने में जन–साधारण की इज्जत, जान, माल सुरक्षित नहीं है. इस घटना ने जितना आम मानस को झकझोरा, उससे कहीं ज़्यादा एक कलाकार, रचनाकार, लेखक, कवि, विचारक को व्यथित किया. नतीजा यह निकला कि तमाम कविताएं सामने आईं, नाटक सामने आए, आलेखों में लेखकों के विचार के रूप में एक अभिभावक की चिंता सामने आई. यानी हर वर्ग ने इस घटना पर अपना दर्द अपने तरीके से बयां किया. तो फिर सैयद जुहैर अहमद जैदी यानी रंजन जैदी कैसे इससे अछूते रहते!

रंजन जैदी रचनाकारों की दुनिया में कोई नया नाम नहीं है. उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले के मूल निवासी और लगभग डेढ़ दर्जन कृतियां रचने वाले सैयद जुहैर अहमद जैदी सारिका कहानी पुरस्कार, साहित्य कृति पुरस्कार–1985, दिल्ली हिंदी अकादमी (85–86) एवं महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं. विभिन्न समाचार–पत्रों एवं पत्रिकाओं में उनके अनगिनत लेखों, साक्षात्कारों एवं समीक्षाओं का प्रकाशन हो चुका है. निर्भया कांड से रंजन जैदी के अंदर का रचनाकार खासा आहत हुआ. नतीजा उपन्यास–वासना के मुर्दाघर के रूप में सबके सामने आया, जिसने सिर्फ़ पीड़ित परिवार

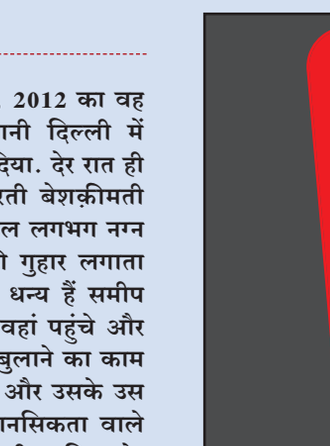

रंजन जैदी

समीक्ष्य कृति
वासना के मुर्दाघर (उपन्यास)
लेखक
रंजन जैदी
प्रकाशक
राजेश प्रकाशन, दिल्ली
मूल्य: 250 रुपये

की ही व्यथा नहीं बयां की, बल्कि कई ऐसे चरित्रों की खूबियों पर रोशनी भी डाली, जिनसे कथित सभ्य समाज दूर रहने में ही अपनी भलाई समझता है. दरअसल, जब कोई रचनाकार किसी कृति का सृजन करता है, तो उसका मकसद यह होता है कि केंद्रीय पात्रों एवं घटनाओं के अलावा वह पार्श्व के उन तमाम चरित्रों, घटनाओं एवं पर्दे के पीछे की उन खूबियों तक ज़रूर पहुंचे, जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है. रंजन जैदी के अनुभव ने उनकी इस कृति में बहुत कुछ अनमोल जोड़ा है, जिसे शायद वह खुद भी महसूस करते होंगे. चंदूबाई, मंजू देवी, कोका, पेटी एवं माली कृति के वे हिस्से हैं, जिनसे समाज के लोग जानते–बूझते हुए भी अनजान रहते हैं और उन्हें अपना हिस्सा नहीं मानते. शायद यही वजह है कि वे उनकी खूबियों, अच्छाइयों, गुणों एवं समाज के प्रति उनके समर्पण को समझ नहीं पाते. और, इसी नासमझी ने हमारे समाज में वह दूरी पैदा कर रखी है कि हमारे अनमोल हिस्से हमारी ज़िंदगी से न चाहते हुए भी दूर हो जाते हैं. बेगम साहिबा, और गिद्ध उड़ गया, हिंसा–अहिंसा जैसे उपन्यास तथा पर्त दर पर्त, नसीरूद्दीन तख्ते खां एवं रूबरू जैसे कहानी संग्रहों के ज़रिये हिंदी साहित्य को धन्य करने वाले रंजन जैदी ने अपने इस नए उपन्यास को उस परिवार पर केंद्रित किया है, जो निर्भया के परिवार जैसी पीड़ा झेलता है. पुलिस ऑफिसर पीटर डिसूजा की बेटी सूजी डिसूजा बिन ब्याहे एक बेटी की मां बन जाती है. दरअसल, उसका प्रेमी माइकल फ्रेजर डॉन शिवा बापड़े और अपने माता–पिता के दबाव में आकर बापड़े की बेटी मारिया से शादी कर लेता है और माइकल एवं मारिया दो बच्चों इला और बबलू के माता–पिता बन बैठते हैं. इधर, सूजी शहर की एक नामी वकील है और पारिवारिक न्यायालय की मनोनीत जज है. सूजी एवं माइकल की संतान मेधावी काबिल–समझदार होने के बावजूद ड्रग्स की लती हो जाती है.

दरअसल, मारिया अपने पति माइकल की प्रेमिका सूजी से बेइंतिहा नफरत करती है. इसीलिए वह उसे बर्बाद करने की साजिश रचती रहती है. इसी क्रम में इला किसी तरह मेधावी को अपनी दोस्त बना लेती है और उसे ऐसी जगह ले जाती है, जहां वह हवस के मारे दो रईसजादों और खुद अपने सौतेले भाई बबलू की पाशविकता का शिकार बन जाती है. बॉलीवुड की दुनिया में अपना एक मुकाम बनाने की हसरत रखने वाली मेधावी अपने सुनहरे सपने साथ लिए, अपनी मां सूजी को अकेला छोड़कर इस संसार से विदा हो जाती है. जैसे निर्भया हमें छोड़कर गई थी. यहां इतना ही बताना पर्याप्त है. जब यह उपन्यास पाठकों के हाथों में होगा, तो वे पढ़ने के बाद रंजन जैदी की पीड़ा और उसे लिखने के दौरान होने वाली कशमकश को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, महसूस कर सकेंगे. अब बाकी फ़ैसला सुधी पाठकों के हाथों में है. ■

mahendra.awdhesh@gmail.com

श्रद्धांजलि

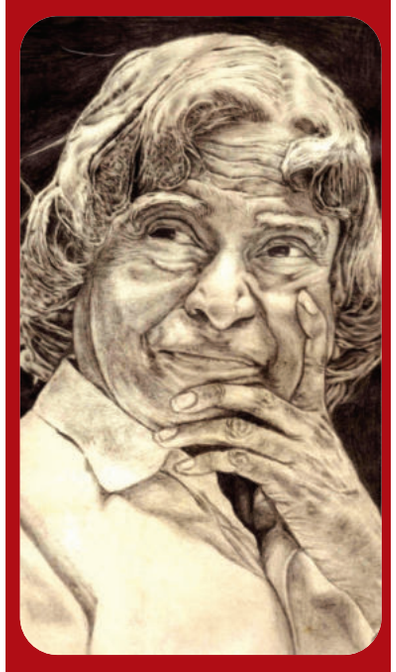

युग पुरुष...शत–शत नमन!
(पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित)

आंखें नम हैं, भारी मन
युग पुरुष...शत–शत नमन.
दुःखी है सारा जन–गन–मन
खो गए वह भारत रत्न.
युग पुरुष...
याद आ रहे सारे राकेट
याद आ रहा पोखरण.
युग पुरुष...
नभ को चीरती मिसाइलें
यादगार सभी भाषण.
युग पुरुष...
द्रवित पूरा राष्ट्र हमारा
स्तब्ध राष्ट्रपति भवन.
युग पुरुष...शत–शत नमन.

–ग़ुलाम क़ुंदनम्

माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले दिनों विंडोज10 को मुफ्त डाउनलोड के तौर पर पेश किया था. यह कंपनी के तीन साल के भीतर एक अरब डिवाइस में विंडोज10 के उपयोग के लक्ष्य से बहुत दूर है. माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह विभिन्न चरणों में सॉफ्टवेयर जारी कर रही है, ताकि आसानी से डाउनलोड सुनिश्चित किया जा सके. अब तक उन सभी पुरानी विंडोज प्रणाली का उपयोग करने वाले उन उपभोक्ताओं को विंडोज 10 मुहैया नहीं कराया है.

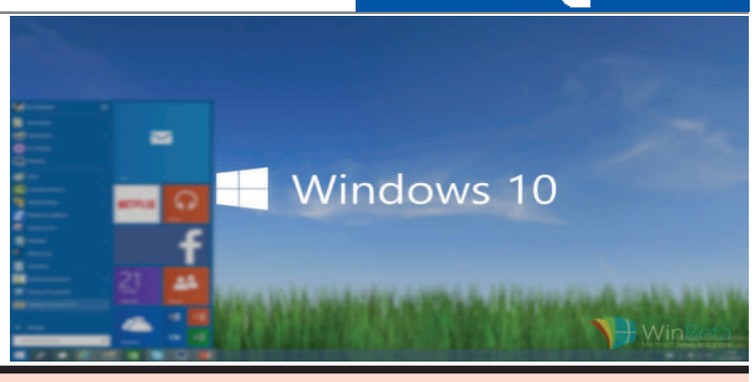

बल्ब से कंट्रोल होते हैं स्मार्टफोन्स

बाजार में ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं, जिनका इस्तेमाल सभी करते है. हालांकि, कुछ ऐसे गैजेट्स भी हैं, जिनके बारे में शायद कम ही लोग जानते हों. ऐसे ही गैजेट्स में एक नाम है स्मार्ट एमआईपीओडब्लू प्लेबल्ब का. यूं तो ये रोशनी करने वाला बल्ब है, लेकिन एमआईपीओडब्लू प्लेबल्ब में ऐसे कई एडवांस फीचर्स हैं. इस बल्ब में बिल्ट–इन स्पीकर भी है, जो नीचे की तरफ दिया है. स्पीकर से आवाज साफ और क्लियर आए, इसके लिए इस बल्ब में जाली दी गई है. सबसे अच्छी बात ये है कि स्पीकर होने के बाद भी इसका साइज दूसरे बल्ब की तरह है. यूजर ऐप के जरिए म्यूजिक को प्ले, पॉज, नेक्स्ट, बैक कर सकता है, साथ ही, वॉल्यूम भी लो/हाई कर सकता है. इतना ही नहीं, यूजर्स मन–मुताबिक बल्ब की रोशनी को बढ़ा और घटा सकता है. इसमें लाइट के लिए चार स्पेशल मोड दिए हैं, जिनमें अलार्म लाइट, सेविंग एनर्जी, नाइट मोड और स्लीप मोड शामिल है. अलार्म मोड की मदद से यूजर्स लाइट और म्यूजिक को अलॉर्म के तौर पर सेट कर सकता है. ऐप की मदद से यूजर्स, बल्ब की रोशनी को अलग–अलग कलर्स दे सकता है. इसके साथ, शेक करके भी लाइट को कम–ज्यादा किया जा सकता है. एमआईपीओडब्लू प्लेबल्ब देखने में किसी साधारण एलईडी बल्ब की तरह होता है, लेकिन इसमें एडवांस वायरलैस कनेक्टिविटी यानी ब्लूटुथ 4.0 फीचर्स दिया है. यूजर्स इसे एप्पल आईफोन, आईपैड, आईपॉड या दूसरे एंड्रॉइड डिवाइस के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकता है. इसके लिए यूजर्स को प्ले स्टोर से एमआईपीओडब्लू का ऐप स्मार्टफोन में इन्स्टॉल करना होगा. इसके बाद इस बल्ब को पूरी तरह ऐप के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है. यानी लाइट्स, स्पीकर जैसे हर फीचर्स पर यूजर की कमांड होगी. इस एमआईपीओडब्लू प्लेबल्ब की कीमत 4,287 रुपए रखी गई है.■

लाखों यूजर्स हैं विंडोज 10 के दीवाने

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि लगभग 1.4 करोड़ से अधिक कंप्यूटर अब उसकी नई विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं. गौरतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले दिनों इसे मुफ्त डाउनलोड के तौर पर पेश किया था. यह कंपनी के तीन साल के भीतर एक अरब डिवाइस में विंडोज 10 के उपयोग के लक्ष्य से बहुत दूर है. माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वह विभिन्न चरणों में सॉफ्टवेयर जारी कर रही है, ताकि आसानी से डाउनलोड सुनिश्चित किया जा सके. अब तक उन सभी पुरानी विंडोज प्रणाली का उपयोग करने वाले उन उपभोक्ताओं को विंडोज 10 मुहैया नहीं कराया है, जिन्होंने इसे मुफ्त अपग्रेड करने की मांग की थी. विंडोज 10 को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है.

मोटोरोला थर्ड जेनरेशन फोन की धूम

मोटोरोला ने अपने बहुचर्चित मोटो जी के थर्ड जनरेशन को लॉन्च किया है. यह डुअल सिम स्मार्टफोन है और 2 वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है. पहले वैरिएंट में 8 जीबी की इंटरनल स्टोरेज है और दूसरे वैरिएंट में 16 जीबी की इंटरनल स्टोरेज क्षमता है. मोटो जी जेन 3 में गोरिल्ला ग्लास 3 का 5 इंच का डिस्प्ले है, जो 720 1280 पिक्सल का रेजोल्यूशन देता है. यह कुछ–कछ जेन2 जैसा ही है. मोटो जेन 3 में इम्प्रुफ्ड 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसमें ऑटो फोकस के साथ लेड फ्लैश भी है और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, जिसमें सेंसर भी है. मोटो जी जेन 3 का मोटो ने प्रोसेसर अपग्रेड किया है, इसमें 64 बिट 1.4 गीगाहर्ट्ज स्नैपड्रैगन 410 क्वाडकोर क्वालकॉम 410 प्रोसेसर से लैस है. साथ ही इसमें 2 जीबी की रैम दी गई है. इस फोन में एंड्रायड लॉलीपॉप 5.1.1 लेटेस्ट आपरेटिंग सिस्टम दिया गया है. मोटो जी जेन 3 कि कॉल क्वालिटी बैहतरीन है और इसमें कम सिग्नल वाले जगह पर भी सिग्नल रहता है. मोटो जी जेन 3 में 4जी की स्पीड अच्छी है और यह फोन बिना रुके जीपीएल लॉक कर सकता है. मोटो जी जेन 3 में 2470 एमएएच की बेहतरीन बैटरी है और 24 घंटे डाटा चालू रखने और स्क्रीन की ब्राइटनेस फुल रखने के बावजूद पूरा दिन आराम से इसकी बैटरी चलेगी. इसकी 8जीबी स्टोरेज क्षमता वाले मोटो जी जेन 3 की कीमत 11,999 रुपये है और 16जीबी स्टोरेज क्षमता वाले मोटो जी जेन 3 की कीमत 12,999 रुपये है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

सोनी एक्सपीरिया की नई सीरीज का धमाका

सोनी ने अपनी एक्सपीरिया सीरीज के ये दो नए फोन एक्सपीरिया सी 5 अल्ट्रा और एक्सपीरिया एम 5 लॉन्च कर दिए हैं. कंपनी ने इन दोनों स्मार्टफोन के अलग–अलग वेरिएंट लॉन्च किए हैं. कंपनी ने इस बार फ्रंट कैमरा पर फोकस किया है, ताकि यूजर्स बेहतर सेल्फी ले सकें. उसने दोनों हैंडसेट में 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया है. एक्सपीरिया सी 5 अल्ट्रा में ये कैमरा एलइडी फ्लैश के साथ और एक्सपीरिया एम 5 बिना फ्लैश के दिया है. इसके साथ, दोनों फोन को उसने वाटरप्रूफ बनाया है. ये दोनों स्मार्टफोन फुल एचडी डिस्प्ले क्वालिटी के साथ आएंगे. सोनी ने अपने एक्सपीरिया सी5 अल्ट्रा हैंडसेट में 6 इंच स्क्रीन दी है, जो फुल एचडी (10801920 पिक्सल रेजोल्यूशन) डिस्प्ले क्वालिटी देगी. ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड के वर्जन 5.0 लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा. इस डिवाइस में 64 बिट ऑक्टा–कोर प्रोसेसर दिया गया है. ये स्मार्टफोन 2जीबी रैम के साथ आएगा. इस हैंडसेट में 16 जीबी इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 200 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ इसमें वीडियो स्टेबलाइजर, ऑटो सीन रिकॉग्नाइजेशन, 22एम एम वाइड–एंगल लेंस (रियर), 80 डिग्री फील्ड व्यू, 4 डिजिटल जूम, फुल एचडी वीडियो, रेड आई रेडक्शन जैसे कई फीचर्स शामिल हैं. इस फोन में ब्लूटूथ, वाई–फाई, माइक्रो–यूएसबी जैसे ऑप्शंस हैं. इसके साथ, इसमें 4जी कनेक्टिविटी भी है, लेकिन ये सभी मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा. सोनी ने इस हैंडसेट में 2930 एमएएच की बैटरी दी है. इनमें सिंगल और डुअल सिम वेरिएंट हैं. उपभोक्ताओं के लिए ये हैंडसेट मिड अगस्त से मार्केट में मौजूद रहेंगे. ■

पूरी तरह वाटरप्रूफ है यह मोबाइल फोन

एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, जो पूरी तरह वाटरप्रूफ है. इस फोन को न कोई तोड़ सकता है और न ही हैक कर सकता है. कंपनी ने इसका नाम ट्यूरिंग फोन रखा है. इस हैंडसेट को 3 वेरिएंट्स (16जीबी, 64जीबी और 128 जीबी मेमोरी) में लॉन्च किया गया है. रोबोटिक इंडस्ट्री ने इस स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट रीडर भी इस्तेमाल किया है. हालांकि इस स्मार्टफोन में यूएसबी पोर्ट और हेडफोन जैक पोर्ट मौजूद नहीं होगा. कंपनी ने इसकी बॉडी जिस मैटेरियल से तैयार की है, वो लिक्विडमोर्फियम है. कंपनी का ऐसा दावा है कि ये एल्युमिनियम और स्टील से ज्यादा मजबूत होता है. इस मटेरियल का इस्तेमाल एप्पल अपने आईफोन 6 की मेकिंग में कर चुकी है. हालांकि, एप्पल ने बेहद कम क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल किया था. इसके साथ, इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए इसके इंटरनल पार्ट्स पर नैनो कोटिंग की गई है. इसमें किसी तरह से रबर का इस्तेमाल नहीं किया गया है और सभी पार्ट्स को आसानी से ओपन भी किया जा सकता है. इस फोन का डिस्प्ले 5.5 इंच का फूल एचडी है. इसमें 2.5 गीगाहर्ट्ज क्वाड–कोर स्नैपड्रैगन 801 प्रोसेसर और 3जीबी रैम होगी. इसमें 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा डुअल लेड फ्लैश के साथ आएगा. वहीं, सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल फ्रंट–फेसिंग कैमरा होगा. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4जी एलडीई के साथ वाई–फाई 802.11एसी, ब्लूटूथ4.0 एलई है. फोन में 3000एमएएच की बैटरी होगी. ■

कीमत–
16 जीबी मेमोरी की कीमत लगभग 39,000 रुपये
64 जीबी मेमोरी की कीमत लगभग 47,300 रुपये.
128 जीबी मेमोरी की कीमत लगभग 55,700 रुपये.

ट्रायम्फ की दमदार बाइक

इंजन की आवाज कम करने के लिए इस बाइक में कई बदलाव किए गए हैं. इसके साथ मोटरसाइकल के गियर बदलना भी आसान बनाया गया है. ट्रायम्फ मोटरसाइकल्स का कहना है कि नई टाइगर मैनर की राइडिंग पोजिशन, हेंडलिंग और रिस्पॉन्सिव इंजन इसे भारत में ऐडवेंचर मोटरसाइकल्स का चहेती बना सकती है. कंपनी का कहना है कि हमारी कोशिश पावर, हेंडलिंग और स्टाइल के शानदार मेल से लैस मोटरसाइकलें बनाना है.

ट्रायम्फ मोटरसाइकल्स ने अपनी टाइगर 800 एक्सआर को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. इस बाइक की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपये रखी गई है. टाइगर 800 एक्स को पिछले मोटरसाइकलों के मुकाबले ज्यादा आरामदेह और रिफाइन मोटरसाइकल बनाया गया है. इसके साथ ही कंपनी ने इसकी फ्यूल एफिशियंसी और टूरिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाया है. इस बाइक में लगा है 800सीसी का थ्री सिलिंडर इंजन, जो अपनी उच्चतम क्षमता पर 94 बीएचपी की पावर देता है. इंजन की आवाज कम करने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं. इसके साथ मोटरसाइकल के गियर बदलना भी आसान बनाया गया है. ट्रायम्फ मोटरसाइकल्स का कहना है कि नई टाइगर मैनर की राइडिंग पोजिशन, हेंडलिंग और रिस्पॉन्सिव इंजन इसे भारत में ऐडवेंचर मोटरसाइकल्स का चहेती बना सकती है. ट्रायम्फ मोटरसाइकल का कहना है कि हमारी कोशिश पावर, हैंडलिंग और स्टाइल के शानदार मेल से लैस मोटरसाइकलें बनाना है. हमारी कोशिश है कि राइडर्स को सवारी का पूरा आनंद आए. एडवेंचर श्रेणी की बाइकों में ट्रायम्फ को खासा पसंद किया जाता है. भारत में इस श्रेणी की मोटरबाइक्स के लिए काफी संभावनाएं हैं. कंपनी ने तीन महीनों में तीसरी बाइक लॉन्च की है. ■

feedback@chauthiduniya.com

> खेल रत्न के लिए पुरस्कार समिति के पास सानिया के अलावा शीर्ष स्क्वॉश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल, गोला फेंक विकास गौड़ा और हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह के नाम की सिफारिशें भी मिली हैं.

खेल रत्न अवॉर्ड की दौड़ में सानिया मिर्जा सबसे आगे

इस वर्ष लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही देश की दिग्गज टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के नाम की सिफारिश राजीव गांधी खेल रत्न के लिए की गई है, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया गया है कि अंतिम फैसला पुरस्कार समिति ही करेगी. खेल सचिव अजित शरण ने कहा है कि खेल मंत्रालय सर्वानंद सोनोवाल ने खेलों में उपलब्धि के लिए सानिया के नाम की सिफारिश सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए की है.

खेल रत्न के लिए पुरस्कार समिति के पास सानिया के अलावा शीर्ष स्क्वॉश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल, गोला फेंक विकास गौड़ा और हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह के नाम की सिफारिशें भी मिली हैं. सानिया ने जून में ऑल इंग्लैंड क्लब में स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर अपने करियर का पहला महिला युगल खिताब जीता था. इससे पहले वह दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी भी बनी थीं. सानिया को 2004 में अर्जुन अवॉर्ड भी दिया जा चुका है. दो वर्ष बाद ही उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया.■

चौहान और महिला तीरंदाजों ने साधा रजत पदक पर निशाना

भारतीय महिला तीरंदाजी टीम विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप का रजत पदक जीतने में सफल रही. रूस ने यह मुकाबला शूट ऑफ में 28–27 से जीता. भारतीय तिकड़ी दीपिका कुमारी, लक्ष्मीरानी मांझी और रिमिल बुरुली महज एक अंक से स्वर्ण पदक से चूक गईं. भारतीय तीरंदाजों ने शानदार शुरुआत करते हुए 4–0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन वे अपनी इस शुरुआत को कायम रखने में नाकामयाब रहीं और अगले दो सेट में विपक्षी टीम से पिछड़ गई. दूसरी सीड भारतीय टीम के खिलाफ तुयाना दशिदोरशिवा, सेनिया पेरोवा और इन्ना स्टेपनोवा की रूसी जोड़ी ने धीमी शुरुवात के बाद बढ़त बनानी शुरू की.

रूसी टीम नौ अंक पर निशाने लगा सकी. दो सेट तक बढ़त बनाने के बाद तीसरे सेट में लक्ष्मीरानी और रिमिल के सात अंक पर निशाना लगाने के कारण भारतीय टीम पिछड़ने लगी. चौथे सेट में दीपिका ने नौ अंक के साथ शुरुआत की, लेकिन लक्ष्मीरानी सात और रिमिल छह अंक ही बना सकी. पांचवे और छठे सेट में भारतीय टीम पिछड़ती चली गई. भारत का इस चैम्पियनशिप में यह दूसरा रजत पदक है. इससे पहले रजत चौहान ने पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम कर इतिहास रचा था. रजत को फाइनल मैच में डेनमार्क के स्टीफेन हेनसेन ने हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया. स्टीफेन ने रजत को 147–143 के अंतर से हराया. रजत वर्ल्ड चैंपियनशिप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कंपाउंड तीरंदाज बन गए हैं. विश्व चैम्पियनशिप में भारत का यह प्रदर्शन अब तक का सर्वश्रेष्ठ है. इस चैम्पियनशिप के जरिए भारतीय महिला टीम ने रियो ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई किया.■

विराट को नहीं छोड़नी चाहिए आक्रामक शैली: द्रविड़

राहुल द्रविड़ को बतौर टेस्ट कप्तान श्रीलंका में पहली पूर्ण श्रृंखला खेलने जा रहे विराट कोहली के कामयाब रहने का यकीन है. उन्होंने कहा है कि कोहली को अपनी आक्रामक शैली नहीं छोड़नी चाहिये. भारत ए के कोच द्रविड़ ने कोहली के मैदान पर बर्ताव के बारे में पूछने पर कहा कि मुझे लगता है कि आपको वही रहना चाहिये, जो आप हैं. इस खेल की खूबसूरती यही है कि इसमें अलग–अलग तरह के लोग कामयाब होते हैं. अधिकांश कामयाब क्रिकेटर आक्रामक रहे हैं. कुछ अधिक आक्रामक होते हैं और कुछ नहीं. कोहली ने भारत ए के लिये दूसरा अभ्यास मैच खेला, जिससे उन्हें द्रविड़ से लंबी बातचीत का मौका भी मिला. श्रीलंका दौरे पर कोहली से अपेक्षाओं के बारे में पूछने पर द्रविड़ ने कहा कि मैं यही कहूंगा कि हर दौरा महत्वपूर्ण है. मुझे नहीं लगता कि इसे अधिक महत्वपूर्ण बनाने की जरूरत है. हर अंतरराष्ट्रीय दौरा अहम है. उसे मेहनत करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराना होगा. कई बार चीजें अनुकूल होती हैं और कई बार नहीं. वे काफी मेहनती हैं और यह अच्छी बात है कि उन्होंने यह मैच खेला. यह अनुभव उनके काम आएगा. द्रविड़ ने इसका खुलासा नहीं किया कि उन्होंने चेतेश्वर पुजारा और कोहली से क्या बात की. उन्होंने कहा कि मैं हर खिलाड़ी के तकनीकी मसलों के बारे में बात नहीं करूंगा. हम पुजारा से लगातार बात कर रहे हैं. कोई बड़ा बदलाव नहीं है. उसे बस क्रीज पर कुछ समय बिताने की जरूरत है. भारत ए को अभ्यास मैचों में आस्ट्रेलिया ए ने उन्नीस साबित कर दिया, लेकिन द्रविड़ ने कहा कि बेंच स्ट्रेंथ को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है. हमें उतार–चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी हैं. आप हर मैच के बाद उनका आंकलन नहीं कर सकते. ये सीरीज हारना या जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है. आपका लक्ष्य उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है.■

पेशेवर कुश्ती लीग: सुशील और योगेश्वर दिखाएंगे दम

भारतीय कुश्ती महासंघ और प्रो स्पोर्टिफाई ने पेशेवर कुश्ती लीग (पीडब्ल्यूएल) की शुरुआत की घोषणा की. इस लीग में देश और दुनिया के 60 से अधिक शीर्ष पहलवान हिस्सा लेंगे. इस साल नवम्बर में लीग के पहले संस्करण में ओलम्पिक पदक विजेता सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त जैसे दिग्गज अपने फन का जादू दिखाते नजर आएंगे. इस लीग का आयोजन 8 नवम्बर से 29 नवम्बर के बीच होगा. इसमें ओलम्पिक में पदक जीत चुके दुनिया भर के 20 से अधिक पहलवान हिस्सा लेंगे. इस प्रतियोगिता के लिए 3 लाख डॉलर (लगभग 19 करोड़ रुपये) की पुरस्कार और नीलामी राशि रखी गई है. भारत के लिए दो ओलम्पिक पदक जीत चुके सुशील और योगेश्वर के अलावा देश की एकमात्र महिला ओलम्पिक पहलवान गीता फोगाट मुख्य आकर्षण होंगी. इसके अलावा भारत से बजरंग कुमार, अमित कुमार, अनुज चौधरी, बबीता कुमारी, विनेश फोगाट और गीतिका जाखड़ भी इस लीग की शोभा बढ़ाएंगी.

विश्व की सबसे महंगी कुश्ती प्रतियोगिता मानी जा रही है. इस लीग में कुल 66 पहलवान हिस्सा लेंगे, जिनमें 36 भारतीय और 30 विदेशी पहलवान होंगे. फ्रेंचाइजी आधारित इस लीग को जीतने वाली टीम पुरस्कार राशि तीन करोड़ रुपये रखी गई है. इसके अलावा दो करोड़ रुपये विभिन्न स्तर पर खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार के तौर पर वितरित किए जाएंगे. इस लीग में छह टीमें होंगी. प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होंगे. इनमें छह पुरुष और पांच महिलाएं होंगी. एक टीम में छह भारतीय और पांच विदेशी खिलाड़ी होगें. यह लीग बेस्ट ऑफ नाइन फॉरमेट के आधार पर खेली जाएगी. सभी नौ मुकाबले लीग स्तर पर आयोजित होंगे. हर मुकाबले में तीन राउंड होंगे और प्रत्येक राउंड तीन मिनट का होगा. इसमें एक मिनट का ब्रेक भी होगा. लीग के लिए कई रोचक नियम बनाए गए हैं. इस लीग को 150 से अधिक देशों में देखा जा सकेगा. इसका प्रसारण किस चैनल पर होगा, इसका खुलासा आने वाले दिनों में होगा. लीग के लिए 15 सितम्बर को नीलामी होगी और इसके मुकाबले छह शहरों में खेले जाएंगे. लुधियाना, चंडीगढ़, हिसार, दिल्ली, गुड़गांव, लखनऊ, रांची, कोलकाता, मुम्बई, पुणे, कोल्हापुर, हैदराबाद और बेंग्लुरु में इसके मुकाबले होंगे. अंतिम रूप से छह मेजबान शहरों का चयन बाद में किया जाएगा.

पांच सितारा होटल में इस लीग की लॉन्चिंग हुई. सुशील ने कहा कि वह इस लीग के आने से खुश हैं, क्योंकि इससे युवा खिलाड़ियों के लिए नए रास्ते खुलेंगे. सुशील ने यह भी कहा कि वह इस बात को लेकर भी खुश हैं कि रियो ओलम्पिक से पहले उन्हें तथा तमाम भारतीय पहलवानों को देश में ही अभ्यास का अच्छा मौका मिल जाएगा. साथ ही भारतीय खिलाड़ी लीग के माध्यम से पैसा भी कमा सकेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

बीजिंग करेगा 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी

चीन की राजधानी बीजिंग को 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है. आईओसी के 85 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया. चीन की राजधानी बीजिंग ने कजाकिस्तान के अलमाटी को कुआलालंपुर के एक कन्वेंशन सेंटर में हुये गुप्त मतदान में पराजित किया. बीजिंग ने 40 के बदले 44 मतों से अल्माटी को हराया. इस तरह बीजिंग ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी पाने वाला पहला शहर बन गया है. आईओसी ने कहा 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की तरह ओलंपिक परिवार ने एक बार फिर बीजिंग पर अपना भरोसा जताया है कि वह एक और बार शानदार खेलों का आयोजन करेगा. बीजिंग को यह मेजबानी मिलने के बाद खेलों की दुनिया में पूर्वी एशिया को लगातार तीसरी बार ओलिंपिक खेलों की मेजबानी मिली है. दक्षिण कोरिया का प्योंगचांग 2018 के विंटर शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, जबकि 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स टोक्यो में होने हैं. इसके बाद अब बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक होंगे. चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने आईओसी प्रमुख थॉमस बाक को एक पत्र लिखकर बीजिंग पर मेजबान के तौर पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद किया है.■

बॉलीवुड से दूर कभी नहीं थी: ऐश्वर्या

फिल्मकार संजय गुप्ता की आगामी फिल्म जज्बा के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन बड़े पर्दे पर वापसी करने वाली हैं. लेकिन ऐश्वर्या राय का कहना है कि उन्हें समझ में नहीं आता कि इस पर क्यों चर्चा होती है, क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगा कि वह फिल्मों से दूर थी. ऐश्वर्या ने कहा कि एक बार फिर कैमरे के सामने लौट कर वह खुश हैं और जज्बा की रिलीज का इंतजार कर रही हैं. इसमें शबाना आजमी, इरफान, चंदन राय सान्याल और जैकी श्रॉफ भी हैं. 2010 में ऐश्वर्या आखिरी बार नजर आई थीं, संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश में उन्होंने ने किरदार निभाया था.

ऐश्वर्या ने कहा अब तक बेहद खास अनुभव रहा. संजय गुप्ता भी बहुत अच्छे हैं. सभी कलाकार इरफान, शबाना आजमी, चंदन, जैकी श्रॉफ, सभी लोग बेहद अनूठे हैं. उनके साथ काम कर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं. मुझे नहीं लगता कि कोई अंतराल आया. सच में मैं आनंद ले रही हूं. यह फिल्म नौ अक्तूबर को रिलीज हो सकती है और यह दक्षिण कोरियाई फिल्म सेवन डेज का रीमेक है.■

मौला-मौला... कैसी बनी एक रूहानी कव्वाली

फिल्म हो गया दिमाग का दही की निर्देशक फौज़िया अर्शी ने एक खूबसूरत फिल्म ही नहीं बनाई है, बल्कि अपनी फिल्म में उन्होंने दिल को छू जाने वाले गानों का संगीत निर्देशन भी किया है. संगीत इस फिल्म का अहम और अटूट हिस्सा है. इस फिल्म में एक कव्वाली भी है, मौला–मौला. यह कव्वाली पारंपरिक और आधुनिक कव्वाली का सहज मिलन है. इस कव्वाली का संगीत तो रूहानी है ही, इसके बोल भी सुकून पहुंचाने वाले हैं. प्रसिद्ध कवि (शायर), गायक और संगीतकार अमीर खुसरो को कौन नहीं जानता. इस महान कवि की पंक्तियों को इस कव्वाली में अपनी आवाज़ से सजाया है खुद फौज़िया अर्शी ने. ऐसी रूहानी और सुकून भरी कव्वाली को दर्शाने के लिए चुनी हुई जगह भी मन को शांति देने वाली होनी चाहिए थी. इसलिए इस कव्वाली की शूटिंग के लिए बहुत खोज करने के बाद चुना गया सरखेज रोज़ा जैसी जगह को. इस रूहानी गाने को फिल्माने के लिए 564 साल पुराने सरखेज रोज़ा जैसी पवित्र जगह से बेहतर जगह नहीं हो सकती थी. सरखेज रोज़ा, अहमदाबाद की खूबसूरत और पौराणिक इमारतों में से एक है. सरखेज रोज़ा में बीचोबीच एक मानव निर्मित झील है. बाकी के वास्तुशिल्प इस झील के चारों ओर बने हुए हैं. एक तरफ संत गंजबक्ष की दरगाह तथा मस्जिद है, तो दूसरी तरफ महमूद बेगड़ा का महल. सरखेज इलाके में स्थित ऐतिहासिक और दिलकश मस्जिद के गुंबद और खंभे इस्लामी शैली में ही बने हुए हैं. मेहराब की जगह पत्थरों पर ही खूबसूरत नक्काशी की गई है. यह जगह इस कव्वाली की खूबसूरती को बखूबी दर्शाती है. इस कव्वाली की संगीत निर्देशक और गायिका फौज़िया अर्शी ने रेनबो एफएम को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि उनकी ख्वाहिश है और उन्होंने अपने आप से ये वादा किया है कि वो अपनी फिल्मों में मेलोडियस यानी मधुर और सुरीले संगीत को लायेंगी, जो कि मौजूदा दौर के हिंदी सिनेमा में अभी गायब है. यह कव्वाली उनकी इस ख्वाहिश का ही अंजाम है. इस काम में आने वाली चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर फौज़िया ने कहा कि उन्हें मालूम है कि वे जो दुनिया को देंगी, दुनिया उसे कुबूल करेगी और अपने सिर आंखों पर बैठाएगी. फौज़िया अर्शी के साथ–साथ इस रूहानी कव्वाली को आवाज़ दी है लोकप्रिय गायक कैलाश खेर ने. इस कव्वाली में जाने–माने कलाकार शहबाज़ खान भी नजर आएंगे.

आइये जानते हैं, कैसे फिल्म हो गया दिमाग का दही की इस कव्वाली की शूटिंग पूरी हुई. फिल्म हो गया दिमाग का दही की टीम जब अहमदाबाद स्थित सरखेज रोज़ा पहुंची तो हर तरफ सावन का नज़ारा था. तेज बारिश के बीच कव्वाली की शूटिंग कैसे हो, ये एक बड़ा सवाल था. ए.एस.आई की तरफ से सरखेज रोज़ा में शूटिंग करने की परमिशन दो दिन की ही थी, जिसमें कव्वाली शूट होनी थी. ऐसे में दो दिन और दो रात लगातार पूरी यूनिट द्वारा काम किया गया. पहले दिन दिनभर बारिश की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा. फिर भी पूरे सेट पर लाइटिंग और सजावट का काम जारी रहा. मजेदार बात यह है की पूरी यूनिट भीग चुकी थी, लेकिन फिर भी शूटिंग का काम नहीं रुका. खास बात यह है कि बारिश शूटिंग में रुकावट बनने की जगह खूबसूरती के साथ निर्देशक के कैमरे में कैद हो गई. शूटिंग के लिए मुंबई और दिल्ली से आर्टिस्ट आये थे. लाइट्स, आर्ट डायरेक्टर्स और सभी इक्विपमेंट्स खास मुंबई से आए थे. तेज बारिश और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हो गया दिमाग का दही की पूरी यूनिट ने फौज़िया अर्शी के निर्देशन में इस कव्वाली की शूटिंग बेहतरीन तरीके से की. इतना ही नहीं, तेज बारिश से शूटिंग में आई परेशानियों के बावजूद, पूरी यूनिट ने इस कव्वाली की शूटिंग हंसते–हंसते की. सरखेज रोज़ा में मौजूद मजार के अन्दर भी शूटिंग की गई. इस पौराणिक जगह के हर हिस्से की खूबसूरती को कव्वाली में बेहद उम्दा तरीके से दर्शाया गया है. फिल्म हो गया दिमाग का दही की संगीत निर्देशक फौज़िया अर्शी का संगीत के प्रति अनुराग कव्वाली मौला–मौला से साफ झलकता है. फिल्म हो गया दिमाग का दही ने मौला–मौला कव्वाली के रूप में हिंदी सिनेमा को एक नायाब उपहार दिया है.■

एक कार्यक्रम के दौरान मल्लिका ने एक सवाल का जवाब दिया कि वह द्रौपदी का किरदार निभाना चाहेंगी.

मल्लिका शेरावत द्रौपदी बनना चाहती हैं

बॉलीवुड की हॉट अभिनेत्री मल्लिका शेरावत अपने किरदारों के लिए जानी जाती हैं. मल्लिका की ख्वाहिस है कि वह द्रोपदी का किरदार निभाना चाहती हैं. वैसे भी इन दिनों बॉलीवुड इंडस्ट्री में बायोपिक का क्रेज चल रहा है.

एक कार्यक्रम के दौरान मल्लिका से पूछा गया कि वह किस किरदार की बायोपिक करना चाहेंगी. इस सवाल केजवाब में उन्होंने कहा कि द्रौपदी क्योंकि वह एक पौराणिक चरित्र हैं. वह बहुत शक्तिशाली महिला थीं और मेरे ख्याल से वह काफी स्ट्रांग हैं.

वहीं मल्लिका ने आगे बताया कि, मेरे पास काफी फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं. लेकिन मैं फिल्मों की कहानी को ध्यान में रखकर फिल्मों का चयन करना चाहती हूं.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

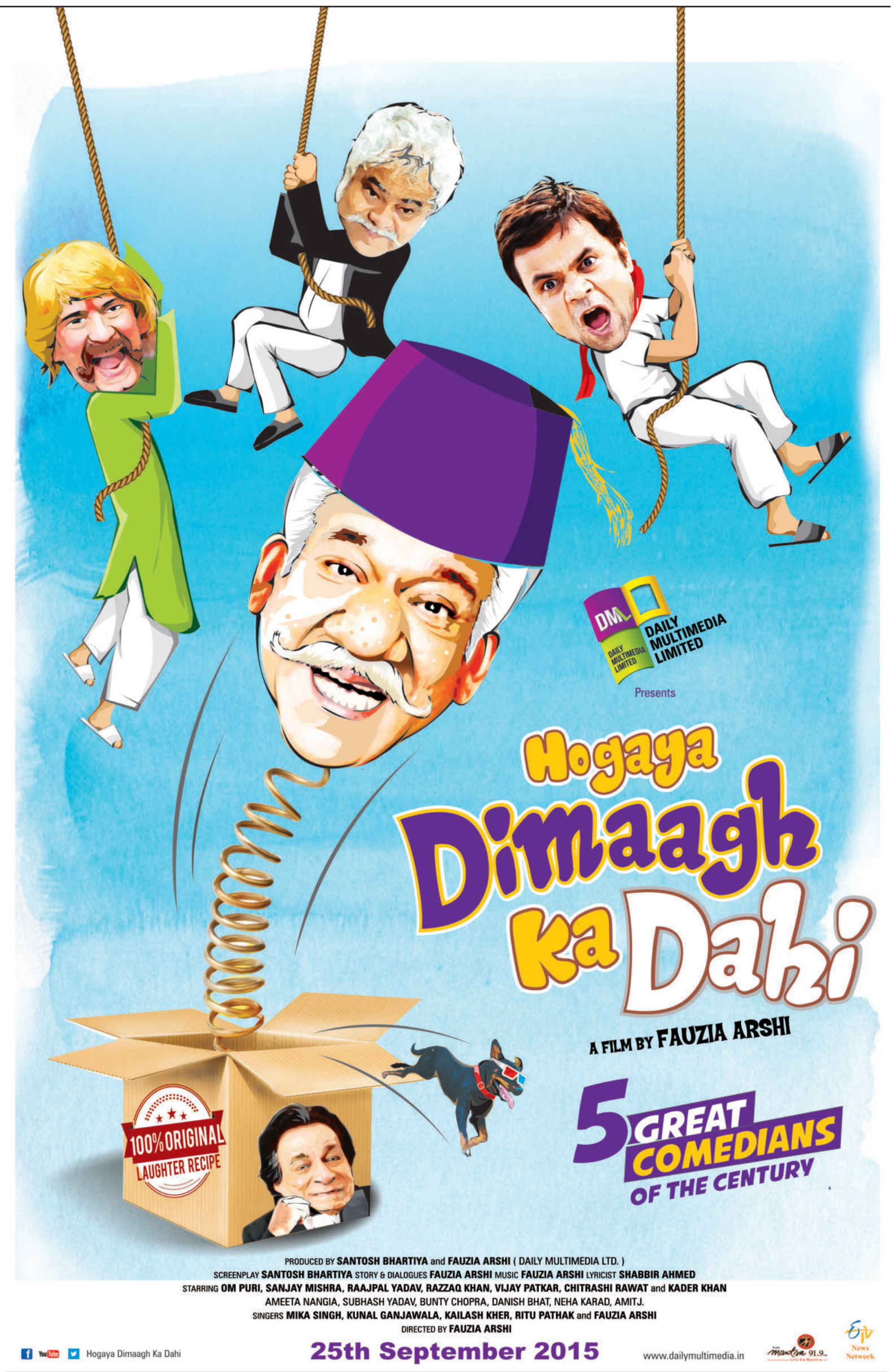

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार -झारखंड

17 अगस्त-23 अगस्त 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

टिकट बंटवारे पर अटकी सांस

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बिहार में राजग और महागठबंधन दोनों के ही नेताओं के बीच टिकट पाने की बेचैनी बढ़ती जा रही है. टिकट के लिए विभिन्न दलों के नेता अपने आलाकमान का चेहरा ताकने के लिए मजबूर हैं. दोनों ही खेमे की टिकट बंटवारे पर एक ही पीड़ा है कि उन्हें आलाकमान से हरी झंडी नहीं मिल रही है. आलाकमान भी हरी झंडी कैसे दे? दरअसल दोनों ही गठबंधनों के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है. बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में टिकट बंटवारे में की गई कोई भी गलती उन्हें काफी महंगी पड़ सकती है. दोनों गठबंधनों में टिकट बंटवारे को लेकर पसोपेश का खुलासा कर रही है हमारी यह रिपोर्ट...

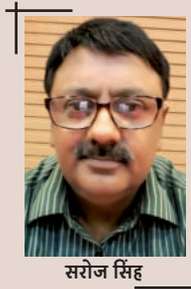

सरोज सिंह

चुनाव आयोग की टीम के ताबड़तोड़ दौरे से सूबे में चुनावी माहौल तो बन गया है पर टिकटों के बंटवारे में हो रही देरी से चुनाव मैदान में कूदने वाले पहलवानों का जोश ठंडा पड़ा हुआ है. क्या होगा और क्या नहीं होगा जैसे सवालों में उलझे नेताओं का एक पांव पटना तो दूसरा दिल्ली में है. गुजरते वक्त के साथ इनकी बैचेनी लगातार बढ़ती जा रही है. सीट से जुड़ी कोई भी सूचना के इंतजार में दिन बीत जा रहा है पर पार्टी आलाकमान का चेहरा देखने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है. दोनों ही खेमे यानि की महागठबंधन और एनडीए से जुड़े नेताओं की यही पीड़ा है कि आलाकमान से हरी झंडी मिल ही नहीं रही है. क्षेत्र में चाहने वाले समर्थक फोन कर करके नेताओं को परेशान किए हुए हैं और नेता जी बस एक ही बात कह रहे हैं कि सब क्लीयर है. सिंबल लेकर जल्द ही आ रहे हैं, आप अपनी तैयारी जारी रखिए. लेकिन बार-बार मिल रहे इन दिलासों से कार्यकर्ता भी निराश होने लगे हैं. लेकिन करें तो क्या करें इंतजार के अलावा कोई दूसरा विकल्प सामने है ही नहीं. ऐसा नहीं है कि यह दुविधा चुनाव लड़ने केवल एक राजनीकि दल के नेताओं के समक्ष है. दरअसल सबसे बड़ी दुविधा तो सहयोगी दलों के सामने ही है. एनडीए के तीनों सहयोगी दलों के नेताओं को भाजपा की तरफ से बुलावे का इंतजार है. लोजपा, रालोसपा और हम के वरीय नेताओं का कहना है कि हम अपने चुनाव लड़ने वाले नेताओं के सामने रोज एक ही तरह का आश्वासन देते-देते परेशान हो गए हैं. सीट और टिकटों का बंटवारा न होने के कारण चुनावी तैयारियों में जो नुकसान हो रहा है सो अलग. आखिर इसकी भरपाई कैसे होगी इसका जबाव किसी के पास नहीं है. भाजपा अपने सहयोगी दलों को बार बार आश्वासन दे रही है कि जल्द ही सीटों का बंटवारा कर दिया जाएगा लेकिन लगता नहीं कि सितंबर के पहले सप्ताह के पूर्व यह काम हो पाएगा. हालांकि भाजपा अब यह कहने लगी है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में हम सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा कर देंगे. जानकार बताते हैं कि भाजपा अभी नरेंद्र मोदी की सभाओं के खत्म होने की बात कह रही है पर हकीकत यह है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ही भाजपा सीटों के बंटवारे के मूड में है. जानकार सूत्र बताते हैं कि इसके पीछे भाजपा की अपनी रणनीति है. बिहार विधानसभा के लिए हुए उपचुनाव और हाल ही में संपन्न स्थानीय निकाय के चुनावों में सहयोगी दलों के लचर प्रदर्शन ने भाजपा को सर्तक कर दिया है. स्थानीय निकाय चुनाव में तो लोजपा चार में से केवल एक और रालोसपा दो में से एक भी सीट नहीं जीत पाई. भाजपा चाहती है कि अपने सहयोगी दलों की मांग से विचलित हुए बिना जमीनी राजनीतिक सच्चाई को पैमाना बनाकर सीटों का बंटवारा हो. भाजपा इसके लिए माइक्रो लेवल पर होमवर्क कर रही है और इसमें समय लग रहा है. संकेतों में भाजपा अपने सहयोगी दलों को यह बता चुकी है कि केवल गिनाने के लिए सीटें नहीं दी जाएंगी. भाजपा इस बार सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, इसलिए एक-एक सीट पर गहन मंथन के बाद ही बंटवारे का फैसला होगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उस सीट का प्रत्याशी भी मजबूत और जनता के बीच लोकप्रिय हो. सीट बंटवारे में विलंब का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि भाजपा अपने सहयोगी दलों को इधर-उधर ताकने का मौका नहीं देना चाहती है. देर से फैसला करने पर सहयोगी दलों के पास विकल्प काफी कम बच जाएंगे और वे चाह कर भी पाला बदलने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे. हालांकि जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उससे ऐसा लगता नहीं कि भाजपा के सहयोगी दल सीट बंटवारे में भाजपा के फैसले का विरोध करेंगे. दूसरी तरफ भाजपा का हाल यह है कि भाजपा में एक-एक सीट पर दस से अधिक दावेदारों की लंबी फौज तैयार है. पार्टी चाहती है कि जितना संभव हो उतना आने वाले विरोध को टाला जा सके. अभी तो सभी मिलकर पार्टी के काम में लगे हैं लेकिन जैसे ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा पार्टी के सामने बगावती तेवर के कई नेता सामने आ जाएंगे. यही वजह है कि भाजपा सीटों के बंटवारे में देरी कर रही है. गौरलतब है कि ऐसी समस्या रालोसपा, लोजपा और हम के साथ भी है. अभी तो सभी 243 सीटों के दावेदारों की फौज सभी दलों के कार्यालयों में जमा है लेकिन जैसे ही सीटों का बंटवारा होगा तस्वीर बदल जाएगी. उसी जगह के लोग ज्यादा नजर आएंगे, जहां की सीट पार्टी को आवंटित होगी. लेकिन तथ्य और हालात जो भी हो मगर सच्चाई यह है कि देरी से चुनावी तैयारियों को काफी नुकसान पहुंच रहा है. चुनाव लड़ने वाले नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें? इसलिए अब उन्होंने भी इंतजार को ही अपनी ताकत बना लिया है. कमोवेश यही हालात राजद, कांग्रेस, जदयू और एनसीपी में भी है. इस महागठबंधन से भी टिकट पाने वालों को इंतजार करने को कहा गया है. दरअसल महागठबंधन एनडीए के बीच सीट बंटवारे का इंतजार कर रहा है. जदयू व राजद के नेताओं को ऐसा लगता है कि एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा आसान नहीं है और बगावत होना तय है. महागठबंधन ऐसी ही स्थिति का लाभ उठाना चाहता है. लालू प्रसाद हर हाल में नीतीश कुमार से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस भी 40 सीटों से कम पर समझौते के मूड में नहीं है. ऐसे में कुछ वक्त लेकर मामले को सुलझाने का प्रयास जारी है. इसलिए स्वाभाविक है कि सीटों के बंटवारे में समय लगेगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होता है या फिर एनडीए में. चूंकि इसके बाद ही फिर टिकटों के बंटवारे का महाभारत शुरू होगा जो और भी भीषण और राजनीतिक तौर पर प्रलयकारी होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

तीस फीसदी विधायकों का टिकट कटेगा!

सीटों के बंटवारे और टिकटों के आवंटन में भले ही अभी देरी हो रही है पर इतना तय है कि इस दफा कम से कम तीस फीसदी सीटिंग विधायकों का टिकट कटेगा. पार्टियों के अंदर चल रही इन तैयारियों से बॉर्डर लाइन पर अटके कई विधायकों की सांस फूल रही है. जानकार सूत्र बताते हैं क सबसे ज्यादा कैंची भाजपा में ही चलने वाली है. भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने स्थानीय इकाई को साफ कर दिया है. इस बार किसी भी कीमत पर बिहार में सरकार बनानी है, इसलिए टिकट उन्हें ही दिया जाए जिनकी जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो भले ही उसके लिए सीटिंग विधायक का टिकट ही क्यों नहीं काटना पड़े. भाजपा ने मोटे तौर पर जो अपना सर्वे कराया है उससे साफ हुआ है कि बहुत सारे विधायकों को लेकर उनके क्षेत्र में जनता की अच्छी राय नहीं है. अगर उन्हें दोबारा टिकट दिया गया तो सीट हाथ से जा भी सकती है. बताया जा रहा है कि विधायक फंड का बहाना लेकर बहुत से विधायकों ने जनता के साथ संवाद बिल्कुल ही बंद कर दिया था. अब चुनाव के वक्त जब वे क्षेत्र में जा रहे हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए भाजपा के थिंक टैंक ने राय बनानी शुरू कर दी है कि ऐसी सीटों पर नए चेहरे के साथ चुनावी समर में उतरा जाए. यही हाल जदयू में भी है. लेकिन जदयू के साथ एक दिक्कत यह भी है कि उनकी कुछ सीटिंग सीटों पर राजद का दावा है, इसलिए जदयू में टिकट से बेदखल हुए विधायकों की संख्या कुछ ज्यादा हो सकती है. एंटी इनकंबैंसी का फैक्टर तो सभी दलों में लागू हो रहा है. जदयू नए सामाजिक समीकरण के आधार पर सीटों का बंटवारा चाह रही है इसलिए स्वाभाविक है उसके कई विधायकों का टिकट कट जाएंगे.

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

बगहा में लोजपा की मजबूत दावेदारी

संजय सिंह
feedback@chauthiduniya.com

जिले का बगहा विधान सभा क्षेत्र को कृषि प्रधान माना जाता है. यह विधान सभा क्षेत्र राजनीतिक व सांस्कृतिक तौर पर भी काफी सजग माना जाता है. इस विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं. इस क्षेत्र पर अभी जदयू का कब्ज़ा है. यहां से पहली बार चुनाव लड़ कर प्रभात रंजन ने विजय हासिल की है. भौगोलिक रूप से इस क्षेत्र में प्रमुख फसल के रूप में धान, गन्ना, दलहन व तिलहन की काफी खेती होती है. उद्योग के रूप में प्रखंड मुख्यालय में एक चीनी मिल है, जहां स्थानीय किसान अपना गन्ना देते हैं. इस विधान सभा क्षेत्र के पश्चिम तथा दक्षिणी तरफ से गंडक नदी बहती है. बार-बार धारा बदलने से इसका दियरा क्षेत्र काफी विस्तृत है. जिसका विकास आज तक नहीं हो पाया है. जिसके कारण यह क्षेत्र अपराधियों की शरणस्थली के रूप में कुख्यात रहा है. विगत दशक में गंडक की धार बदलने के कारण जमीन की पहचान में दिक्कतों की वजह से यहां अपराध पनपा. जमीन के कब्जे को लेकर अपराधियों का बोलबाला बढ़ा. वर्ष 2010 के विधान सभा चुनाव में तत्कालीन जदयू विधायक प्रभात रंजन को 67, 500 मत मिले थे. जबकि निकटम प्रतिद्वंद्वी के रूप में राजद प्रत्याशी राम प्रसाद यादव को 18,755 मत मिले थे. वर्तमान विधायक की मानें तो उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था पहले से काफी बेहतर हुई है. गंडक के पार जाने के लिये रतवल पुल बना, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिला है. साथ ही क्षेत्र में पुल-पुलिया व सड़क निर्माण होने से आवागमन सुलभ हुआ है. बाढ़ से निजात के लिये तटबंधों के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया है.

विगत विधान सभा चुनाव से इतर इस बार तकरीबन सभी दलों में टिकट के लिये ज्यादा मारा-मारी है. संभावित प्रत्याशी अभी से टिकट के जुगाड़ में लग चुके हैं. जानकारों की मानें तो टिकट कटने पर कई लोग निर्दलीय भी मैदान में उतरने का मन बना कर अपनी तैयारी में अभी से लग गए हैं. ऐसा लगता है कि वर्तमान विधायक इस बार जदयू के टिकट पर यहां से किस्मत आजमाएंगे. राजद से रनर-अप रहे राम प्रसाद यादव भी अपनी पार्टी का पहला हक मान कर अपने को संभावित प्रत्याशी मान कर तैयारी में जुट गये हैं. भाजपा से भी यहां काफी लोग अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने में लगे हैं. भाजपा के जिलाध्यक्ष रवींद्र श्रीवास्तव की काफी चर्चा है. पूर्व पेट्रोलियम सचिव आर एस पांडेय के भी नाम की चर्चा है. भाजपा से ही पूर्व आइएएस के. गुप्ता का भी नाम आगे आ रहा है. बहरहाल टिकट जिसे भी मिले लेकिन उन्हें अपने दल के लोगों से भी पार पाने की चुनौती रहेगी.

जानकारों की मानें तो सबसे सशक्त दावेदारी लोजपा के शैलेंद्र कुमार सिंह की है. शैलेंद्र का स्थानीय होना तथा इस क्षेत्र के विकास के लिये सतत प्रयत्नशील होकर काम करना क्षेत्र के लोगों के द्वारा काफी पसंद किया गया. पश्चिम चंपारण को पर्यटन के मानचित्र पर लाने में उनके द्वारा किए गए प्रयास व सुझाव काफी कारगर हुए हैं. वाल्मीकि नगर में पौराणिक महत्व के स्थलों के विकास, जंगल सफारी समेत इको टूरिज्म को बढ़ावा. बकौल शैलेन्द्र पर्यटन क्षेत्र के विकास से ही लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है. जिसकी पहल उन्होंने लौरिया में नंदनगढ़ बौद्ध स्तूप, चानकी गढ़, रमपुरवा लौह स्तंभ को विश्व मानचित्र पटल पर लाने के लिये ताइवान के डेलीगेशन को यहां बुलाया. वर्ष 2012 में ताइवान के तुमान चिंसिन्ताओ के नेतृत्व में 100 देश के बौद्ध मतावलंबियों का प्रतिनिधिमंडल ने यहां का दौरा किया. जिसके बाद नंदनगढ़ समेत अन्य जगहों पर विदेशी सैलानियों की संख्या अप्रत्याशित वृद्दी नजर आयी. हालांकि यह सीट राजग तथा महागठबंधन के लिये प्रतिष्ठा का प्रश्न बनेगा.■

बगहा में जातीय समीकरण

ब्राम्हण- 13,500
राजपूत-22,000
भूमिहार-5, 500
कायस्थ-6,200
यादव-24,000
मुसलमान-23,500
बनिया (तेली, सूढ़ी, मारवाड़ी व अन्य)-39,000
नोनिया-7,500
बिंद मल्लाह-15,000
कुर्मी चनउ-8,200
कोइरी-12,000
पासवान-13,500
रविदास-13,000
अन्य दलित-14,000
मुसहर-9,100
थारू-6,000
उरांव-8,500
गोंड, लोहार, कंहार, बइई तत्वा, हजाम-10,500
ईसाई-1,500

कुल मतदाता-2,52,500

शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र
भाजपा में दावेदारों की फौज

ऋषि लाल
feedback@chauthiduniya.com

नये परिसीमन के बाद शेरघाटी (गया) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का भूगोल बदल जाने के कारण राजनीतिक दलों को उम्मीदवार तय करने में खासी परेशानी हो रही है. यह क्षेत्र यादव और वैश्य बहुल माना जाता रहा है. यही कारण है कि भाजपा शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से वैश्य समाज के उम्मीदवार को तरजीह दे रही है. 2010 में हुए परिसीमन के बाद शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से जद (यू) के विनोद कुमार यादव विधायक हैं. वे पंचायती राज मंत्री हैं.विनोद को उस समय भाजपा–जद (यू) गठबंधन रहने के कारण वैश्य वोटों का लाभ मिला था. लेकिन अब स्थिति बदलने लगी है. अन्य जातियों का झुकाव भाजपा की तरफ बढ़ा है. विनोद को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का संरक्षण प्राप्त है. हालांकि इस बार भी यहां चुनावी मुद्दे वही हैं जो पिछले चुनाव में थे जैसे सिंचाई, बिजली, पानी, शहर, ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क व्यवस्था में सुधार. इसके बावजूद भी परिसीमन के बाद शेरघाटी को जिला बनाए जाने की मांग जस की तस है. विनोद की राह इस बार आसान नहीं दिख रही है. जदयू की मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा से टिकट के दावेदारों में संतोष कुमार गुप्ता अगर चुनावी मैदान में आए तो वर्तमान विधायक को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

विनोद कुमार यादव | मंजू अग्रवाल | सीताराम यादव | संतोष कुमार गुप्ता

शेरघाटी विधानसभा का राजनीतिक व सामाजिक समीकरण संतोष कुमार गुप्ता के अनुकूल माना जा रहा है. 2010 के चुनाव में विनोद कुमार यादव का मुकाबला सुषमा देवी उर्फ मंजू अग्रवाल निर्दलीय प्रत्याशी से था. इस बार मंजू अग्रवाल भी भाजपा से टिकट की कतार में हैं. मंजू अग्रवाल नया चेहरा हैं और उनकी छवि भी बेदाग है. जहां तक सीताराम यादव का सवाल है, वह विवादों से घिरे हैं. इस कारण क्षेत्र में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं बतायी जा रही है. भाजपा मंडल अध्यक्ष और वार्ड पार्षद मंजू अग्रवाल कहती हैं कि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण हिस्सा नारी सशक्तिकरण का भी है.

शेरघाटी विधानसभा का राजनीतिक व सामाजिक समीकरण संतोष कुमार गुप्ता के अनुकूल माना जा रहा है. 2010 के चुनाव में विनोद कुमार यादव का मुकाबला सुषमा देवी उर्फ मंजू अग्रवाल निर्दलीय प्रत्याशी से था. इस बार मंजू अग्रवाल भी भाजपा से टिकट की कतार में हैं. मंजू अग्रवाल नया चेहरा हैं और उनकी छवि भी बेदाग है. जहां तक सीताराम यादव का सवाल है, वह विवादों से घिरे हैं. इस कारण क्षेत्र में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं बतायी जा रही है. भाजपा मंडल अध्यक्ष और वार्ड पार्षद मंजू अग्रवाल कहती हैं कि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण हिस्सा नारी सशक्तिकरण का भी है. वे कहती है कि समानता के दौर में भी हमारा समाज औरतों की स्वतंत्रता के प्रति संवेदनशील नहीं है. ग्रामीण इलाकों में आधी आबादी के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान नहीं है. वहीं भाजपा के टिकट के दावेदारों में संतोष कुमार गुप्ता कहते हैं कि क्षेत्र को जिला बनाने की मांग को लेकर दो दशक से आंदोलन का दौर चल रहा है. यहां कुल बूथों की संख्या 260 है. कुल मतदाताओं की संख्या 225105 संख्या है. अगर उन्हें मौका मिला तो शरेघाटी को जिला बनाने के सपने को पूरा करने की कोशिश की जाएगी.

इस पर विनोद कुमार यादव का कहना है कि भाजपा से बिहार को बहुत खतरा है. भाजपा सांप्रदायिक राजनीति का चेहरा है. एक सवाल के जवाब में विनोद कहते हैं कि इस बार प्रचार की कमान प्रशांत किशोर के पास है जो नरेंद्र मोदी की प्रचार टीम का हिस्सा रह चुके हैं. इसके अलावा पार्टी ने विज़न 2025 तैयार किया है जिसके जरिये बिहार के विकास मॉडल पर लोगों का विश्वास हासिल करने की कोशिश की जाएगी.■

समस्त बिहारवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई

डायबिटीज-मधुमेह कारण और निवारण

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ.कपिल कुमार
फिजिशियन, एमडी, भागलपुर

वर्तमान समय में डायबिटिज सबसे अधिक होने वाला रोग है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया का हर पांचवा इंसान डायबिटिज से पीड़ित है। इस विषय पर भागलपुर के अनुभवी चिकित्सक डॉ. कपिल कुमार से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि भारत में भी डायबिटिज के रोगियों की संख्या दिन–ब–दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि मेडिकल साइंस में इस रोग का सटीक उपचार संभव है इस रोग में शीघ्र लाभ मिलने की संभावना रहती है–आजकल कॉमन समस्या जो लोगों में देखी जाती है और जिससे आप पहचान कर सकते हैं वह है वेट लॉस, ज्यादा प्यास, ज्यादा भूख, आलस्या तथा जो व्यक्ति पेशाब के लिए रात में 3 चार बार उठता है तो उस व्यक्ति का इस बीमारी से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। इस बीमारी की उम्र सीमा तय तो नहीं है लेकिन बच्चों में भी यह हो सकता है बच्चों में होने का एक कारण उसका यूरेजेनिक ब्लॉडर भी हो सकता है या फिर बिकोलॉय, जिस व्यक्ति को यदि मधुमेह या डायबिटिज हो जाय तो उनका आंखों की रौशनी जाने तथा ब्लडप्रेशर बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है और यदि इसे कंट्रोल नहीं कर पाये तो लकवा मारने की भी संभावना रहती है। **परहेज रखें** – मक्खन, पनीर, मीट, चीज का सेवन कम से कम कर दें। सफेद चावल का सेवन न करें। अगर कभी सफेद चावल **खायें** भी तो उबाल कर न खाएं क्योंकि सारे विटामिन्स और मिनरल्स अतिरिक्त पानी में निकल जाएंगे। चीनी, शक्कर, गुड़ शहद गन्ना, चाकलेट, पेस्ट्री, केक, कुल्फी, आइसक्रीम का सेवन न करें। आलू, कचालू, अरबी, कटहल, जिमीकंद, शकरकंद, चुकंदर का सेवन, न करें। कभी बहुत मन करे तो उन्हें उबाल कर थोड़ा खा सकते हैं। **क्या करें** – चिंता मुक्त रहें, समय समय पर सुगर और ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें, खाना हरेक दो घंटे पर थोड़ा–थोड़ा लें, नियमित दवाईयां लें, रेगुलर एक्सरसाईज करें। **क्या खायें** –सब्जियों में चेरी, स्ट्राबेरी, सेब, संतरा, अनार, जामुन, पपीता, मौसमी और करेला, घीया, तोरी, सीतफल, खीरा, टमाटर आदि नियमित लें। डायबिटिज के रोगियों को सोया, मूंग दाल, काले चने, रजमा, ब्राउन राइस, अंडे का सफेद हिस्सा, हरी सब्जियां का प्रयोग तथा खाना ऐसा खाएं जिनमें रेशे की मात्रा इनमें एंटी आक्सीडेंट्स काफी होते हैं। चोकरयुक्त आटे की रोटी, दलिया, ओट्स ब्रॉन, राजमा, लोबिया आदि लें। अगर जूस पीना भी हो तो, करेला, खीरा, टमाटर, आंवला और एलोवेरा का जूस ले सकते हैं।

■ प्रस्तुतिः चित्रा भारती

URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap
Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अंकगणित के महत्वपूर्ण प्रश्न

सुबोध कुमार, Director
S.T.C., Motihari
वृहत अंकगणित के लेखक

51. संख्या का 3/4 भाग विवाहित और विवाहिता पुरूष का 2/3 भाग पुरूष बच्चा वाले हैं। यदि कुल विवाहित संख्याओं में 55 लोग निःसंतान हैं तो कुल काम करने वाले लोगों की संख्या क्या है?
A) 190 B) 180 C) 288 D) 198

52. एक फल विक्रेता पहले ग्राहक को कुल संख्या का 1/5 भाग और 3 फल देता है दूसरे ग्राहक को शेष का 1/3 भाग और 2 फल देता है। तीसरे ग्राहक को शेष का 1/2 भाग और 1 फल देता है। यदि उसके पास शेष 5 फल बच जाता है। तो दूसरे ग्राहक को कितना फल दिया ?
A)10 B) 20 C) 25 D) 30

53. एक आदमी के पास कुछ सेब थे। इनमें से आधे और एक अधिक सेब पहले बच्चे को देता है। बचे हुए सेब के आधे और दो अधिक सेब दूसरे बच्चे को देता है। इसके बाद बचे हुए सेब के आधे और तीन अधिक सेब तीसरे बच्चे को देता है। अन्ततः उसके पास15 सेब बच जाता है। तो कुल कितना सेब उसके पास थे ?
A) 150 B) 154 C) 152 D) 156

54. किसी परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करके 130 प्राप्त करता है तो कितना प्रश्न गलत बनाया ?
A) 21 B) 20 C) 22 D) 18

55. किसी परीक्षा में सही हल के लिए 2 अंक मिलते हैं और गलत हल के लिए 0.5 अंक काट लिए जाते हैं। यदि 200 के प्रश्न में कोई छात्र 40 प्रतिशत प्रश्न गलत हल किया तो उसे कितना अंक प्राप्त होगा ?
A) 130 B) 140 C) 150 D) 200

56. किसी परीक्षा में 200 प्रश्न थे। सही उत्तर देने पर 5 अंक मिलते हैं। गलत उत्तर के लिए (–2) मिलते हैं। कोई छात्र 470 अंक प्राप्त किया जिसमें वह 25 प्रतिशत प्रश्न हल करने का प्रयास नहीं किया, तो उसने कितना प्रश्न सही हल किया?
A) 100 B) 110 C) 120 D) 90

57. किसी व्यायाम में 200 लोग शामिल थे। उनमें कुछ लोग सीधे खड़े थे और कुछ लोग धरती पर हाथों और पैरों के बल झुके थे। यदि कुल 480 हाथ और पैर जमीन को छू रहे थे तो कितने लोग सीधे खड़े थे ?
A) 160 B) 120 C) 140 D) 130

58.किसी किसान के पास कुछ पक्षी और चार पैर वाले जानवर थे। जिनके सिरों की संख्या 200 और पैरों की संख्या 480 था। तो कितने पक्षी थे?
A) 160 B) 120 C) 140 D) 150

59. भैसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुणा से 24 अधिक पैर हैं। भैसों की संख्या समूह में कितनी है?
A) 14 B) 12 C) 10 D) 8

स्वतंत्रता दिवस के शुभअवसर पर छात्र–छात्रा, अभिभावक, शिक्षकण एवं बिहारवासियों को हार्दिक बधाई
सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले प्रथम दस विजेताओं को पुरस्कृत किया जायेगा।
SMS द्वारा उतर 8002817092 पर भेजें
शेष अगले अंक में

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

17 अगस्त–23 अगस्त 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

फिल्मों के लिए खुला है सरकारी खजाना, धंधेबाजी का बहाना

सीएम से मिलिए, फिल्म टैक्स फ्री!

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश में लोग अब आमतौर पर यह कटाक्ष करते मिल रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम लेना हो तो कह दो फिल्म वाले हैं, फौरन मुलाकात का समय मिल जाएगा. प्रदेश में समाजवादी पार्टी की यही छवि पिछले तीन साल में बनी है. आम लोगों की तकलीफों से मुखातिब होने और पीड़ा झेल रहे किसानों की समस्या दूर करने के बजाय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हीरो हिरोइनों और फिल्म निर्देशकों से मिलने और उन्हें तमाम सरकारी रियायतें देने में ही लगे रहते हैं. अभी उत्तर प्रदेश में फिल्मों के तथाकथित निर्माण में अनुदान लेने और छूट लेने की लूट मची हुई है. जिस फिल्म के निर्देशक या हीरो–हिरोइन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली, समझ लें वह फिल्म मनोरंजन कर की छूट लूट कर ले गई. समाजवादी सरकार ने मनोरंजन कर विभाग का भट्ठा बिठा कर रख दिया है.

अभी पिछले ही दिनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सलमान खान अभिनीत फिल्म बजरंगी भाईजान को मनोरंजन कर से मुक्त कर दिया. बॉक्स ऑफिस पर अरबों रुपये पीट रही फिल्म को मनोरंजन कर से मुक्त किए जाने के औचित्य पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब कौन दे! जवाबदेही हो तो कोई जवाब दे. सपा के ही एक नेता ने भन्नाए हुए स्वर में यह कहा और मनोरंजन कर विभाग को बंद कर देने की सलाह भी दे डाली. रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान को टैक्स फ्री किए जाने पर खुद मनोरंज कर विभाग के अधिकारी

सलमान खान की बजरंगी भाईजान के अलावा, विद्या बालन और इमरान हाशमी की हमारी अधूरी कहानी, 600 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली आमिर खान की फिल्म पीके को टैक्स फ्री करने से भी उत्तर प्रदेश के मनोरंजन कर विभाग को करीब करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है. इसके अलावा अर्जुन कपूर की तेवर, माधुरी दीक्षित की डेढ़ इश्किया, प्रियंका चोपड़ा की मैरीकॉम और रानी मुखर्जी की मर्दानी ने बॉक्स ऑफिस पर तो अपनी जमकर कमाई कर ली, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की दरियादिली से टैक्स फ्री होने के चलते मनोरंजन कर विभाग को करोड़ों रुपये का नुकसान दे गई.

ही काफी नाराज हैं. एक अधिकारी ने कहा कि सत्ता हाथ में है, तो सरकारी खजाना फिल्म वालों को ही दे दें, फिर हमें बैठा कर पगार क्यों दिया जा रहा है! फिल्म के टैक्स फ्री होने से फिल्म बनाने वाले और दर्शक खुश थे, लेकिन असलियत जानने वालों को यह पता है कि मुख्यमंत्री की यह उदारता प्रदेश के खजाने पर भारी पड़ रही है. हाल यह है कि प्रदेश को राजस्व देने में दूसरे नंबर पर रहने वाला मनोरंजन कर विभाग अब अपना लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पा रहा है. मनोरंजन कर विभाग के ही एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री यह दरियादिली प्रदेश के किसानों के लिए क्यों नहीं दिखा रहे? इतनी उदारता बरतते तो किसानों का करोड़ों रुपये का गन्ना बकाया मिल जाता और वे भूखों नहीं मरते.

बाजार–गणित यह है कि फिल्में जितनी अच्छी चलती हैं, मनोरंजन कर विभाग को आय भी उतनी ही अच्छी होती है. लखनऊ में रिलीज के सिर्फ तीन दिनों के अंदर बजरंगी भाईजान ने 18 लाख रुपये की कमाई की थी. इसका 40 फीसदी हिस्सा मनोरंजन कर विभाग को मिला. यह सिलसिला दोगुनी रफ्तार से चलने वाला था, लेकिन मुख्यमंत्री ने सरकार को होने वाली आय के स्रोत पर कुल्हाड़ी मार दी. मुख्यसमंत्री अखिलेश यादव द्वारा

फिल्म के लिए नियम की ऐसी-तैसी

किसी भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की प्रक्रिया बहुत लोकतांत्रिक पद्धति पर बनी हुई है. लेकिन समाजवादी सरकार ने इसका सत्यानाश कर दिया है. टैक्स मुक्त करने का अधिकार शासन के पास जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्णय पर विभाग के प्रमुख सचिव के अलावा वित्त विभाग समेत कई अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा फिल्म देखकर उसे टैक्स फ्री करने या नहीं करने का बाकायदा मंतव्य देने का प्रावधान है. इसके बाद उस मंतव्य को प्रस्ताव की शक्ल देकर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का नियम है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल से औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद ही मनोरंजन कर विभाग फिल्म को टैक्स फ्री करने का आखिरी फैसला लेता है. इसके बाद आदेश की प्रति जिला मनोरंजन कर अधिकारियों के जरिए सिनेमाघरों तक पहुंचती है. लेकिन टैक्स फ्री में छूट की लूट में ये सारे लोकतांत्रिक प्रावधान ताक पर हैं. हीरो-हिरोइनें मुख्यमंत्री से मिल कर फोटो खिंचवाती हैं और फिल्में फौरन टैक्स फ्री हो जाती हैं.

सरकारी खजाने में नहीं, जेबों में जा रहा मुनाफा

अभी उत्तर प्रदेश में खनन और फिल्म, ये दो धंधे खूब फल-फूल रहे हैं, लेकिन सरकारी खजाने को इससे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है. नेता, नौकरशाह, दलाल, ठेकेदार और फिल्मी वेशधारी व्यापारी मौज कर रहे हैं. 50 फीसदी फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश में करने पर अधिकतम एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है और 50 प्रतिशत से अधिक की शूटिंग पर सीधे दो करोड़ दे दिया जा रहा है. अगर वही फिल्म निर्माता प्रदेश में दूसरी बार फिल्म की शूटिंग करता है, तो उसे सरकार की ओर से सवा दो करोड़, तीसरी बार शूटिंग करने पर पर ढाई करोड़, चौथी बार फिल्म की शूटिंग करने पर पौने तीन करोड़ रुपये और पांचवी फिल्म के लिए पौने चार करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं. साथ ही फिल्मों में काम करने वाले यूपी के कलाकारों को 25 लाख रुपये अलग से मिल रहे हैं. अगर फिल्म में उत्तर प्रदेश के पांच मुख्य कलाकार हैं, तो उस फिल्म को 25 लाख रुपये का अनुदान और अगर सारे कलाकार यूपी के हैं, तो फिल्म को 50 लाख रुपये का अनुदान अलग से मिल रहा है. फिल्म निर्माता प्रदेश में फिल्म के जरिए यहां के पर्यटन स्थलों और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताता है, तो तो उसे 50 लाख रुपये का एक और अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है. अभी इतना ही नहीं है, फिल्म की प्रोसेसिंग यूपी में हो तो अनुदान का पिटारा खोल कर रख देने के और भी प्रावधान हैं. प्रोसेसिंग के लिए लिए 25 लाख रुपये अलग से मिल रहे हैं.

शूटिंग है या लूटिंग!

उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना खोल दिए जाने का नतीजा यह निकला है कि प्रदेशभर में फर्जी फिल्मों की फर्जी शूटिंग करने का धंधा चल निकला है. जिसे देखिए वही फिल्म निदेशक बन बैठा है और प्रदेश के लोगों पर फिल्मी कलाकार बनने का भूत सवार हो गया है. यह भूत नेताओं के बेटों, भतीजों, रिश्तेदारों और ठुल्लों पर अधिक सवार है. कोई मुख्यमंत्री की ऐक्टिंग कर रहा है, तो कोई विलेन, तो कोई हीरो, तो कोई हिरोइन बनी बैठी हैं. लखनऊ का कोई भी अच्छा घर दिख जाए, समझ लें वहां शूटिंग हो रही है. घर वालों को पैसे का लोभ दिखा कर शूटिंग हो रही है और शूटिंग करके पूरी फिल्मी टीम फरार हो जा रही है. घर वाले इसकी शिकायत शासन-प्रशासन को नहीं कर रहे, क्योंकि उनका कहना है कि शिकायत करने पर उल्टा उन्हें ही प्रताड़ित किया जाएगा. किससे पूछ कर शूटिंग की इजाजत दी थी. प्रशासन को पहले से आवेदन दिया था कि नहीं, जो पैसे मिले उसका हिसाब दो. वगैरह, वगैरह. ऐसे ही एक गृह स्वामी ने कहा कि फर्जी शूटिंग के क्लिप्स दिखा कर फर्जी फिल्म वाले सरकार से अनुदान तो ले गए, लेकिन उनके घर की ऐसी-तैसी करके फिल्म वाले फरार हो गए. आप शहर के होटलों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य सेवाएं मुहैया करने वाली एजेंसियों से बात करें, तो हैरतभरी जानकारियां हासिल होंगी. उनके पैसे लेकर फरार होने वालों में कई स्वनामधन्य फिल्म निर्देशक के नाम भी हैं, जिनके साथ मुख्यमंत्री बड़े गौरव से फोटो खिंचवाते हैं और सूचना विभाग से जारी करवाते हैं. ये लोग किसी को भी बाजार से दिहाड़ी पर उठा लेते हैं और उन्हें कलाकार दिखा कर शूटिंग करते हैं. कलाकारों की भीड़ में कई तो सरकारी कर्मचारी भी हैं, जो कैमरे के आगे आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं. फिल्मी अनुदान-लूट नीति या फार्मूला सभी भाषाओं की फिल्मों के लिए लागू है. लिहाजा, उत्तर प्रदेश में केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि बनारस, आगरा, इटावा, मथुरा, कन्नौज, इलाहाबाद, चित्रकूट, नोएडा, चंदौली, गोरखपुर, फैजाबाद, विंध्याचल और सोनभद्र जैसी जगहों पर फिल्मों की अंधाधुंध शूटिंग हो रही है. यह फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है कि झटको-उद्योग को, इसे आसानी से समझा जा सकता है. मिस टनकपुर या मसान जैसी कुछ फिल्में तो पर्दे पर दिख भी गईं, लेकिन उन अनगिनत फिल्मों का हिसाब-किताब कौन लेगा जो सरकारी अनुदान तो ले गईं, लेकिन बाकी लोगों को ठेंगा दिखा गईं?

केवल बजरंगी भाईजान ही नहीं, बल्कि एक साथ कई फिल्मों को टैक्स फ्री करने के धड़ाधड़ आदेश देने के बाद मनोरंजन कर विभाग मुंह के बल जा गिरा. राजस्व लक्ष्य हासिल कैसे हो जब टैक्स छूट की लूट मची हो. उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष में कई बड़ी फिल्मों को टैक्स फ्री किया है.

सलमान खान की बजरंगी भाईजान के अलावा, विद्या बालन और इमरान हाशमी की हमारी अधूरी कहानी, 600 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली आमिर खान की फिल्म पीके को टैक्स फ्री करने से भी उत्तर प्रदेश के मनोरंजन कर विभाग को करीब करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है. इसके अलावा अर्जुन कपूर की तेवर, माधुरी दीक्षित की डेढ़ इश्किया, प्रियंका चोपड़ा की मैरीकॉम और रानी मुखर्जी की मर्दानी ने बॉक्स ऑफिस पर तो अपनी जमकर कमाई कर ली, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की दरियादिली से टैक्स फ्री होने के चलते मनोरंजन कर विभाग को करोड़ों रुपये का नुकसान दे गई. उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ और फिल्मों, मसलन, मिस टनकपुर हाजिर हो, इश्क के परिंदे, मसान, जां निसार को भी टैक्स फ्री कर दिया है. बजरंगी भाईजान देखने अभी भी उमड़ रही दर्शकों की भीड़ देख कर मनोरंजन कर विभाग के कलेजे पर सांप लोट रहा है. विभाग के अधिकारी–कर्मचारी अब खुद ही टैक्स वसूली की तरफ उन्मुख नहीं हो रहे. उनका कहना है कि जब सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है, तो फिर वे अतिरिक्त उत्साह क्यों दिखाएं! विडंबना देखिए कि मनोरंजन कर विभाग ने पिछले वर्ष टैक्स के जरिए 41 करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन विभाग को मिले केवल कुछ लाख रुपये. इस साल विभाग ने 50 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया था. विभाग को आमिर खान की फिल्म पीके और सलमान खान की बजरंगी भाईजान से काफी उम्मीद थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे टैक्स–फ्री करके उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया. यह पूछने पर कि इस वर्ष अभी तक क्या मिला, तो विभाग के एक अधिकारी ने मुंह बना कर कहा, बाबा जी का ठुल्लू. केवल पीके को छूट मिलने से मनोरंजन कर विभाग को करीब 68 लाख रुपये का नुकसान हुआ था. बजरंगी भाईजान की कृपा से मनोरंजन कर के हो रहे नुकसान का इसी से आकलन किया जा सकता है. घाटे का ब्यौरा मुख्यालय से होते हुए बाकायदा शासन तक पहुंच गया है. ऐसा नहीं है कि सरकार को इस घाटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है और सरकार इनोसेंट है. शासन के एक अधिकारी ने कहा, टैक्स फ्री की छूट की लूट से होने वाले घाटे का बोझ केबल टीवी ऑपरेटरों पर डालकर सरकार उन्हें दुह लेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश की खबरें इंटरनेट पर पढ़ने के लिए www.up.chauthiduniya.com लॉगऑन करें.

दहकते खेत खलिहानों और उजड़ते किसानों वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तो बार-बार विदेश यात्राओं पर जाते रहते हैं, उन्हें तो आदत है, लेकिन इस बार वे अपने साथ राजेंद्र चौधरी को भी लंदन लेकर गए थे. ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले समाजवादी नेता राजेंद्र चौधरी ब्रिटेन के गांव और वहां की खुशहाली देख कर हतप्रभ हैं. वे चकाचौंध हैं कि इंग्लैंड ने अपने गांवों को इतना खूबसूरत और सम्पन्न कैसे बनाया. लेकिन वे साथ गए मुख्यमंत्री से यह नहीं पूछ पाए कि उत्तर प्रदेश के किसानों की जहालत के लिए कौन जिम्मेदार है? यूपी के गांवों को इंग्लैंड जैसे गांव बनाने में क्यों फिसड्डी साबित हुई हैं यहां की सरकारें? चौधरी जी को इंग्लैंड में भीख मांगते लोगों को देख कर शर्म आती है और अंग्रजों को रिक्शा खींचते देख कर उन्हें बहुत दुख होता है. भिखमंगों और गरीब रिक्शाचालकों की हिंदुस्तानी भीड़ को चौधरी जी की बातों से शर्म आएगी या गुस्सा, यह समझा जा सकता है. ब्रिटेन में पूंजीवादी व्यवस्था की लगभग नगण्य प्रतिशत की विषमता राजेंद्र चौधरी को खलती है और वे समाजवादी व्यवस्था की हिमायत करते हैं, लेकिन यह लिखने से परहेज कर जाते हैं कि समाजवादी व्यवस्था ने प्रदेश में विषमताओं की इतनी गहरी खाई क्यों खोद डाली है, जिसकी भरपाई अब कभी नहीं हो सकती. चौधरी जी इंग्लैंड में दूध की पूर्ण गुणवत्ता का जिक्र करते नहीं अघाते, लेकिन अपने यहां के दूध के पूर्ण प्रदूषित होने की कोई चर्चा भी नहीं करते. चौधरी जी कलकल बहती टेम्स नदी के किनारे खड़े होकर अखिलेश के साथ फोटो खिंचवाते हुए आह्लादित हो जाते हैं. उस समय उन्हें अपनी गंदली गोमती और प्रदूषित गंगा-यमुना याद नहीं आती. राजेंद्र चौधरी ने अपनी लंदन यात्रा का संस्मरण खुद अपनी कलम से लिखा है. आप उस लेख को पढ़ें तो आपको उत्तर प्रदेश के गांव-किसानों की पीड़ा खुद ब खुद दिखेगी. लंदन यात्रा की चकाचौंध वाली उनकी यादों और मुख्यमंत्री को खुश करने वाली ठकुरसुहाती के पीछे छाये घोर अंधेरे को आप कितना भांप पाते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है. पेश है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी का लेख...

लंदन, जैसा चौधरी जी ने देखा...

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ 22 जुलाई से 27 जुलाई तक ब्रिटेन यात्रा मेरी पहली विदेश यात्रा थी. इस यात्रा में जहां ब्रिटेन के पुराने साम्राज्य के प्रतीक चिन्ह दिखाई दिए वहीं उसके क्षरण के भी दृश्य देखे. संसद और शाही बकिंघम पैलेस देखा तो वहीं महान साहित्यकार शेक्सपीयर के गांव तक भी गए. सदियों पुरानी आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखी, तो क्रिकेट का लॉर्ड्स मैदान और हाईड पार्क जैसे स्थानों का भी अवलोकन किया. इस यात्रा में पुरातन के साथ नए बदलाव भी हमारे स्मृति पटल पर अंकित होते रहे. लंदन से 50 मील दूर गांव खेतों के बीच जाना इस यात्रा का सबसे सुखद और रोमांचक पक्ष रहा. यहां खेतों में भेड़ों की तादाद ज्यादा दिखी. खेतों में पीली सरसों की छटा दर्शनीय थी. यहां गेहूं और धान के अलावा सब्जी और फल की फसलें भी होती हैं. भारत के गांवों से भिन्न ब्रिटिश गांवों का रहन-सहन, उनके आवास और पशु बाड़े देखकर लगता ही नहीं कि ये किसानों की बस्ती है. हम भारत के लोगों के जेहन में अपने गांवो की ही तस्वीर रहती है जहां गांववासी अभावों और नागरिक असुविधाओं से जूझते दिखाई देते हैं. मुख्यमंत्री ने गम्भीरता से स्थितियों का आकलन किया और अपने यहां उनमें सुधार पर चिंतित दिखे. गांव, खेती और किसान उनकी प्राथमिकता में प्रारम्भ से रहे हैं. मुख्यमंत्री को इसकी चिन्ता है कि किसान और गांव कैसे खुशहाल हों. उन्होने लंदन में फल और सब्जियों की अच्छी क्वालिटी की ओर संकेत करते हुए मुझसे कहा कि अगर भारत में भी किसानों को सुविधाएं मिल जाएं, तो वे अच्छा उत्पादन कर सकते हैं. उनके उत्पादित माल का विपणन, मंडी की सुविधाएं तथा फसल का लाभकारी मूल्य मिले इसके प्रयास और तेज किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री जी का यह भी कहना था कि हम पश्चिम की हूबहू नकल नहीं कर सकते हैं. हमारे पास गांधीजी, चौधरी चरण सिंह, डॉ. लोहिया और मुलायम सिंह यादव के विचार तथा उनका मार्गदर्शन प्राप्त हैं. हमें भारतीय समाज व्यवस्था के अनुकूल अपनी नीतियों का प्रतिपादन करना होगा. इंग्लैंड की आबादी 3.5 करोड़ है, जिसका एक चौथाई हिस्सा यानी 92 लाख लोग लंदन में रहते हैं. यहां की अर्थव्यवस्था व्यापार, कृषि और पर्यटन पर आधारित है. यहां के लोग सम्पन्न तो हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग भीख और मदद मांगते देखे जा सकते हैं. बाजार और होटल में अंग्रेज प्लीज हेल्प मी की तख्ती लेकर भीख मांगते दिखाई दिए, यह शर्मनाक लगा. सम्पन्नता की चौंधियाने वाले लंदन की दुनिया में आज भी मानव चालित रिक्शों को देखकर सिर झुक जाता है, जहां अंग्रेज रिक्शा खींचता है. हिन्दुस्तान में डॉ. लोहिया ने इस सवारी की निन्दा की थी. वे कभी रिक्शा पर नहीं बैठे. उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बैटरी चालित रिक्शों को प्रोत्साहित किया है. ब्रिटेन में पूंजीवादी व्यवस्था फल-फूल रही है, उसके बावजूद बढ़ती विषमता इसके लिए अभिशाप साबित हो रही है. विकासशील और विकसित देशों के बीच का जो अंतर है वह तो समझ में आता है, लेकिन एक विकसित देश में भी सामाजिक विषमता की त्रासदी देखकर यही लगता है कि पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था ही मानवीय है.

ब्रिटेन की यात्रा में हम वहां की संसद, शाही परिवार के निवास स्थल बकिंघम पैलेस के साथ ईस्ट इंडिया कम्पनी के दफ्तर तक भी गए. सात समंदर पार देश के इन स्थलों से कभी हिन्दुस्तान का राजपाट चलाया जाता था. हमारी जिज्ञासा थी कि कैसे चन्द अंग्रेजों ने आकर भारत देश को आर्थिक, राजनीतिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा. ईस्ट इंडिया कम्पनी अब चाय की पत्ती बेचने का व्यवसाय करती है और वहां दार्जिलिंग की चाय भी मिलती है. यही नहीं, ईस्ट इंडिया कम्पनी आज भी चाय मुफ्त में पिलाती है. लंदन में दूध पूर्ण गुणवत्ता का मिलता है. दही और मक्खन बहुतायत में उपलब्ध है. उनके विक्रय केन्द्रों की समुचित व्यवस्था की गई है. उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कामधेनु योजना शुरू की है. इसके माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना है और गोवंश की सेहत भी इससे ठीक रहेगी.

लंदन में ऐतिहासिक इमारतों की भरमार है. यहां के बाजारों, होटलों तथा शिक्षण संस्थाओं की इमारते भी एक सदी से ज्यादा पुरानी हैं, लेकिन अभी भी मजबूती से खड़ी हैं. शाम के समय लंदन रंग बिरंगी रौशनी से नहाया हुआ बहुत शानदार और आकर्षक लगता है. हमने द्वितीय विश्वयुद्ध के समय ब्रिटिश कैबिनेट का वार रूम और तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का वार रूम भी देखा जहां गोपनीय बैठके होती थी. लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का स्थायी सरकारी निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट है. यहां उनका सचिवालय भी काम करता है.

लंदन में यातायात और परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद दिखाई पड़ती है. यहां टैक्सी कार हर वक्त उपलब्ध रहती है. इनकी साइज बहुत बड़ी नहीं है, जिससे ये सड़क पर ज्यादा स्थान घेर कर नहीं चलती है. इनका संचालन आसानी से हो जाता है. यहां दूरी नापने के लिए अभी भी मील का इस्तेमाल होता है. जबकि भारत में किलोमीटर से नाप होती है. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण नाम है. यह लंदन से 60 मील दूर है और शिक्षा का अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र है. इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी. यहां 38 कालेज और 6 स्थायी निजी रिहायशी हाल हैं. दुनिया के 26 प्रधानमंत्री यहां शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं. दुनिया के 10 नामी विश्वविद्यालयों और दुनिया की तीन सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में इसका नाम है.

लंदन से दो घंटे का सफर कर हम शेक्सपीयर के गांव स्ट्रैटफोर्ड पहुंचे. शेक्सपीयर जन्म 1564 में हुआ था और मृत्यु 1616 में हुई. दुनिया के मशहूर नाटककारों में उनका नाम है. यहां एक चर्च है और इसके पास ही महान अंग्रेज नाटककार की कब्र है. चार सौ साल बीत जाने के बावजूद उनकी स्मृति को आज भी जिन्दा रखा गया है. हमने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए. लंदन में हाइड पार्क है जहां आपको भाषण देने की आजादी है. यह साढ़े 3 सौ एकड़ में फैला है जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार द्वारा बनाया गया जनेश्वर मिश्र पार्क 4 सौ एकड़ में फैला हुआ है. यहां हाइड पार्क में लीडो कैफे है जो सरपेंटाइन लेक के किनारे है. यहां अखिलेश यादव के साथ कॉफी पीने का हमें मौका मिला.

ब्रिटिश संसद भवन के सामने गांधी जी और चर्चिल की प्रतिमाएं स्थापित हैं. ब्रिजटावर्स के निकट की किलानुमा बिल्डिंग में कोहिनूर हीरा सुरक्षित है, जो कभी भारत के बादशाहों के ताज को शोभा देता था. इसकी वर्तमान कीमत लगभग 150 हजार करोड़ रुपये है. 105 कैरेट का यह हीरा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताज में जड़ा है. यह मुगलों के पास सन् 1739 तक रहा था. बाबरनामा में लिखा है कि यह हीरा सन् 1294 में मालवा के एक राजा का था. बाद में यह हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पास भी रहा था. लंदन का वाशिंगटन होटल, जहां हम ठहरे थे, में कभी हिन्दी फिल्मों के सदाबहार हीरो देवानन्द भी ठहरते थे. होटल की खिडकियों से सुबह शाम साइकिलों पर लोगों को घर-दफ्तर और बाजार आते जाते देखना सचमुच अच्छा लग रहा था. साधारण ही नहीं अमीर और उच्च पदस्थ अफसर भी साइकिल से आते जाते दिखाई दिए. हजारों की संख्या में युवा वर्ग लंदन में साइकिल की सवारी करना पसंद करता है. यहां साइकिले प्रत्येक चैराहे पर किराये पर मिल जाती हैं. लंदन में ईस्ट वेस्ट साइकिल सुपरहाई वे सेंट्रल लंदन लंकास्टर गेट से टावर हिल तक बन रहा है, जो सन् 2016 तक बनकर तैयार होगा. अभी हाइड पार्क कार्नर से विक्टोरिया इम्बैंकमेंट तथा अपर लोअर टेम्स स्ट्रीट पर अप्रैल, 2015 से काम चालू है. उत्तर प्रदेश में भी साइकिल से यात्रा को समाजवादी सरकार प्रोत्साहित कर रही है और राजधानी लखनऊ में तो कई साइकिल ट्रैक बन भी गए हैं. इनका और भी विस्तार होगा. इंग्लैंड प्रवास में हम टेम्स नदी के किनारे लंदन आई देखने भी गए. इसमें ऊपर जाकर पूरे लंदन का दृश्यावलोकन किया जा सकता है. इसी तर्ज पर लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में लखनऊ आई से लखनऊ देखा जा सकेगा.

हम विदेश में थे, तो यहां भी अखिलेश यादव के प्रशंसकों की भीड़ उनके पीछे थी. उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत के दूसरे राज्यों के नागरिक जो लंदन घूमने आए थे, सभी ने मुख्यमंत्री जी को अपना-अपना परिचय दिया और उनके साथ फोटो खिंचवाई. लंदन में बसे अन्य प्रांतों के लोग भी उनसे मिलने आए और उन्हें अपने घरों में आने का आमंत्रण दिया. ■

feedback@chauthiduniya.com

दलित किसी को बेच सकेंगे अपनी ज़मीन

सूफी यायावर

केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश से किसानों की सहमति की अनिवार्यता का हिस्सा काट दिया, तो पूरे देश में बवाल मच गया. केंद्र सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए सारे विपक्षी दलों ने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी पर खूब प्रहार किया. अब उत्तर प्रदेश सरकार ने दलितों को जमीन बेचने की इजाजत देकर फिर से सामंती शोषण का रास्ता प्रशस्त कर दिया है. इस पर कोई कुछ बोल नहीं रहा. अखिलेश सरकार ने दलितों को अपनी जमीन बेचने और किसी भी व्यक्ति को दलितों की जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया है. दलितों को बहला-फुसला कर, प्रलोभन देकर या धमकी देकर उनसे जमीन लिखवा ली जाती थी. सामंत शोषण के उस तौर-तरीके को रोकने के लिए यह कानून बनाया कि कोई दलित अपनी जमीन न बेच सके और कोई दलित की जमीन खरीद नहीं सके. दलितों के जमीन खरीदने बेचने वाले प्रावधान अत्यंत सख्त थे.

अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों को जिलाधिकारी की अनुमति से अपनी खेती की जमीन गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने का हक देने का फैसला किया है. इसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 में संशोधन लाएगी. अधिनियम में संशोधन के लिए अखिलेश कैबिनेट ने पिछले दिनों यह विवादास्पद फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2015 के प्रारूप पर मुहर लगा दी. सरकार अब इस विधेयक को मानसून सत्र में विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-157 (क) में अनुसूचित जाति के भूमिधर को कलक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपनी जमीन बेचने, दान करने या उसका पट्टा देने का अधिकार नहीं है. इस सिलसिले में प्रतिबंध यह है कि अनुमति देने से पहले कलक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि जमीन बेचने पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पास कम से कम 3.125 एकड़ (1.26 हेक्टेयर) जमीन बच रही है कि नहीं. यदि उसके पास इससे कम जमीन बच रही होगी, तो जिलाधिकारी उसे जमीन बेचने की अनुमति नहीं देते थे. लेकिन अब सरकार का मानना है कि इस प्रतिबंध के कारण अनुसूचित जाति का भूमिधर आसानी से अपनी जमीन बेच नहीं पाता. सरकार का तर्क है कि पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का विभाजन होने और आबादी बढ़ने के कारण औसत जोत का आकार लगातार घट रहा है. इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों के जमीन बेचने पर क्षेत्रफल का प्रतिबंध अब प्रासंगिक नहीं रह गया है. लिहाजा अधिनियम के प्रावधान को सरल बनाने की जरूरत है. प्रावधान को सरल बनाने के लिए सरकार विधेयक के जरिए अधिनियम में संशोधन कर धारा-157 (क) के परंतु को हटाना चाहती है. सरकार का मानना है कि अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन से अनुसूचित जाति के भूमिधरों

के हितों की सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 65 साल पुराने और अप्रासंगिक हो चुके तीन दर्जन से ज्यादा राजस्व कानूनों को भी हटा दिया है. 9 साल की कवायद के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया. नई राजस्व संहिता के मुताबिक अब प्रदेश में दलितों के लिए गैर-दलित को अपनी जमीन बेचना आसान हो जाएगा. हालांकि इसके लिए उन्हें पहले की तरह जिलाधिकारी से मंजूरी लेनी होगी. इसके तहत दलितों के पास 3.125 एकड़ से कम जमीन होने पर उन्हें गैर दलितों को बेचने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा. पहले के कानूनों के मुताबिक जिलाधिकारी की अनुमति से दलित काश्तकार अपनी 3.125 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी की जमीन बेच सकता था. अब बदली व्यवस्था में दलित के पास अगर 3.125 एकड़ से कम जमीन भी शेष है, तो उसे वह गैर दलित को तीन शर्तों के साथ बेच सकता है. राजस्व संहिता में किए गए बदलावों के मुताबिक इसमें पहली शर्त यह होगी कि जमीन बेचने वाले दलित का कोई वारिस न हो. दूसरी, अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश में या कहीं और बस गया हो और तीसरी शर्त कि परिवार के किसी सदस्य के जानलेवा बीमारी से ग्रस्त होने पर विपदा की स्थिति में ईलाज के लिए जमीन बेचना उसके लिए जरूरी हो गया हो. राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 का प्रारूप तैयार करने के लिए अपर महाधिवक्ता राज बहादुर सिंह यादव की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति ने सरकार से राजस्व कानून में संशोधन की यह सिफारिश की है. विधानमंडल के आगामी सत्र में इसे पेश करने की तैयारी है. विधानमंडल और राज्यपाल की अनुमति के बाद यह कानून लागू हो जाएगा.

इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने ताजमहल के पूर्वी गेट के निकट स्थित शिल्प ग्राम को ध्वस्त करने का भी फैसला किया है. शिल्प ग्राम को ध्वस्त कर वहां नए सिरे से ताज ओरिएंटेशन सेंटर परियोजना के निर्माण का काम शुरू होगा. सरकार में बैठे अधिकारी ही इस फैसले को कमाई का नया जरिया बता रहे हैं. फैसले के मुताबिक ताजमहल के पूर्वी गेट के निकट स्थित शिल्प ग्राम को ध्वस्त कर ताज ओरिएंटेशन सेंटर, शिल्प ग्राम का फिर से निर्माण होगा. इस योजना के लिए उद्योग विभाग की 11.50 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को मुफ्त में हस्तांतरित करने का निर्णय भी लिया गया है. इस विचित्र किन्तु सत्यनुमा परियोजना के सम्बंन्ध में आगे की कार्रवाई के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को ही अधिकृत कर दिया है. इस परियोजना के निर्माण के लिए बजट की व्यवस्था राज्य सरकार की अवस्थापना निधि से की जाएगी. निर्माण कार्य में प्रस्तावित आवश्यक खर्चों को भी अनुमोदित कर दिया गया है. परियोजना के अनुश्रवण एवं मॉनिटरिंग के लिए स्टेट तथा फील्ड लेवल कमेटी गठित की जाएगी. स्टेट लेवल कमेटी का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है, जिसके सदस्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन होंगे. जबकि फील्ड लेवल कमेटी आगरा मंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में गठित की जाएगी. पर्यटन विभाग का क्षेत्रीय अधिकारी इसका सदस्य सचिव नामित किया गया है. दोनों कमेटियों में विभिन्न विभागों के अधिकारी सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं. आगरा में मुगल म्यूजियम की स्थापना के लिए भी प्रदेश सरकार ने बिजली विभाग की 5.9 एकड़ जमीन मुफ्त में भूमि पर्यटन विभाग को दे दी है. इस जमीन पर ताजमहल से लगभग 1300 मीटर की दूरी पर मुगल म्यूज़ियम की स्थापना होगी. म्यूज़ियम परियोजना के निर्माण कार्य के लिए 12966.49 लाख रुपये के प्रस्ताव को सैद्धान्तिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है. इसके लिए पर्यटन विभाग के अनुदान में अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट की व्यवस्था का निर्णय लिया गया है. साथ ही, परियोजना के निर्माण कार्य में प्रस्तुत विभिन्न विशिष्टियों के प्रावधान की अनुमति भी दे दी गई है. परियोजना के निर्माण के बाद इसकी संरचना एवं संचालन हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा. इस समिति में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के वास्तुविद, म्यूजोलॉजिस्ट, विषय-विशेषज्ञ एवं इस क्षेत्र में कार्य कर रहे संस्थानों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार मुगल म्यूज़ियम के लिए आर्टिफेक्टस एवं मुगलकाल से सम्बन्धित वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा. संचालन हेतु विख्यात एवं प्रतिष्ठित संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है. इसके उपरान्त सक्षम स्तर की संस्था द्वारा चयन किया जाएगा. परियोजना के अनुश्रवण एवं मॉनीटरिंग किए जाने हेतु स्टेट एवं फील्ड लेवेल कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है. स्टेट लेवल कमेटी की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे. पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर राज्य सरकार ने 36 जिलों में पर्यटन प्रोत्साहन परिषद का गठन करने का भी फैसला किया है. पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 36 जनपदों गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, बरेली, फर्रूखाबाद, पीलीभीत, बाराबंकी, रायबरेली, रामपुर, गाजियाबाद, जौनपुर एवं गाजीपुर में जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. जिला पर्यटन प्रोत्साहन परिषद के जरिए समाजवादी पार्टी की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा, इसका दायित्व भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ही संभाल लिया है. अभी शासन यह बता रहा है कि समिति में सम्बन्धित जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, सम्भागीय वनाधिकारी, नगर आयुक्त, क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक राज्य सड़क परिवहन निगम, जिला सूचना अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, लोनिविभाग, क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी को सदस्य एवं जिला कोषाधिकारी को कोषाध्यक्ष तथा पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी सचिव नामित किए जाएंगे. सम्बन्धित जिले के सांसद, महापौर एवं अध्यक्ष जिला पंचायत विशेष आमंत्री के रूप में नामित किए जाएंगे. ■

सूबे की जेलें ठसाठस भरी हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

जेलों में विचाराधीन कैदियों की भीड़ पर जबसे सुप्रीम कोर्ट गंभीर हुई है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से इस मामले में अद्यतन रिपोर्ट लेनी शुरू की है, तबसे उत्तर प्रदेश सरकार भी विचाराधीन कैदियों के मामले निपटाने की तरफ उन्मुख हुई है. केंद्र की नोटिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विचाराधीन कैदियों की रिहाई की ताजा स्थितियों के बारे में अवगत कराया है. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिख कर इस मामले में तकनीकी पेंच जरूर फंसा दिया है, लेकिन यह आधिकारिक तौर पर माना भी है कि प्रदेश की जेलों में कैदियों के लिए अब जगह नहीं बची है.

सरकार यह स्वीकार कर रही है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में कैदी ठसाठस भरे पड़े हैं, इनमें अधिक संख्या विचाराधीन कैदियों की है. प्रदेश की जेलों में अब अगर और बंदियों को रखना है, तो अब जेलों में जगह नहीं बचा. ऐसे में बड़ा सवाल है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त कैसे बनाया जाए. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को लिखे पत्र में यह बात कही है. अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने यह जरूर बताया है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के जरिए ई-प्रिजन सॉफ्टवेयर को सूबे की जेलों को ई-प्रिजन उत्तर प्रदेश के नाम से लैस किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की नौ जेलों में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग इकाइयों के माध्यम से विचाराधीन बंदियों की रिमांड भी कराई जा रही है. लेकिन इनसे हालात संभलने की स्थिति नहीं है. 25 जेलों में ब्रॉड बैण्ड आधारित प्रक्रिया से भी बंदियों की रिमांड हो रही है. इसके बावजूद जेलों में कैदियों की संख्या के बनी स्थिति को ओवर-क्राउडेड ही कहा जा सकता है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को प्रदेश के कारागारों में विचाराधीन कैदियों की भीड़ कम करने के लिए उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-436-ए और 436 (1) का लाभ देने के संबंध में पत्र लिखा है. पत्र के जरिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राष्ट्री सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा संरचित ई-प्रिजन सॉफ्टवेयर को उत्तर प्रदेश के कारागारों में ई-प्रिजन उत्तर प्रदेश के नाम से क्रियान्वित किए जाने के लिए यूपी सरकार ने 429.78 लाख रुपये की कार्य योजना स्वीकृत की है तथा एनआईसी के सहयोग से इस कार्य योजना को प्रारम्भ भी कर दिया गया है. एनआईसी द्वारा ई-प्रिजन उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर को प्रदेश के कारागारों में संचालित किए जाने के दौरान विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार लागू भी किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सॉफ्टवेयर में प्रिजनर्स मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस) एप्लीकेशन मॉड्यूल में धारा-436-ए और 436 (1) से आच्छादित बंदियों की सूचना फीड किए जाने का भी प्रावधान किया गया है. इस एप्लीकेशन मॉड्यूल में कारागारों में निरुद्ध बंदियों की सूचनाएं फीड हो जाने के

पश्चात इसके ऑनलाइन स्वरूप में इसे किसी भी स्तर पर देखा जा सकेगा. इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह धारा-436-ए और 436 (1) से आच्छादित बंदियों की सूचना एकत्रित कर जनपद के सीजेएम को प्रस्तुत की जाती है. वर्ष-2014 में प्रदेश के कारागारों में धारा-436-ए से आच्छादित पात्र कुल 3922 बंदियों में से 804 बंदियों को रिहाई का लाभ प्राप्त हुआ. इसी प्रकार धारा 436 (1) से आच्छादित पात्र कुल 23,289 बंदियों में से 19,702 बंदियों को रिहाई का लाभ प्राप्त हुआ. यह प्रक्रिया प्रदेश के सभी कारागारों में नियमित रूप से संचालित हो रही है.

मुख्यमंत्री ने बीपीआर एंड डी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल प्रिजन मैनुअल को प्रदेश सरकारों द्वारा लागू किए जाने की भारत सरकार की अपेक्षा के क्रम में अवगत कराया कि मॉडल प्रिजन मैनुअल के स्वीकार्य प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल संशोधन हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित जेल मैनुअल का ड्राफ्ट विचाराधीन है, जिसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा. प्रदेश के सभी कारागारों में माह में एक बार लोक अदालतों का आयोजन कर लोक अदालत में प्रस्तुत किए जाने हेतु पात्र विचाराधीन बंदियों के मामलों को प्रस्तुत करने के आदेश पूर्व से निर्गत है, तथा सभी कारागारों में इसका नियमित रूप से आयोजन हो रहा है. जिसके फलस्वरूप वर्ष-2014 में प्रदेश के सभी कारागारों में कुल 880 लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिनमें 17,283 विचाराधीन बंदियों के मामले प्रस्तुत किए गए, जिसके फलस्वरूप कारागारों से कुल 3,118 बंदी रिहा हुए. वर्तमान में उत्तर प्रदेश की नौ कारागारों में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग इकाइयों के माध्यम से विचाराधीन बंदियों की रिमांड कराई जा रही है. इसके साथ ही 25 कारागारों में ब्राड बैंड आधारित प्रक्रिया से भी बंदियों की रिमांड हो रही है, जिसके फलस्वरूप अभी तक पांच लाख से अधिक बंदियों की रिमांड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करायी जा चुकी है. नौ कारागारों के अतिरिक्त शेष सभी कारागारों में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग इकाइयों की स्थापना की कार्यवाही प्रचलित है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सभी कारागारों में दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 के पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की स्थापना कराकर संचालित कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक पत्र के माध्यम से प्रदेश के कारागारों में विचाराधीन कैदियों की भीड़ कम किए जाने के दृष्टिगत विचाराधीन बंदियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-436-ए तथा 436 (1) का लाभ प्रदान किए जाने एवं विचाराधीन बंदियों की रिमाण्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए जाने के संबंध में जानकारी मांगी थी. इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है. ध्यान रहे कि सीआरपीसी की धारा 436-ए के तहत ऐसा प्रावधान है कि संभावित सजा का आधा समय अगर किसी कैदी ने विचाराधीन रहकर ही गुजार दिया हो, तो उसे निजी मुचलके पर जमानत दी जा सकती है. मगर इस प्रावधान के बावजूद लम्बी खिंचती हुई क़ानूनी प्रक्रिया की वजह से विचाराधीन कैदी जेलों में बंद रहते हैं और उन्हें राहत नहीं मिल पाती.

आम लोगों से जुड़े मसलों को सरकारें इसी तरह की ऊबाऊ सरकारी भाषावली में उलझा देती हैं और आम लोगों के सरोकार से जुड़े मामले यूं ही लंबित पड़े रहते हैं. जेलों में विचाराधीन कैदियों का मसला भी ऐसा ही है. आधिकारिक तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में जेलों की हालत बहुत खस्ता है. जेलों में निर्धारित क्षमता से बहुत अधिक कैदी ठुंसे हुए हैं. सजायाफ्ता कैदियों की तादाद से तीन-चार गुना अधिक विचाराधीन कैदी हैं. उत्तर प्रदेश की जेलें यातना गृह के रूप में तब्दील हो चुकी हैं. आधिकारिक आंकड़ा बताता है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में करीब 90 हजार कैदी हैं, जबकि यहां की जेलों में केवल 48298 कैदियों के रखने की ही क्षमता है. प्रदेश की जेलों में कैदियों की 167 प्रतिशत से अधिक भीड़ है. यह भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है, जबकि जेलों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है. जेलों में बन्द दो तिहाई से अधिक कैदी ऐसे हैं, जिनके मामले अदालतों में विचाराधीन पड़े हैं. उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद 90 हजार कैदियों में विचाराधीन कैदियों की संख्या 66 हजार और सजा याफ्ता (दोष सिद्ध) कैदियों की तादाद 26 हजार है. विचाराधीन कैदियों की इतनी भारी तादाद न्यायिक-शासनिक दुर्गति बताने के लिए काफी है. न्याय में अवांछित देरी और सरकार की भीषण लापरवाही की वजह से भारी भीड़ अकारण जेलों में बंद है.

इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से कहा था कि वे जेलों का निरीक्षण कर ऐसे क़ैदियों को निजी मुचलके पर रिहा करें, जिनका मामला लंबे समय से विचाराधीन है और उन्होंने संभावित सजा का आधा समय जेल में बिता दिया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश भी ढाक के तीन पात होकर ही रह गया. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की कुछ समय पहले की रिपोर्ट बताती है कि देश में सबसे ज़्यादा कैदी उत्तर प्रदेश की जेलों में हैं जहां इनकी संख्या 83, 518 है. इन कैदियों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर समाज के पिछड़े तबके से ताल्लुक रखते हैं. इस समय क्षमता से 118.4 प्रतिशत अधिक कैदी भरे हुए हैं. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी यह कह चुका है कि जेलें सजायाफ्ता कैदियों के लिए हैं न कि विचाराधीन बंदियों के लिए, लेकिन भारत में कौन किसकी सुनता है! ■

feedback@chauthiduniya.com

बीमार कैदियों की भारी भीड़

उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक वक्तव्य है कि राज्य की जेलों में बीते एक साल में 28 लाख से ज्यादा बार बीमार कैदियों ने अपना इलाज कराया. 44 हजार से अधिक कैदी तो इलाज के लिए अस्पतालों में बाकायदा भर्ती कराए गए. राज्य की जेलों में बंद कैदी विभिन्न बीमारियों से ग्रसित पाए गए, जिनमें अधिकांश टीबी के मरीज हैं. बीमार कैदियों के पिछले दो साल का आंकड़ा कारागार मंत्री बलराम यादव ने सदन में रखा था. वर्ष 2012-13 में इलाज के लिए कैदियों की 26 लाख 33 हजार 226 बार इंट्री हुई. इनमें 43 हजार 34 कैदियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसी तरह वर्ष 2013-14 में 28 लाख 84 हजार 177 बार इंट्री हुई और 44 हजार 366 कैदियों को इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया. पिछले दो साल में कैदियों के इलाज पर सरकार ने 11 करोड़ 97 लाख 16 हजार 277 रुपये खर्च किए. यह आंकड़ा पेश करने वाले कारागार मंत्री यह नहीं बता पाये कि बीमार कैदियों में उस तरह के रसूखदार कैदी कितने हैं जो जेल काटने के बजाए बीमारी का बहाना बनाकर अस्पतालों में भर्ती हो जाते हैं. यह आम बात है कि गिरफ्तार होते ही सामर्थ्यवान कैदी जेल जाने से बचने के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं. ऐसे अपराधियों के लिए यूपी की जेंलें बेहतर रिसॉर्ट बन गई हैं. छापों में जेल से तमाम आपत्तिजनक सामाग्रियां बरामद होती रहती हैं. दबंग अपराधी जेल की कोठरियों में बंद रहने के बजाए अस्पताल में आनंद ले रहे हैं. राज्य सरकार का उन्हें संरक्षण प्राप्त होता है. यहां तक कि जेल प्रशासन के सहयोग से अपराधी जेल और अस्पतालों में रहकर आपराधिक गतिविधियों को भी अंजाम दे रहे हैं. ■

हेलिकॉप्टरों के शोर से केदार घाटी का इको सिस्टम प्रभावित

-राजकुमार शर्मा

केदारनाथ धाम के लिए संचालित हेलिकॉप्टरों की उड़ानों के शोर से केदार घाटी का इको सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जिसका बुरा असर ग्लेशियरों पर पड़ने के साथ वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है. शेड्यूल एक के विलुप्तप्राय थार, और कस्तूरी मृग समेत अन्य कई वन्यजीव अपना पुश्तैनी घर (केदारनाथ वन्यजीव विहार) छोड़कर भाग रहे हैं. दुर्लभ हिमालयन गिद्धों की प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है और तितलियों के वतन छोड़ने से कई वनस्पतियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. ये तथ्य उपवन

संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर की रिपोर्ट का ऐसा सनसनीखेज सच है, जिन्हें वन विभाग की फाइलों में उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों ने दफन कर दिया, जिन पर जंगल और वन्यजीवों के सुरक्षा की जिम्मेदारी है. यह रिपोर्ट दो साल पुरानी है, इसको लेकर जिम्मेदार अधिकारी कह सकते हैं कि उतनी पुरानी रिपोर्ट के हवाले से अब सवाल उठाने से क्या फायदा. सूबे की सरकार केदार घाटी में थोड़े आर्थिक लाभ के चलते भगवान के अतूल्य, अमूल्य वन जीवों को खोने की स्थिति के बावजूद आंख कान बन्द कर रखी है. राज्य के वन्यजीव प्रेमियों की उन्हें बचाने की गुहार नक्कारखाने में तूति की आवाज़ सिद्ध हो रही है. केदारनाथ वन्य जीव विहार से पलायन कर रहे वन्य जीवों के लिए दोषी कौन, यह जांच के बाद तय होगा. हेलीकॉप्टर कंपनियां खुद को अनजान साबित करने के लिए अजीब तर्क गढ़ रही हैं. केदारनाथ वन्य विहार के ऊपर से उड़ान भरने वाली हेलीकॉप्टर कंपनियों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं कि उस क्षेत्र में उड़ान भरने के लिए वन विभाग से एनओसी लेने की जरूरत है. कंपनियों का कहना है कि अगर एनओसी जरूरी थी, तो उडयन विभाग को बैठकों में बताना चाहिए था. उनका यह तर्क तब है जब डीएम चमोली के आदेश में स्पष्ट है कि वन्य जीव जंतु क्षेत्र तथा प्रतिबंधित क्षेत्र के ऊपर से उडान न भरी जाए. केदारनाथ वन्य विहार के ऊपर से उडान भरने वाली हेलीकॉप्टर कंपनियां भी मान रही हैं कि प्रमुख वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखंड से एनओसी नहीं ली. ■

feedback@chauthiduniya.com

स्वजल ने किया नाली निर्माण में लाखों का गबन

-चौथी दुनिया ब्यूरो

स्वजल परियोजना अधिकारियों की मनमर्जी के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है. मात्र तीन महीने के कार्यकाल में पूर्व परियोजना प्रबंधक ने पाइपों की खरीद में करीब 20 लाख रुपये का गोलमाल किया. इसके अलावा कई अन्य मदों में भी भारी गड़बड़ी सामने आयी है. मजेदार बात यह कि उस भ्रष्ट अधिकारी की एक कांग्रेसी विधायक व जिला पंचायत के 17 सदस्यों ने एकमत होकर पैरवी की है. केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्वच्छता के लिए ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना स्वजल हमेशा से ही विवादों में रही है. गाहे बगाहे शौचालय निर्माण में लेन-देन के आरोपों से बदनाम स्वजल अब नाली निर्माण के घोटाले में घिर गया है. यहां पर तैनात पूर्व परियोजना प्रबन्धक पर आरोप है कि उन्होंने मानकों की पूरी तरह अनदेखी करते हुए नाली निर्माण की जगह प्लास्टिक के पाइप बिछा दिए, जिस कारण योजना अपने मूल उद्देश्य को पूरा नहीं कर पायी. कागजों में नाली निर्माण दिखाया गया, जबकि धरातल पर प्लास्टिक के पाइप बिछे हुए हैं. उन पाइपों की खरीद में भारी वित्तीय अनियमितता सामने आयी है. बाजार में चार सौ रुपये मूल्य पर उपलब्ध पीबीसी पाइप को आठ सौ रुपये में खरीदा गया. कागजों में सैकड़ों पाइपों की खरीद है, जबकि मौके पर हकीकत कुछ और ही है. जलेथा गांव में 160 पाइपों की खरीद का बिल दिया गया, जबकि ग्राम प्रधान के अनुसार उन्हें मात्र 25 ही पाइप मिले. मजेदार बात यह है कि एक ही दिन में कोटेशन व बिल दर्शाए गए हैं. नाली निर्माण के लिए दस रुपये में मिलने वाली ईंट भी 46 रुपये प्रति के हिसाब से खरीदी गई हैं. यही नहीं पाइपों की खरीद निर्माण स्थल से सैकड़ों किलोमीटर दूर से की गई. खरीद फरोख्त का कार्य ग्राम स्तर पर गठित उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति का होता है. आरोप है कि परियोजना प्रबन्धक ने जबरन समिति से पैसे वसूलकर स्वयं खरीद की. राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने के लिए शौचालय निर्माण के लाभार्थियों को जनप्रतिनिधियों के हाथों चेक बंटवाए गए, जबकि नियमानुसार सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाना था. भ्रष्ट एवं विवादित कार्यशैली के चलते शासन ने आरोपित परियोजना प्रबन्धक का स्थानान्तरण तैनाती के तीन माह के भीतर ही कर दिया था, जिले के एक कांग्रेसी विधायक व जिला पंचायत पौड़ी के 17 सदस्यों ने उस भ्रष्ट अधिकारी की खुलकर पैरवी की व स्थानान्तरण रोकने में कामयाब रहे. बाद में भ्रष्टाचार की हदें पार होने पर शासन को मजबूरन उस अधिकारी को हटाना पड़ा. अब घोटाले उजागर होने पर उक्त अधिकारी एवं उसके द्वारा की गई खरीद फरोख्त की जांच बैठा दी गई है.

ग्रामसभा को नाली निर्माण के लिए स्वजल की ओर से 2 लाख 76 हजार रुपये की धनराशि का चेक दिया गया था, बाद में स्वजल के कर्मचारी जबरन उस धनराशि में से एक लाख 30 हजार रुपये पाइप खरीदने के लिए ले गए. बिल में 160 पाइप दर्शाए गए हैं, जबकि मुझे मात्र 25 पाइप ही दिये गए.

इन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान जलेथा, जयहरीखाल.

स्वजल विभाग में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिली है. मौके पर जांच टीम को भेजा गया, लेकिन अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है.

सोनिका, मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी, उत्तराखंड.

feedback@chauthiduniya.com

शराब व्यापारी को महामण्डलेश्वर बनाने पर बवाल

-रेनू शर्मा

बीयर बार संचालक, शराब माफिया पोंटी चड्ढा के दाहिने हाथ कहे जाने वाले सचिन दत्ता के स्वामी सच्चिदानंद गिरि के रूप में महामंडलेश्वर बनने के बाद मचे बवाल के बीच यह बहस भी तेज हो गई है कि इस महत्वपूर्ण पदवी के लिए परंपराओं और नियमों को ताक पर क्यों रखा गया. 31 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन सचिन गृहस्थ जीवन से संन्यासी बने और इसी दिन उन्हें राजनेता के दबाव व धन बल के प्रभाव के चलते महामंडलेश्वर भी बना दिया गया. नई अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने भी स्वीकार किया कि दोनों रस्में गुरु पूर्णिमा के दिन ही निभाई गईं. इस कार्यक्रम में सपा सुप्रिमों मुलायम सिंह यादव के अनुज शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि संत समाज भी अपनी सम्मानित पदवी राजनेताओं के दबाव में मजबूर हो कर बाट रहा है. उस अवसर पर हेलिकॉप्टर से जिस तरह पुष्प वर्षा की गई इससे साफ हो गया की श्रेष्ठ संत बनने के लिए श्रेष्ठ सेवा की जगह कालाधन होना जरूरी है. उस घटना के बाद मचे बवाल के बाद आखाड़ा परिषद ने उस नकली संत को सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेने पर रोक लगा दी है. महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविन्द्रपुरी महाराज के अनुसार संन्यास की प्रक्रिया जटिल है और महामंडलेश्वर बनने के लिए संन्यासी होना अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि संन्यास की प्रक्रिया दो तरीके से संपन्न कराई जाती है. पहली बाल्यकाल और दूसरी गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद. गृहस्थ आश्रम से वनप्रस्थ आश्रम में प्रवेश के दौरान वह व्यक्ति किसी अखाड़े से जुड़े. बड़ा अखाड़ा उदासीन के महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अखाड़ों में कम से कम दस वर्ष तक धर्म और लोक सेवा करनी होती है. उन लोगों के आचार-व्यवहार पर अखाड़े के प्रमुख संतों की समिति नजर रखती है. समिति के मानदंडों पर खरा उतरने के बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कुंभ में विधि विधान के साथ संन्यास दीक्षा देते हैं. संन्यास दीक्षा में व्यक्ति को अपना मुंडन संस्कार, क्रिया-कर्म व पिण्ड-दान करना होता है. पिण्डदान के बाद संन्यासी बनाने की प्रक्रिया का सबसे अहम पड़ाव है विजयाहोम इसे आचार्य महामंडलेश्वर संपादित करते हैं. इस प्रक्रिया को सार्वजनिक नहीं किया जाता. जूना अखाड़े से जुड़े समाजसेवा का कीर्तिमान स्थापित करने वाले जयराम संस्थाओं के पीठाधीश्वर कर्मयोगी ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी (पूर्व कुलपति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय) कहते हैं कि संत हृदय नव नीत समाना एक व्यक्ति को संत बनाने से पहले गुरू उसके तन, मन एंव हृदय तक की जांच करता है, राजनेताओं के दबाव में श्रेष्ठता की पदवी वितरण को ब्रह्मचारी जी खतरनाक बताते हैं और संत, समाज दोनों को सावधान करते हैं.

भारत साधु समाज के राष्ट्रीय सचिव स्वामी ऋषिश्वरानंद ने बताया कि अखाड़े में रहने के दौरान उस व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम के नियम-कायदे का धर्म सम्मत तरीके से पालन करते हुए धर्म, शास्त्र, वेद, पुराण और अन्य धर्मग्रन्थों का पठन-पाठन करना होता है. सन्यास दीक्षा पूरी करने के बाद वह अखाड़े में फिर से सेवा कार्य करता है और उस दौरान अखाड़े के प्रमुख संतों की समिति उसके आचार व्यवहार पर नजर रखती है. उसके बाद यदि वह मानदंडों में खरा उतरता है तो समिति की सिफारिश पर उसे महामंडलेश्वर की पदवी के लिए चुना जाता है. अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता बाबा हठयोगी बताते हैं कि अखाड़े में महामंडलेश्वर की अपनी मंडली होती है. इन सब बवाल के बीच निरंजनी अखड़ा ने महामंडलेश्वर सच्चिदानंद को निष्कासित कर दिया है.

महामंडेलेश्वर बनने के नियम

महामंडलेश्वर बनने के लिए नियम-सनातन धर्म और देवी-देवताओं में आस्था,दस वर्षों तक अखाड़े में धर्म सेवा का कार्य किया हो, हिदू धर्म, वेद, पुराण और अन्य धर्म शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रार्थ, प्रवचन करने की क्षमता, दस वर्ष बाद कुंभ में ली गई हो संन्यास दीक्षा, अखाड़े की उच्चस्तरीय समिति से चयनित होने पर सभी तेरह अखाड़ों के प्रमुख पदाधिकारियों, महामंडलेश्वरों द्वारा आचार्य महामंडलेश्वर की उपस्थिति में महंताई चादर प्रदान की जाती है. सभी तेरह अखाड़ों की सहज स्वीकृति के बाद ही व्यक्ति महामंडलेश्वर पदवी को धारण करने का अधिकारी बनता है. ■

सीबीआई जांच शुरू होने के बावजूद यादव सिंह को बचाने में लगे अखिलेश

खुद फंसने की बौखलाहट में सरकार

दीनबंधु कबीर

आखिर यादव सिंह मामले में सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो ही गई. चार अगस्त को यादव सिंह के दर्जनभर से अधिक ठिकानों पर सीबीआई ने सघन तलाशी का अभियान चलाया और अकूत कमाई के बहुत सारे दस्तावेज हासिल किए. दिल्ली और नोएडा समेत लखनऊ के ठिकानों पर भी छापा मारा गया. यादव सिंह के दामाद आईएएस अधिकारी शशिभूषण लाल के बटलर पैलेस कॉलोनी स्थित आवास पर भी सीबीआई की छापामारी हुई. सीबीआई टीम ने यादव सिंह के दामाद के बटलर पैलेस कॉलोनी स्थित सी-22 आवास से कई दस्तावेज कब्जे में लिए हैं. दिल्ली से आई सीबीआई टीम जब करीब ढाई बजे बटलर पैलेस कॉलोनी पहुंची, तो घर पर यादव सिंह की बेटी गरिमा भूषण मौजूद थी. तलाशी वारंट दिखाने के बावजूद कार्रवाई को लेकर गरिमा और सीबीआई टीम की काफी देर तक कहासुनी होती रही. तलाशी शुरू होने के बाद कॉलोनी पहुंचे मीडिया वालों से भी बहस करने में गरिमा भूषण ने कोई संकोच नहीं किया. सीबीआई ने यादव सिंह की फिरोजाबाद स्थित ससुराल पर भी छापा मारा. हालांकि वहां पर टीम को कुछ खास हासिल नहीं हुआ. फिरोजाबाद के उत्तर क्षेत्र थाने के दुली मुहल्ले में यादव सिंह की ससुराल में कोई नहीं था. यादव सिंह के ससुर रामप्रसाद और साले सुरेश का कुछ पता नहीं चला. घर पर ताला लगा मिला.

इस तरह अरबों के भ्रष्टाचार मामले में फंसे यादव सिंह को बचाने की उत्तर प्रदेश सरकार की सारी कोशिशें नाकाम रहीं. अखिलेश यादव सरकार के तमाम विरोध के बावजूद सीबीआई की जांच शुरू हुई और नोएडा प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कर पड़ताल तेज कर दी गई. सीबीआई ने मंगलवार चार अगस्त को यादव सिंह और उसके परिवार के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा फिरोजाबाद और लखनऊ स्थित 14 ठिकानों पर छापेमारी की और सघन तलाशी अभियान चलाया. लखनऊ में उनके दामाद के घर भी छापा मारा गया. इसके साथ ही सीबीआई टीम ने नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना विकास प्राधिकरण के दफ्तरों पर भी छापे मारे. सीबीआई टीम ने नवम्बर 2014 में यादव सिंह के ग्रेनो प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण के 13 दिन के कार्यकाल के दौरान टेंडरों और निजी कंपनियों को रिलीज किए गए रुपयों वाली फाइलों की भी जांच की और जरूरी दस्तावेज अपने साथ ले गई.

कोर्ट के आदेश पर यादव सिंह के राजनीतिक संपर्क भी सीबीआई की जांच के दायरे में हैं. अपने राजनीतिक संपर्कों की वजह से ही वह बदनाम और कुख्यात होने के बावजूद अहम पदों पर लंबे समय तक बना रहा. उत्तर प्रदेश में मायावती के कार्यकाल में वर्ष 2002 में नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में नियुक्त हुआ यादव सिंह, मुलायम सिंह और अखिलेश सरकार में भी मुख्य भूमिका में रहा. यादव सिंह ने इस दौरान करीब 8,000 करोड़ की योजना पर कुंडली मारते हुए कई बड़े विवादास्पद वित्तीय फैसले लिए. सीबीआई की पहली एफआईआर में यादव सिंह, उसकी पत्नी कुसुम लता, बेटी गरिमा भूषण और बेटे सनी के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप लगाए गए हैं. यादव सिंह भ्रष्टाचार प्रकरण में राजीव मनोचा नाम का एक व्यक्ति भी आरोपी है. यह मामला यादव सिंह परिवार की आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है. दूसरी एफआईआर में बेनामी लोगों के साथ यादव सिंह को धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोपी बनाया गया है.

पिछले साल नवम्बर में आयकर विभाग के छापे में यादव सिंह के ठिकानों से भारी मात्रा में गहने, घोटाले और कर चोरी के दस्तावेज बरामद किए गए थे. छापे में यादव सिंह की कार की डिक्की से ही 10 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे. यादव पर आरोप है कि उसने निजी व्यक्तियों और फर्जी संस्थानों को करोड़ों रुपये के ठेके दे दिए थे. शीर्ष सत्ता तक पहुंच की वजह से यादव सिंह के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, उल्टा यादव सिंह को संरक्षण दिया जा रहा था. इस पर समाजसेविका डॉ. नूतन ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने सीबीआई को यादव के खिलाफ जांच के आदेश दिए. जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका सख्त विरोध किया. सीबीआई द्वारा जांच टेकओवर कर लेने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. प्रदेश सरकार ने हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को झटका देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी. प्रदेश के महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह का कहना है कि इस सिलसिले में एडवोकेट ऑन रेकार्ड को पत्र जा चुका है. सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला है. उधर, यादव सिंह मामले की जांच के लिए गठित एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ए.एन वर्मा भी यह दावा कर रहे हैं कि उनकी जांच जारी है और यह जारी रहेगी.

बहरहाल, चार अगस्त को यादव सिंह के ठिकानों पर जब सीबीआई की छापामारी चल रही थी, तब यादव सिंह की पत्नी कुसुम और बेटा सनी लापता थे. यादव सिंह के सेक्टर 27 स्थित ए-38 मकान में कोई नहीं था. हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को ही सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे, लेकिन सीबीआई ने जांच शुरू करने में 20 दिन लगा दिए. लोग तो यह भी कहते हैं कि इतने दिनों की रियायत में महत्वपूर्ण साक्ष्य व दस्तावेज नष्ट कर दिए गए. हालांकि सीबीआई ने दावा किया है कि छापे में कई अहम दस्तावेज मिले हैं.

यादव सिंह प्रकरण की सीबीआई जांच शुरू होते ही इसमें प्रवर्तन निदेशालय भी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से छानबीन शुरू कर रहा है. काले धन की जांच के लिए बनी एसआईटी ने पिछले साल ही यादव सिंह के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत केस दर्ज करने को कहा था. अब इस बात की भी काफी संभावना है कि सीबीआई यादव सिंह के समधी प्रमेंद्र सिंह पर भी शिकंजा कसेगी. यादव सिंह ने समधी प्रमेंद्र सिंह को ग्रेनो और यमुना अथॉरिटी का ओएसडी प्रॉजेक्ट बनवा दिया था. इसी तरह यादव सिंह ने रिश्तेदार संदीप को यमुना अथॉरिटी में प्रॉपर्टी विभाग में तैनात करा दिया था. घोटालों के आरोप में संदीप को सस्पेंड किया गया लेकिन यादव सिंह की पहुंच के चलते बहाल कर उसे एचआर विभाग से अटैच कर दिया गया. यादव सिंह के तीन करीबी ग्रेनो अथॉरिटी के मैनेजर रमेश चंद्रा, उमेश और मुकेश करोड़ों के घपले में दोषी पाए गए और उन्हें निलंबित किया गया, लेकिन यादव सिंह ने तीनों को बहाल करा दिया. यादव सिंह ने जिन लोगों को बहाल करा लिया और जिन लोगों के बूते बहाल करा लिया, वे सब सीबीआई के लपेटे में आने वाले हैं. ■

सपा-बसपा पर केंद्र का दबाव!

राजनीति की नब्ज पर हाथ रखने वाले लोग सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारियों को केंद्र सरकार की दबाव की सियासत बताने लगे हैं. वे कहते हैं कि यह सब वर्ष 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है. वे मानते हैं कि भाजपा यादव सिंह के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सपा और बसपा को घेरने का प्रयास करेगी. दूसरी तरफ संसद में सरकार कई अहम मुद्दों को लेकर विपक्षियों से घिरी हुई है. अन्य दलों के साथ सपा और बसपा भी केंद्र सरकार का जमकर विरोध कर रही है. 19 दिन से यादव सिंह के खिलाफ कार्रवाई से कतरा रही सीबीआई के अचानक शुरू हुए युद्ध स्तरीय अभियान के पीछे तीन अगस्त को संसद में आए तीव्र गतिरोध का नतीजा बताया जा रहा है. ■

> पिछले साल नवम्बर में आयकर विभाग के छापे में यादव सिंह के ठिकानों से भारी मात्रा में गहने, घोटाले और कर चोरी के दस्तावेज बरामद किए गए थे. छापे में यादव सिंह की कार की डिक्की से ही 10 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे. यादव पर आरोप है कि उसने निजी व्यक्तियों और फर्जी संस्थानों को करोड़ों रुपये के ठेके दे दिए थे. शीर्ष सत्ता तक पहुंच की वजह से यादव सिंह के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, उल्टा यादव सिंह को संरक्षण दिया जा रहा था.

बचाने वालों की खैर नहीं

शीर्ष सत्ता से लेकर नौकरशाही तक में यादव सिंह को बचाने की आपाधापी इसलिए मची है, क्योंकि पूरा मामला खुला तो सफेद वस्त्रधारियों के साथ-साथ खाकी वर्दीधारी तक कठघरे में खड़े हो जाएंगे. जैसे-जैसे सीबीआई की जांच बढ़ेगी यादव सिंह से जुड़े लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जाएंगी. अगर जांच निष्पक्ष तरीके से हुई और इसमें कोई खेल नहीं हुआ, तो इस प्रकरण में नपने वाले सफेदपोशों के चेहरे आपको अभी से साफ-साफ दिखने लगेंगे. उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेताओं और आला अफसरों के साथ सीबीसीआईडी के कई अफसर भी सीबीआई जांच के दायरे में आ रहे हैं. इसकी वजह है यादव सिंह के खिलाफ 954 करोड़ के घोटाले में दर्ज एफआईआर पर शुरू हुई सीबीसीआईडी जांच में आनन-फानन लगी फाइनल रिपोर्ट(एफआर). यादव सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए दूसरे मुकदमे में सीबीआई ने नोएडा में दर्ज हुए मुकदमे और उसकी सीबीसीआईडी जांच पर ध्यान केंद्रित किया है. उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश जारी करते हुए कहा था कि पूरे सिस्टम को अपना गुलाम बनाकर भ्रष्टाचार किया गया है. हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि यादव सिंह को बसपा और सपा दोनों सरकारों में भरपूर संरक्षण मिला. उन्हीं नामों का खुलासा करने के लिए जांच सीबीआई को दी गई है. सपा सरकार के आने से पहले यादव सिंह को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती और उनके भाई आनंद का करीबी माना जाता था. लेकिन सपा सरकार के आने के कुछ समय बाद ही यादव सिंह की सपा के कद्दावर नेताओं तक पहुंच हो गई. इस नजदीकी का ही असर था कि पहले एक हजार करोड़ के घोटाले की जांच सीबीसीआईडी को दी गई, फिर यादव सिंह को बहाली मिल गई, तीनों प्राधिकरणों का चीफ इंजीनियर बना दिया गया और आखिर में सीबीसीआईडी वाले मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट भी लग गई. स्पष्ट है कि यादव सिंह सत्ताशीर्ष से जुड़ा नहीं होता, तो उसे इतनी तरजीह नहीं मिलती. उसे संरक्षण देने वाले भी अब जांच के घेरे में आएंगे, क्योंकि यादव सिंह के खिलाफ दर्ज सीबीआई की दूसरी एफआईआर नोएडा में हुई घोटाले की एफआईआर और उस पर की गई सीबीसीआईडी जांच पर ही केंद्रित है. इसमें सीबीसीआईडी के विवेचक, पर्यवेक्षक और आखिरी मुहर लगाने वाले विभागीय प्रमुख तक जांच के घेरे में आ रहे हैं. 30 जून 2012 को नोएडा विकास प्राधिकरण के प्रभारी सहायक परियोजना अभियंता आरपी सिंह ने सेक्टर 39 थाने में यादव सिंह, इंजीनियर रमेन्द्र सिंह समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. बाद में आरोपित के प्रार्थना पत्र पर मामले की जांच सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दी गई. सीबीसीआईडी के तत्कालीन एडीजी जगमोहन यादव (मौजूदा डीजीपी), आईजी संजय तरडे (वर्तमान में एडीजी सीबीसीआईडी) और एसपी पंकज कुमार के पर्यवेक्षण में मेरठ सेक्टर के एएसपी राजेश सक्सेना ने इस मामले की विवेचना की थी. 31 जनवरी 2014 को उन्होंने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी. मामले की विवेचना करने वाले और पर्यवेक्षक दोनों के लिए ही वह आधार फांस बनेगा जिसके जरिए सीबीसीआईडी ने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाई, क्योंकि विभागीय जांच के बाद काफी विस्तृत आरोपों के साथ जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, सीबीसीआईडी ने उसे एक झटके में पूरी तरह से खारिज कर दिया. प्रभाव, दबाव और डर का आलम यह हुआ कि एफआईआर दर्ज कराने वाले आरपी सिंह ने भी कोर्ट में सीबीसीआईडी की फाइनल रिपोर्ट का विरोध नहीं किया. ■

पुलिस को मोहरा बनाने की कोशिश

सीबीआई की जांच, ताबड़तोड़ छापेमारियों और फंसने की आशंकाओं से अखिलेश सरकार बौखला गई है. इस बौखलाहट में सरकार ने ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जो बरबस ही लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. जब सीबीआई ने औपचारिक तौर पर मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी तब नोएडा के सेक्टर 20 थाने में यादव सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने का क्या औचित्य है? सरकार की बौखलाहट में उत्तर प्रदेश पुलिस मोहरा बन रही है. सरकार इस प्रकरण में कई तरह के फच्चर फंसा कर सुप्रीमकोर्ट से स्टे हासिल करना चाहती है. तभी न्यायिक आयोग भी जांच कर रहा है और अब नए दर्ज मुकदमे की भी जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल गठित कर दिया है. आईपीएस स्तर के अधिकारी इसकी अलग से जांच करेंगे. उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. सरकार पर साफ-साफ आरोप लग रहा है कि यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत दिलाने के लिए इस तरह की बौखलाहट भरी कोशिशें की जा रही हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com